रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 1994/माघ 30, 1915
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1994/MAGHA 30, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994

का.आ. 472.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सुश्री रेखा मेहरोत्रा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(6)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

New Delhi, the 7th January, 1994

S.O. 472.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Miss Rekha Mehrotra, Advocate for appointment as a Notary to practise in UNNAO (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5. (6)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994

का.आ. 473.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री इन्द्र मोहन मल्होत्रा, एडवोकेट, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(7)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 7th January, 1994

S.O. 473.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Inder Mohan Malhotra, Advocate for appointment as a Notary to practise in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5. (7)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994

का.आ. 474.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रणधीर ठाकुर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे होशियारपुर (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(5)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 7th January, 1994

S.O. 474.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Randhir Thakur, Advocate for appointment as a Notary to practise in Hoshiarpur (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5. (5)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994

का.आ. 475.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हर स्वरूप ठाकुर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे लक्ष्मी नगर (दिल्ली) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(4)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 7th January, 1994

S.O 475.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Har Swaroop Thakur, Advocate for appointment as a Notary to practise in Laxmi Nagar Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5. (4)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority.

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994

का.आ. 476.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रदीप कुमार तालुकदार, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे तूफानगंज, सब डिवीजन, जिला कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(8)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 7th January, 1994

S.O 476.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Pradip Kumar Talukdar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Tufanganj Sub-Division Distt. Cooch Behar (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5. (8)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1994

का.आ. 477.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रमेश एम. अग्रवाल, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे बम्बई

(महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(13)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 20th January, 1994

S.O. 477.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Ramesh M. Agarwal Advocate for appointment as a Notary to practise in Bombay, (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5. (13)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1994

का.आ. 478.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुरेश चन्द भारद्वाज एडवोकेट, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे बुलन्द शहर (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(14)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 20th January, 1994

S.O. 478.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Suresh Chandra Bhardwaj, Advocate for appointment as a Notary to practise in Bulandshahar (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5. (14)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

का.आ. 479.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री विजय पाल सिंह यादव, एडवोकेट के उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे टीब्बी, श्री गंगानगर, (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(16)/94-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 25th January, 1994

S.O. 479.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Vijay Pal Singh Yadav, Advocate for appointment as a Notary to practise in TI-BI, Sriganganagar (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5. (16)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1994

का.आ. 480.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा गृह मंत्रालय, न्याय विभाग तथा पुनर्वास प्रभाग में संयुक्त सचिव श्री एम.पी. सिंह को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन महाभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से निष्क्रान्त सम्पत्ति का महाभिरक्षक नियुक्त करती है।

2. इसके द्वारा दिनांक 17-9-1992 की अधिसूचना संख्या 1(3)/विशेष कक्ष/90-एसएस II/एस(ख) का अधिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(1)/विशेष कक्ष/94-बन्दोबस्त(ख))]

मु० असलम, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 18th January, 1994

S.O. 480.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri M. P. Singh, Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, Department of Justice and Rehabilitation Division as the Custodian General of Evacuee Property for the purpose of performing functions assigned to such Custodian General by or under the said Act.

2. This superseeds notification No. 1(3)/Spl. Cell/90-SS.II/S(B) dated the 17-9-1992.

[No. 1(1)/Spl.Cell/94-Settlement (B)]

M. ASLAM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1994

का.आ. 481.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा गृह मंत्रालय, न्याय विभाग तथा पुनर्वास प्रभाग में संयुक्त सचिव श्री एम.पी. सिंह को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से मुख्य बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

2. इसके द्वारा दिनांक 17-9-1992 की अधिसूचना संख्या 1(3)/विशेष कक्ष/90-एसएस/बन्दोबस्त (क) का अधिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(1)/94-विशेष कक्ष/बन्दोबस्त (क)]

मु० अस्लम, उप सचिव

New Delhi, the 18th January, 1994

S.O. 481.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri M. P. Singh, Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, Department of Justice and Rehabilitation Division as Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Chief Settlement Commissioner by or under the said Act.

2. This supersedes notification No. 1(3)/Spl.Cell/90-SS.II/Settlement (A) dated the 17-9-1992.

[No. 1(1)/94-Settlement(A)]

M. ASLAM, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का०आ० 482—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, जो होम (एस०सी०—ए)/विभाग जी०ओ०आर०टी० सं० 2671 तारीख 4-10-1993 द्वारा दी गई थी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रीकृत आर०सी० 23(एस०)/91—हैदराबाद तारीख 31-8-1991 में नीचे यथा उपदर्शित अपराधों का तथा उन्ही तथ्यों से उद्भूत उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए उक्त अपराधों और किसी अन्य अपराध या अपराधों, जो सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय हैं, के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के जो निम्नलिखित प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए गए अभिकथित हैं अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है :

आर०सं० संख्या और विधि की धाराएं	अभियुक्त के नाम
भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 408, 468, के साथ पठित धारा 120 ख के अधीन आर०सी० सं. 23 (एस०)/91—हैदराबाद तारीख 31-8-1991 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 408, 468 और 477 के अधीन अधिष्ठायी अपराध।	1. श्री पी० एम० स्वामी, पुत्र पी० सूर्याराव श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति। 2. श्री के० जनकिरन, पुत्र लक्ष्मन चेट्टी मुथू मिस्त्री देवराज स्ट्रीट चित्तूर और अन्य।

[संख्या] 228/86/93—ए०वी०डी० (II)]

आर०एस० बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

ORDER

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 482.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Andhra Pradesh vide Home (SC-A)/Department G.O. Rt. No. 2671 dated 4-10-1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of the offences in RC. 23(S)/91-Hyderabad, dated 31-8-1991 registered by CBI and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with said offences and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts, and punishable under the provisions of relevant Act as indicated below alleged to have been committed by the following private persons :—

RC. No. and Sections of Law	Name of accused
RC. 23(S)/91-Hyderabad, dated 31-8-1991, under Section 120-B read with 420, 408, 462, Indian Penal Code and substantive offences under Sections, 420, 408, 468 and 477 of Indian Penal Code.	1. Sh. P.M. Swamy S/o P. Surya Rao Sri Venkateswara University Tirupati. 2. Sh. K. Janakiran S/o Laxman Chetty Muthu Mestri Devaraj Street Chittoor and others.

[No. 228/86/93-AVD-II]

R.S. BISHT, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1993

(आयकर)

का.आ. 483.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23—ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "कलकत्ता जोरोस्ट्रियन कम्यूनिटीज रिलीजियस चेरिटी फण्ड कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यो के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(ii) कर-निर्धारती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नही कर सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नही होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं० 9437/फा०सं० 197/148/93—आयकर (नि०—I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th December, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 483.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Calcutta Zoroastrian Community's Religious Charity Funds, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, Furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9437/F. No. 197/148/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1993

(आयकर)

का०आ० 484.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23—ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "जेसूटस आफ सन्ताल सोसाइटी, दुमका, बिहार" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं० 9438/फा०सं० 197/132/93—आयकर (नि०—I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 28th December, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 484.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jesuits of Santal Society, Dumka, Bihar" for the purpose of the said sub-clause for the assessment year 1989-90.

[Notification No. 9438/(F. No. 197/132/93-ITA-I)]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर 1993

(आयकर)

का०आ० सं० 485.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23—ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "जेसूटस आफ सन्ताल सोसाइटी, दुमका बिहार" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नही करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं० 9439 (फा०सं० 197/132/93—आयकर (नि०—I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 28th December, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 485.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby noti-

fies "Jesuits of Santal Society, Dumka, Bihar" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9439/F. No. 197/132/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

आयकर

का०आ० 486.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री अरविन्दो सोसाइटी, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर, जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छित अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं० 9445/फा०सं० 197/100/92-आयकर नि०-I]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 31st December, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 486.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Sri Turobindo Society, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9445/F. No. 197/100/92-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1994

का०आ० 487.—रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री गोविंद जी० मिश्रा, आई०ए०एस० (राजस्थान 58) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा 31 अगस्त, 1995 तक, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 7/1/94-बी०ओ०I]

एम.एस० सीतारामन, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 2nd February, 1994

S.O. 487.—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with sub-section (2) of section 6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, the Central Government hereby appoints Shri Govind Jee Misra, IAS (RJ : 58) as a Member of the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction for the period from the date of his taking charge and upto 31st August, 1995.

[No. 7/1/94—BO.I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का०आ० 488.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 369 तारीख 16 जनवरी, 1992 को 12 नवम्बर, 1993 से विखंडन करती है।

[फाईल सं० 5(18)/93-ईआईएण्डईपी)]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना वाणिज्य मंत्रालय के सं०का०आ० 369 तारीख 16 जनवरी, 1992 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 488.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, w.e.f. 12th November, 1993 rescinds the Notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce, No. S.O. 369 dated the 16th January, 1992.

[File No. 5(18)/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

Footnote : The principal notification was published vide Ministry of Commerce, No. S.O. 369 dated 16th January, 1992.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का०आ० 489.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्बनिक रसायनों का बम्बई में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मेकर भवन, नं० 1, सर विट्ठलदास ठाकरसे मार्ग, बम्बई-400020 पर स्थित मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० को निम्न शर्तों के अधीन 12 नवम्बर, 1992 से तीन और वर्षों की अवधि के लिए एतद्द्वारा अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :—

(i) मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि कार्बनिक रसायन के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण का प्रमाण पत्र दिया जा सके।

(ii) मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा कि निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में दें।

अनुसूची

1. एसिटिक एसिड
2. हाइड्रोक्वीनान
3. आक्जेलिक एसिड
4. बेनजीन
5. एथिल अल्कोहल
6. जाईलीन
7. सोडियम साईट्रेट

[फाईल सं० 5(18)/93—ईआईएण्डईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 489.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years from 12th November 1993, M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., located at Maker Bhavan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Bombay-400020, as an agency for the inspection of Organic Chemicals specified in schedule annexed hereto, prior to export at Bombay, subject to the following conditions, namely :—

(i) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of Inspection under rule 4 of the Export of Organic Chemicals (Inspection) Rule, 1966;

(ii) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

SCHEDULE

1. Acetic Acid
2. Hydroquinone
3. Oxalic Acid
4. Benzene
5. Ethyl Alcohol
6. Xylene
7. Sodium Citrate

[File No. 5(18)/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का० आ० 490:—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अकार्बनिक रसायनों का बम्बई में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मेकर भवन, नं० 1, सर विट्ठलदास ठाकरसे मार्ग बम्बई-400020 पर स्थित मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० को निम्न शर्तों के अधीन 12 नवम्बर, 1992 से तीन और वर्षों की अवधि के लिए एतद्द्वारा अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् —

(i) मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि अकार्बनिक रसायन के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण का प्रमाण पत्र दिया जा सके।

(ii) मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा जो कि निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में दे।

अनुसूची

1. पोडियम डाइक्रोमेट
2. पोडियम सल्फेट
3. मैगनीज डायक्साइड (प्राकृतिक से अलग)
4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड
5. कोपर सल्फेट
6. पोडियम कार्बोनेट
7. फैरिक एल्यूम
8. एल्यूमिनियम सल्फेट (नोन फैरिक)
9. अमोनियम क्लोराईड
10. पोटेशियम डाइक्रोमेट
11. मैगनीजसल्फेट
12. सोडियम बाईकार्बोनेट
13. एल्यूमिनों फैरिक
14. एल्यूमिनियम क्लोराइड
15. बैरियम क्लोराइड
16. कैल्शियम कार्बोनेट
17. पोटाशियम परमैगनेट
18. जिंक सल्फेट
19. अमोनियम एल्यूम
20. पोटाश एल्यूम
21. एल्यूमिनियम आक्साइड
22. ब्लीचिंग पाउडर
23. बोरेक्स
24. कास्टिक सोडा

25. कास्टिक पोटाश
26. पोटाशियम कार्बोनेट
27. पोटाशियम क्लोरेट
28. सोडियम सिलिकेट
29. सोडियम हाइड्रो सल्फेट

[फाईल सं० 5(18)/93-ईआईएण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 490.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years from 12th November 1993, M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., located at Maker Bhavan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Bombay-400 020, as an agency for the inspection of Inorganic Chemicals specified in schedule annexed hereto, prior to export at Bombay, subject to the following conditions, namely :—

(i) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Rules, 1966;

(ii) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection and Quality Control) may give in writing from time to time.

SCHEDULE

1. Sodium Dichromate
2. Sodium Sulphate
3. Manganese Dioxide (other than natural)
4. Hydrochloric Acid
5. Copper Sulphate
6. Sodium Carbonate
7. Ferric Alum
8. Aluminium Sulphate (non-ferric)
9. Ammonium Chloride
10. Postassium Dichromate
11. Manganese Sulphate
12. Sodium Bicarbonate
13. Alumino Ferric
14. Aluminium Chloride
15. Barium Chloride
16. Calcium Carbonate
17. Potassium Permanganate
18. Zinc Sulphate
19. Ammonium Alum
20. Potash Alum
21. Aluminium Oxide
22. Bleaching Powder
23. Borax
24. Caustic Soda
25. Caustic Potash
26. Potassium Carbonate
27. Potassium Chlorate
28. Sodium Silicate
29. Sodium Hydro Sulphate

[File No. 5(18)/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का०आ० 491.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3978 तारीख 20-12-1965 के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कच्चा क्रोम तथा क्रोमासान्द्र के अलावा खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-II) का निर्यात से पूर्व बम्बई में निरीक्षण करने के लिए मेकर भवन, नं० 1, सर विट्ठलदास ठाकरसे मार्ग, बम्बई-400020 पर स्थित मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० को तीन और वर्षों की अवधि के लिए 12 नवम्बर, 1993 से निम्न शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :—

(i) मैसर्स जे० बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा० लि० निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को इसके द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क ग्रुप-II के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण का प्रमाण-पत्र दिया जा सके।

(ii) मैसर्स जे० बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में दें।

[फाइल सं० 5(18)/93-ईआईएण्डईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 491.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years from 12th November, 1993, M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., located at Maker Bhavan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Bombay-400020. as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-II) specified in schedule annexed to Ministry of Commerce notification No. S. 3978 dated 20-12-1965 except for Chrome Ore and Chrome Concentrates, prior to export at Bombay, subject to the following conditions, namely:—

(i) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group II (Inspection) Rules, 1965;

(ii) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5(18)/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का०आ० 492.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3975 तारीख 20-12-1965 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) का निर्यात से पूर्व बम्बई में निरीक्षण करने के लिए मेकर भवन, नं०-1 सर विट्ठलदास ठाकरसे मार्ग बम्बई-400020 पर स्थित

मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० को 12 नवम्बर 1993 से 31 जनवरी, 1995 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :—

(i) मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को इसके द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क ग्रुप—1 के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण का प्रमाण पत्र दिया जा सके।

(ii) मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा०लि० इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में दे।

[फाईल सं० 5(18)/93—ईआई एण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 492.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period ending 31st January, 1995 from 14th November, 1993, M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., located at Maker Bhavan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Bombay-400 020, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group I) specified in Schedule annexed to Ministry of Commerce Notification No. S O 3975 dated 20-12-1965, prior to export at Bombay subject to the following conditions, namely :—

(i) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group I (Inspection) Rules, 1965;

(ii) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection and Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5(18)/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का०आ० 493.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खनिज तथा अयस्क ग्रुप-1 अर्थात् मैंगनीज डायक्साइड रहित कच्चा लोहा तथा मैंगनीज कच्चा का निर्यात से पूर्व विशाखापत्तनम में निरीक्षण करने के लिए 23—23—12/1 बीच रोड विशाखापत्तनम-530001 पर स्थित मैसर्स फैराडो लेबोरेट्रीज को और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 25-6-4 गंजम स्ट्रीट, काकीनाडा-533001 पर है इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्-द्वारा अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :—

(i) मैसर्स फैराडो लेबोरेट्रीज इस संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा नामित अधिकारी को उनके द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क ग्रुप—I के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दिया जा सके।

(ii) मैसर्स फैराडो लेबोरेट्रीज इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगी जिन्हें निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में दे।

[फाईल सं० 5/2/94—ईआईएण्डईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 493.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification, M/s. Ferrado Laboratories, located at 23-23-12/1, Beach Road, Vishakapatnam-530001 and having their registered office at 25-6-4, Ganjam Street, Kakinada-533001, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) namely Iron Ore and Manganese Ore excluding Manganese Dioxide, prior to export at Vishakapatnam subject to the following conditions, namely :

(i) that M/s. Ferrado Laboratories, shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group I (Inspection) Rules, 1965;

(ii) that M/s. Ferrado Laboratories in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection and Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5/2/94-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का०आ० 494.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3975 तारीख 20-12-1965 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) का विशाखापत्तनम में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए 24—3—6 मैन रोड (पहली मंजिल), विशाखापत्तनम—530001 पर स्थित मैसर्स इटालेब प्रा०लि० को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा मान्यता देती है, अर्थात् :—

(i) मैसर्स इटालेब प्रा०लि० निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गई निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र दिया जा सके।

(ii) मैसर्स इटालेब प्रा०लि०, इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देगा।

[फाइल सं० 5/10/93—ई.आई.एण्ड.ई.सी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 494.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification, M/s. Italab Pvt. Ltd., located at 24-3-6, Main Road (1st Floor), Visakhapatnam-530 001, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) specified in Schedule annexed to Ministry of Commerce Notification No. S.O. 3975 dated 20-12-1965 prior to export at Visakhapatnam, subject to the following conditions, namely :—

(i) that M/s. Italab Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group I (Inspection) Rules, 1965;

(ii) that M/s. Italab Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection and Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5/10/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का.आ. 495.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3978 तारीख 20-12-1965 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-II) का विशाखापत्तनम में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए 24-3-6 मेन रोड (पहली मंजिल), विशाखापत्तनम-530001 पर स्थित मैसर्स इटालेब प्रा. लिमिटेड को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा मान्यता देती है अर्थात् :—

(i) मैसर्स इटालेब प्रा. लिमिटेड, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गई निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-II) के निर्यात (निरीक्षण) नियम 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाण-पत्र दिया जा सके ।

(ii) मैसर्स इटालेब प्रा. लिमिटेड इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देगा ।

[फाइल सं. 5/10/93-ई.आई.एंड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा निदेशक

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 495.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification, M/s. Italab Pvt. Ltd., located at 24-3-6, Main Road (1st Floor) Visakhapatnam-530 001, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-II) specified in Schedule annexed to Ministry of Commerce Notification no. 3978 dated 20-12-1965 prior to export at Visakhapatnam, subject to the following conditions, namely :—

(i) that M/s. Italab Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of Export of Minerals and Ores (Group-II) (Inspection) Rules, 1965;

(ii) that M/s. Italab Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection and Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5/10/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

विदेश व्यापार महानिदेशालय

(डी.ई.एस-3 (इंजी.) अनुभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

का.आ. 496.—मै. शर्के कान्स्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट्स प्रा.लि. 72-76 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मन्धवा, पुणे-411036 को 2,85,96,000 रुपये (9,04,937.00 अमरीकी डालर) के निर्यात आधार के साथ 1,93,86,100 रुपये (6103.00 अमरीकी डालर) के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए एक अग्रिम लाइसेंस सं. पी/एल/1525379 दिनांक 18-6-1993 मंजूर किया गया था जिसकी वैधता अवधि लाइसेंस जारी करने की तारीख से 12 महीने थी । अब फर्म ने केवल आयात के लिए उक्त अग्रिम लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) तथा डी.ई.ई.सी. बुक (आयात) के भाग-I की दूसरी प्रति इस आधार पर प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि उक्त अग्रिम लाइसेंस सं. पी/एल/1525379 दिनांक 18-6-1993 (केवल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) और डी.ई.ई.सी. बुक (आयात) सं. 078364 दिनांक 18-6-1993 का भाग-I खो गया है/गुम हो गया है । फर्म ने आवश्यक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार पूर्वोक्त अग्रिम लाइसेंस तथा डी.ई.ई.सी. बुक (आयात) का भाग-I सीमाशुल्क (कस्टम हाउस) बम्बई से पञ्जीकृत कराया गया था तथा उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ था तथा लाइसेंस के मद्दे शेष लागत बीमा भाड़ा मूल्य 1,93,86,100 रुपये है । हलफनामे में इस आशय की एक घोषणा भी अन्तर्विष्ट की गई है कि यदि उक्त लाइसेंस बाद में मिल जाता है या पाया जाता है तो उसे निर्गम प्राधिकारी को लौटा दिया जाएगा ।

2. इस तथ्य से सन्तुष्ट होने पर कि केवल आयातों के लिए उक्त मूल अग्रिम लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) तथा डी.ई.ई.सी. बुक (आयात) का भाग-I खो गया है, अधोहस्ताक्षरी का यह निदेश है कि आवेदक को केवल आयातों के लिए दूसरा अग्रिम लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) तथा डी.ई.ई.सी. बुक (आयात) का भाग एक जारी कर दिया जाए साथ ही विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के खण्ड-9 के उपखण्ड (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त मूल अग्रिम लाइसेंस (केवल आयातों के लिए सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति तथा डी.ई.ई.सी. बुक भाग-1) को निरस्त करता हूं ।

[फा.सं. 1/81/40/387/एम-94/डी.ई.एस/3/3036]

आर.के. भूड, उप महानिदेशक विदेश व्यापार

कृते महानिदेशक विदेश व्यापार

Directorate General of Foreign Trade

(Des-III (Engg.) Section)

New Delhi, the 27th January, 1994

S.O. 496.—M/s. Shirke Construction Equipments Pvt., Ltd., 72-76, Industrial Estate, Mundhwa, Pune-411036 were grant-

ed an Advance Licence No. P|L|1525379 dated 18-6-1993 for a cif value of Rs. 1,92,86,100 (US doller 6,10,348.00) with an export obligation of Rs. 2,85,96,000) (US doller 9,04,937.00) with a validity of 12 months from the date of issue of the licence. Now the firm have applied for grant of duplicate copy of said Advance Licence (Customs purpose copy) and Part I of DEEC Book (Import) for the import only on the ground that the said Advance Licence No. P|L|1525379 dated 18-6-1993 (Customs purpose copy only) and Part I of DEEC Book (Import) No. 078354 dated 18-6-1993 have been lost|misplaced. The firm have furnished necessary affidavit according to which the aforesaid Advance Licence and Part I of DEEC Book (Import) were registered with the Customs (Customs House), Bombay and was not utilised at all and the balance CIF value against the licence is Rs. 1,92,86,100. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said licence is traced or found later on, it will be returned to the Issuing Authority.

2. On being satisfied that the said Original Advance Licence (Customs purpose copy) and Part I of DEEC Book (Import) for imports only have been lost, the undersigned directs that duplicate Advance Licence (Customs Purpose copy) and Part I of DEEC Book for import only should be issued to the applicant. I also, in exercise of the powers conferred in sub-clause (4) of Clause 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, hereby cancel the said Original Advance Licence (Customs purpose copy) and DEEC Book (Part I) for imports only.

[No. 01|81|40|387|AM-94|DES-III|3036]

R. K. SOOD, Dy. Director General of Foreign Trade

For Director General of Foreign Trade

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1994

का.आ. 497 :—मैसर्स टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. बम्बई को लाइसेंस जारी करने की तारीख से 12 महीने की वैध अवधि सहित 5,21,36,674/-रुपये (18,29,357 अमरीकी डालर) के निर्यात आभार सहित 2,51,48,184/रुपये के लागत बीमा भाड़ा मूल्य (8,82,417 अमरीकी डालर) के लिए एक अग्रिम लाइसेंस सं. 1514186 दिनांक 21-9-92 और डी ई ई सी बुक सं. 021111 दि. 21-9-92 (भाग-1 और 2) दी गई थी। अब फर्म ने अग्रिम लाइसेंस (केवल विनिमय नियंत्रण प्रति) की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि उक्त लाइसेंस उनसे खो/गुम गया है। फर्म ने आवश्यक शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उक्त अग्रिम लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास दर्ज नहीं कराया गया था और अतः इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और लाइसेंस के लिए लागत बीमा भाड़ा मूल्य की शेष राशि 2,51,48,184/-रुपये पड़ी रही। शपथपत्र में इस आशय की घोषणा भी सम्मिलित है कि यदि उक्त लाइसेंस का पता चलता है या बाद में मिल जाता है तो यह जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा दिया जाएगा।

2. इस बात से संतुष्ट होने पर कि मूल अग्रिम लाइसेंस (केवल विनिमय नियंत्रण प्रति) खो गई है, अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देता हूं कि आवेदक को अग्रिम लाइसेंस की अनुलिपि (केवल विनिमय नियंत्रण प्रति) जारी की जाए। मैं विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल अग्रिम लाइसेंस को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[एफ सं. 01/81/40/739/ए एम-94/डी ई एस-3/3105]

आर. के. सूद, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

कृते महानिदेशक, विदेश व्यापार

New Delhi, the 2nd February, 1994

S.O. 497.—M/s. Technocraft Industries (India) Ltd., Bombay were granted an Advance Licence No. 1514186 dt. 21-9-92 and DEEC Book No. 021111 dt. 21-9-92 (Part I & II) for a cif value of Rs. 2,51,48,184 (US doller 8,82,417) with an export obligation of Rs. 5,21,36,674 (US doller 18,29,357) with a validity of 12 months from the date of issue of the licence. Now the firm have applied for grant of duplicate of Advance Licence (Exchange Control copy only) on the ground that the said licence have been lost|misplaced. The firm have furnished a necessary affidavit according to which the aforesaid Advance Licence was not registered with any Customs Authority and was not utilised at all and the balance cif value against the licence was Rs. 2,51,48,184. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said licence is traced or found later on, it will be returned to the Issuing Authority.

2. On being satisfied that the original Advance Licence (Exchange Control copy only) has been lost, the undersigned direct that duplicate Advance Licence (Exchange Control copy only) should be issued to the applicant. I also, in exercise of the powers conferred in Sub-clause (4) of Clause 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, hereby cancel the original Advance Licence.

[No. 01|81|40|739|AM-94|DES-III|3105]

R. K. SOOD, Dy. Director General of Foreign Trade

For Directir General of Foreign Trade

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1994

का.आ. 498.—मै. एस.एस. सिंथेटिक्स लि., बम्बई को जापान से 6 नग एयर जेट लूम्स, उनके पुर्जे सहित तथा अल्ट्रासोनिक स्लिटिंग मशीनें आयात करने के लिए 71,54,621/-रु. (इकहत्तर लाख, चौवन हजार छः सौ इक्कीस रु. केवल) का आयात लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2127258 दिनांक 25-3-91 मंजूर किया गया था।

2. फर्म ने उक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि इस आधार पर जारी करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है या गुम हो गई है। यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति कस्टम हाउस बैल्लार्डपियर, बम्बई से पंजीकृत करायी गयी थी और इसकी 60,74,53 रु० की राशि प्रयोग में लायी जा चुकी है लेकिन इसकी शेष राशि 10,80,098/ रु. का उपयोग नहीं हुआ है।

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, बम्बई के समक्ष विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2127258 दिनांक 25-3-91 की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति/विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति फर्म से खो गई है या गुम हो गई है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उपखण्ड 9(ग) (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एस.एस सिंथेटिक लि., बम्बई को जारी की गई उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति/. विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति सं. पी/सीजी/2127258, दिनांक 25-3-91 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

4. पार्टी को उक्त लाइसेंस की दूसरी सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति/विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[फाइल सं. 18/एएम 90/136/ईपीसीजी-3]

माया डी. केम, उप-महानिदेशक, विदेश व्यापार

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 1994

S.O. 498.—M/s. L. S. Synthetic Ltd., Bombay were granted an import licence No. P/CG/2127258 dated 25th March, 1991 Rs. 71,54,621 (Rupees Seventyone lakhs Fiftyfour thousand six hundred and Twenty one only) for import of Six Numbers of Air Jet Looms with its spares and ultrasonic slitting machines from Japan.

2. The firm has applied for issue of duplicate copy of Customs and Exchange Control Purpose of the above mentioned licence on the ground that the original Custom Purposes and Exchange Control purpose copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the licence was registered with Customs House, Ballardpier, Bombay and has been utilised for a some of Rs. 60,74,523 leaving an unutilised balance of Rs. 10,80,098.

3. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before Notary Public, Bombay. I am accordingly satisfied that the Custom Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of import licence No. P/CG/2127258 dated 25-3-91 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose copy No. P/CG/2127258 dated 25-3-91 issued to M/s. L. S. Synthetics Ltd., Bombay are hereby cancelled.

4. The duplicate Custom Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 18/AM-90/186/EPCG-III/1579]

MAYA D. KAM, Dy. Director General of Foreign Trade

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1994

का.आ. 499:—मैसर्स सी व्यू ग्रेनाइट्स प्राइवेट लि., बंगलौर को 1. ग्रेनाइट ब्राण्ड फ्रुगोनी ब्लेड फोल्डर 3000×2000 मि.मी. टाइप आटोमेटिक केलिए गैंगसा मशीन-एक नग 2. मार्बल/ग्रेनाइट ब्राण्ड साइडरल माडल आई डी आर ए 71 सं. 3 सहित एब्रेसिव हैड्स—एक नग का आयात करने के लिए रु. 19,82,918 (उन्नीस लाख ब्यासी हजार नौ सौ अठारह रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2134953 दिनांक 21-1-94 को मंजूर किया गया था ।

2. फर्म ने उपरोक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की दूसरी प्रति इस आधार पर जारी करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है/या गुम हो गई है और यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी कस्टम हाउस से पंजीकृत नहीं था तथा इसकी शून्य राशि का उपयोग किया है जिससे कि शेष 19,82,918/-रु. अप्रयुक्त रह गया है ।

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, नई दिल्ली के समक्ष स्टाम्प पेपर पर विधिवत् शपथ लेकर एक हलफनामा दाखिल किया है । तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2134953 दिनांक 21-1-94 की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति फर्म से खो गई है या गुम हो गई है अथवा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उपखण्ड 9(गग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मे. सी व्यू ग्रेनाइट्स प्रा.लि., बंगलौर को जारी की गई । उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सं. पी/सी जी/2134953 दिनांक 21-1-94 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

4. पार्टी को उक्त लाइसेंस की दूसरी सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[फा सं. 18/1178/ए एम 94/ईपीसीजी-3/1578]

माया डी. कैम, उपमहानिदेशक, विदेश व्यापार

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 1994

S.O. 499.—Sea View Granites Pvt. Ltd., Bangalore were granted an Import Licence No. P/CG/2134953 dated 21-1-94 Rs. 19,82,918 (Rupees Ninteen Lakhs Eighty Two Thousand Nine Hundred and Eighteen only) for import of 1. Gangsaw Machine for Granite Brand Frugoni Blade Folder 3000x 2000MM type automatic-One number, 2. Polishing machine for marble/granite brand sideral model-IDRA 71 with No. 3-Abrasive Heads-One number.

2. The firm has applied for issue of duplicate copy of Custom Purpose Copy of the above mentioned licence on the ground that the original custom purposes of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the custom purpose copy of the licence was not registered with any Customs House and has been utilised for a sum of Rs. Nil leaving an unutilised balance of Rs. 19,82,918.

3. In support of their contention, the licensee has filed an Affidavit on stamped paper duly sworn in before Notary Public, New Delhi. I am accordingly satisfied that the custom purpose copy of import licence No. P/CG/2134953 dated 21-1-94 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said Original Customs Purpose copy No. P/CG/2134953 dated 21-1-94 issued to M/s. Sea View Granites Pvt. Ltd., Bangalore is hereby cancelled.

4. The duplicate Custom Purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 18/178/AM-94/EPCG-III/1578]

MAYA D. KAM, Dy. Director General of Foreign Trade

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1994

का.आ. 500 :—मैसर्स घाटगे पाटिल इंडस्ट्रीज लि., कोल्हापुर को ई पी सी जी स्कीम के अन्तर्गत स्ट्रेन्डर्ड एक्सेसरीज सहित तीन पम्प और एक सैंड सीलिंग सिस्टम सहित पेप सेट बान्डेड सैंड के लिए दो टन प्रति घन्टे की सामान्य क्षमता के एक नं. टी. 36/2 सिंगल आर्म कांटीनुअस मिक्सर के आयात के लिए 6,39,352/-रुपये (छः लाख उन्तालीस हजार तीन सौ बावन रुपये मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं.पी./सी जी/2131111 दिनांक 28-9-93 दिया गया था ।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि यह उनसे खो गई अथवा गुम गई है । आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास दर्ज नहीं कराई गई थी । अतः सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, बम्बई के समक्ष विधिवत शपथ लेकर रसीदी कागज पर एक शपथपत्र दाखिल किया है । तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2131111 दिनांक 28-9-93 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति फर्म से कहीं खो गई अथवा गुम हो गई है । अतः यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उप धारा 9(गग) दिनांक 7-12-1955 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स घाटगे पाटिल इंडस्ट्रीज लि. को जारी की

गई मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सं. पी/सी जी/2131111 दिनांक 28-9-93 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[एफ. सं. 18/ए एम 94/648/ई पी सी जी-2/1049]

एम. डी. केम, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 1994

S.O. 500.—M/s. Ghatge Patil Industries Ltd., Kolhapur were granted an Import Licence No. P/CG/2131111, dated 28-9-93 for Rs. 6,39,352 (Rupees Six lakhs thirty nine thousand three hundred and fifty two only) for import of One No. T36/2 single arm Continuous mixer normal capacity two tonnes per hour for pepset bonded sand with three pumps and one sand feeding system with standard accessories under EPCG Scheme.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Custom Purpose copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that Customs purpose copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Customs Purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary public, Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs Purpose copy of Import Licence No. P/CG/2131111 dt. 28-9-93 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Custom Purpose copy No. P/CG/2131111 dated 28-9-93 issued to M/s. Ghatge Patil Industries Ltd. is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purpose copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 18/AM/94/648/EPCG-II/1049]

M. D. KEM, Dy. Chief Controller
of Imports and Exports

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1994

का.आ. 501.—मै. सौराष्ट्र सीमेन्ट एंड कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि., रनावाव, गुजरात, पिन कोड–360560 को 20253232 रुपये (653330 अमरीकी डालर) के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए 13066.6 मी. टन कोयले का आयात करने के लिए एक मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस सं. पी/एल/1524408 दिनांक 23-11-93 जारी किया गया था जिसका निर्यात आधार (क) क्लिंकर (पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेन्ट को छोड़कर)—40333.00 मी. टन–पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1330989/– अमरीकी डालर, और (ख) साधारण पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट (पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेन्ट को छोड़कर) 25000.00 मी. टन–236% के मूल्य संयोजन के साथ 68071719/ (2197989/–अमरीकी डालर) के कुल पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 867000/–अमरीकी डालर हो। यह लाइसेंस शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र (डी ई ई सी) क्रम सं. 091483 (भाग–1 आयात) और 091483 (भाग-2 निर्यात) के साथ जारी किया गया था।

2. अब फर्म ने डी ई ई सी बुक (भाग-1 और भाग–2 दोनों) के साथ दूसरा अग्रिम लाइसेंस इस आधार पर जारी करने के लिए आवेदन किया है कि इस कार्यालय द्वारा भेजा गया मूल अग्रिम लाइसेंस डी ई ई सी बुक के साथ आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है।

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि डी ई ई सी बुक सं. 091483 (आयात और निर्यात दोनों) के साथ मूल अग्रिम लाइसेंस संख्या पी/एल/1524408 दिनांक 23-11-93 फर्म को नहीं मिला है। विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(4) तथा विदेश व्यापार विनियमन नियमावली, 1993 के नियम 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सौराष्ट्र सीमेन्ट एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि. रनावाव, गुजरात - 360560 के पक्ष में जारी किया गया उक्त मूल अग्रिम लाइसेंस संख्या पी/एल/1524408 दिनांक 23-11-93 तथा डी ई ई सी बुक संख्या 091483 (भाग–1 आयात) तथा 091483 (भाग–2 निर्यात) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

4. पार्टी को डी ई ई सी बुक (आयात और निर्यात दोनों) के साथ एक दूसरा अग्रिम लाइसेंस अलग से जारी किया जा रहा है।

[फा. सं. 01/84/40/921/ए एम 94/डी ई एस–5)]

के. एम. अहमें, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार
कृते महानिदेशक, विदेश व्यापार

ORDER

New Delhi, the 7th February, 1994

S.O. 501.—M/s. Saurashtra Cement and Chemicals Industries Ltd., Ranavav, Gujarat, Pin Code-360560 were issued a Quantity Based Advance Licence No. P/L/1524408 dated 23-11-93 for import of Coal 13066.6 M.T. for cif value of Rs. 2,02,53,232 (US Dollar 653,330) with an obligation to export (A) Clinker (excluding Portland Slag Cement)-40333.00 M.T.-F.O.B. Value US Dollar 13,30,989; and

(B) Ordinary Portland Cement (Excluding Portland Slag Cement)-25000.00 M.T.—F.O.B. Value US Dollar 867,000 for a total F.O.B. Value of Rs. 6,80,71,719 (US Dollar 21,97,989) with a Value Addition of 236 per cent. This Licence was issued alongwith Duty Exemption Entitlement Certificate (DEEC) bearing Serial Nos. 091483 (PART I—IMPORT) and 091483 (PART II—EXPORT).

2. The firm has now applied for issue of Duplicate Advance Licence alongwith DEEC Book (both Part-I and Part-II) on the ground that the original Advance Licence alongwith DEEC BOOK despatched by this office has not been received by them till date.

3. In support of their contention, the Licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public. I am accordingly satisfied that the Original Advance Licence bearing the number P/L/1524408 dated 23-11-93 alongwith DEEC Book Nos. 091483 (both Imports and Exports) has not been received by the firm. In exercise of the powers conferred under section 9(4) of Foreign Trade (Development of Regulation) Act, 1992 and Rule 10 of the Foreign Trade Regulation Rules 1993, the said original Advance Licence Number P/L/1524408 dated 23-11-93 and the DEEC Book Number 091483 (Part-I IMPORT) and 091483 (PART-II EXPORT) issued in favour of M/s. Saurashtra Cement and Chemicals Industries Ltd., Ranavav, Gujarat-360560 is hereby cancelled.

4. A duplicate Advance Licence alongwith DEEC Book (both IMPORTS and EXPORTS) is being issued to the Party separately).

[F. No. 01/84/40/921/AM94/DES-V]

K. M. BRAHME, Dy. Director General of Foreign Trade
For Director General of Foreign Trade

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1994

का.आ. 502 :—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड "ख" के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे दिये गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस : 6381-1972	संशोधन सं. 3 दिसम्बर 1993	1993-12-31

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, तथा मद्रास और शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना त्रिवेन्द्रम, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में बिक्री हेतु उपलब्ध है।

[सख्या केप्रवि/13 : 5]

एन. श्रीनिवासन, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION

(Bureau of Indian Standards)

New Delhi, the 19th January, 1994

S.O. 502 .—In pursuance of clause (b) of Sub Rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment to the Indian Standard given in the schedule hereto annexed has been issued.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standard amendment	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1	2	3	4
1.	IS 6381 : 1972	Amdt No. 3 December 1993	1993-12-31

Copies of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : Bombay, Calcutta, Chandigarh and Madras and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Patna, Faridabad, Ghaziabad and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 5]

N. SRINIVASAN, Addl. Director General

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

का.आ. 503:—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लम्बी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "जे पी पी" सिरीज और "जे पान" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, और स्वचलित तोलन उपकरण के प्रतिमान का, जो मैसर्स जे इंस्ट्रूमटस एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ई-16, एवरेस्ट, ताड़देव रोड़, मुम्बई - 400036 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी./01/94/06 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ;

पुनश्चः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार उसी सामग्री से विनिर्मित, जिससे अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, उसी सिरीज के उसी प्रकार, शुद्धता और कार्यकरण के 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम,

50 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम और 5000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तोलन उपकरण भी आएंगे ।

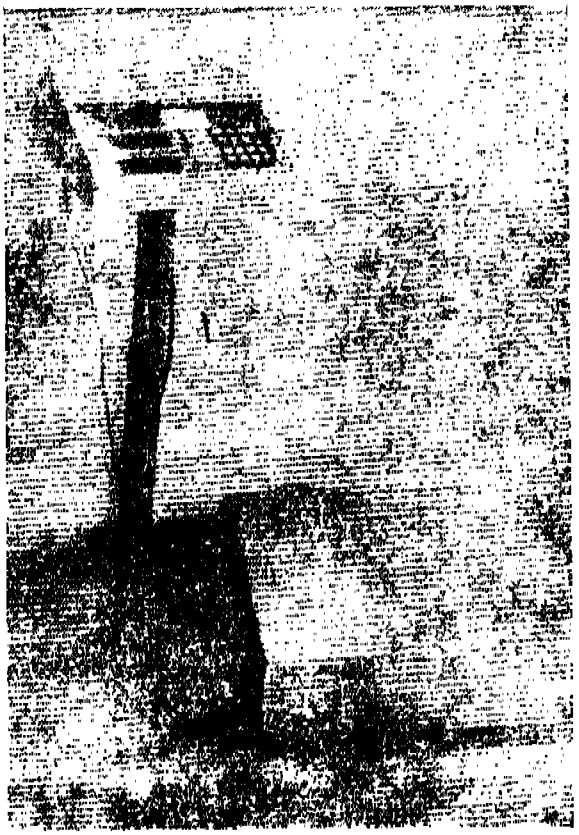

(आकृति 1)

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है । सत्यापन मापमान अंतर (ई) 200 ग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । प्लेटफार्म स्टेनलेस स्टील का बना है और वर्गाकार है और एक तरफ की 500 किलोमीटर की लम्बाई है । 12 × 8 मिलीमीटर संप्रतिक आकार का सात अंडीय निर्वात प्रतिदीप्तिशील प्रदर्श, तोल परिणाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

[फा. सं. डब्ल्यू 21(20)90]
सती नायर, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 4th February, 1994

S.O. 503.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic weighing instrument of 'JAP' series and with brand name 'JAY-PAN' manufactured by M|s. Jay Instruments and Systems Private Limited, E-16, Everest, Tardeo Road, Bombay-400 036, and which is assigned the approval mark-IND|01|94|06;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the Weighing Instrument of similar make, accuracy and performance of same series with a maximum capacity of 5 kilogram, 10 kilogram, 25 kilogram, 30 kilogram, 50 kilogram, 200 kilogram, 300 kilogram, 500 kilogram, 1000 kilogram, 2000 kilogram, 3000 kilogram and 5000 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

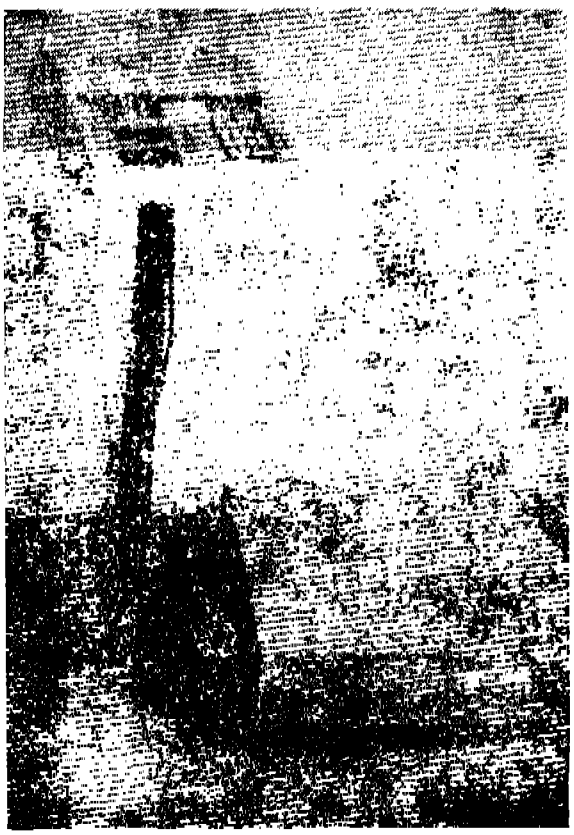

(Figure 1)

The Model (see Figure 1) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kilogram and a minimum capacity of 400 gram. The verification scale interval(e) is 200 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The platform is made up of stainless stlee and is of square shape with sides of length 500 millimetre. The seven segment vacuum fluorescent display of character size 12 millimetre × 8 millimetre indicate the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply

[F. No. WM-21(35)/92]
SATHI NAIR, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

का.आ. 504 :—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित

प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लम्बी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "जे.पी.टी." सिरीज और "जे.पान" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, गैर स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का, जो मैसर्स ज इंस्ट्रूमेंटस एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ई–16, एवरेस्ट, ताड़देव रोड, मुम्बई–400036 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी./01/94/07 समनुदेशित किया गया है; अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

पुनश्चः, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार उसी सामग्री से विनिर्मित जिसके अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, उसी सिरीज के इसी प्रकार, शुद्धता और कार्यकरण, और 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 30 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तोलन उपकरण भी आएंगे।

(आकृति 1)

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है। सत्यापन मापमान अंतर (ई) 2 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। प्लेट फार्म स्टेनलेस स्टील का बना है और आयताकार है और तरफों की 300 मिलीमीटर × 225 मिलीमीटर की लम्बाई वाला है। 12 मिलीमीटर × 8 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का सात खंडीय निर्वात प्रतिदीप्तिमान प्रदर्श, तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा.सं. डब्ल्यू 21(35)92]

सती नायर, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 4th February, 1994

S.O. 504.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic weighing instrument of 'JAP' series and with brand name 'JAY-PAN' manufactured by M/s. Jay Instruments and Systems Private Limited, E-16, Everest, Tardeo Road, Bombay-400 036, and which is assigned the approval mark-IND/01/94/07;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the Weighing Instrument of similar make, accuracy and performance of same series with a maximum capacity of 1 kilogram, 1.5 kilogram, 2 kilogram, 5 kilogram and 30 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

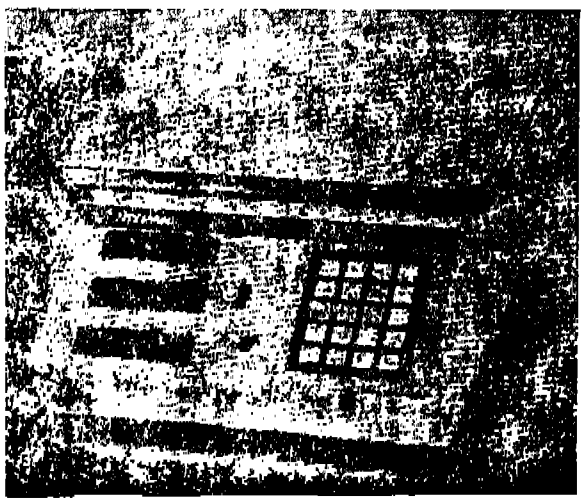

(Figure 1)

The Model (see Figure 1) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 10 kilogram and a minimum capacity of 40 gram. The verification scale interval(e) is 2 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The platform is made up of stainless steel and is of rectangular shape with sides of length 300 millimetre × 225 millimetre. The seven segment vacuum fluorescent display of character size 12 millimetre × 8 millimetre indicate the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(35)/92.]

SATHI NAIR, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

का.आ. 505—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लम्बी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "डी 1-10" सिरीज और "इसई डिग्री" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, गैर-स्वचलित तोलन उपकरण के प्रतिमान का, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) जो मैसर्स इसई टेरोका प्रा.लि., 27, 9वां क्रास बिल्सन गार्डन बेंगलोर-560027 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी./09/94/08 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र, प्रकाशित करती है;

पुनश्चः, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार उसी सामग्री से विनिर्मित, जिससे अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, उसी सिरीज के सभी प्रकार, शुद्धता और कार्यकरण और 30 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम और 6000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तोलन उपकरण भी आएंगे।

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 60 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है। सत्यापन मापमान अंतर (ङ) 10 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। प्लेटफार्म स्टेनलेस स्टील का बना है और आयातकार है और 300 मिलीमीटर × 225 मिलीमीटर की तरकी वाला है 12 मिलीमीटर × 8 मिलीमीटर संप्रतीतक आकार का सात खंडीय द्रव क्रिस्टल प्रदर्श, तोल परिणाम, उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(4)/90]
सती नायर, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 4th February, 1994

S.O. 505.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic weighing instrument of 'DI-10' series and with brand name 'ESSAE DIGI' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Essae Teraoka Pvt. Ltd., 27, 9th Cross, Wilson Garden, Bangalore-560 027, and which is assigned approval mark-IND/09/94/08;

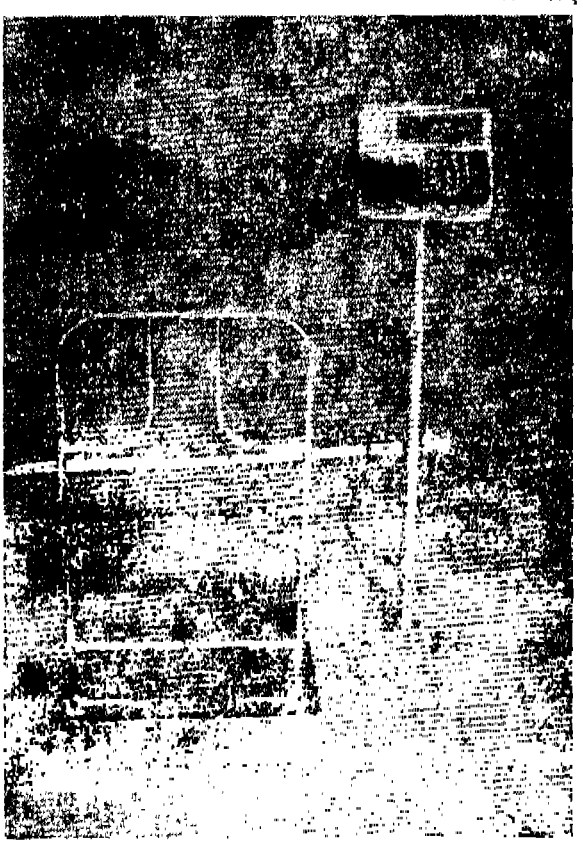

(आकृति 1)

(Figure 1)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the Weighing Instrument of similar make, accuracy and performance of same series with a maximum capacity of 30 kilogram, 150 kilogram, 300 kilogram, 600 kilogram, 1500 kilogram, 3000 kilogram and 6000 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

The Model (see Figure 1) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 60 kilogram and a minimum capacity of 200 gram. The verification scale interval(e) is 10 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The platform is made up of stainless steel and is of rectangular shape with sides of length 300 millimetre x 225 millimetre. The seven segment liquid crystal display of character size 12 millimetre × 8 millimetre indicate the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(4)/90.]

SATHI NAIR, Jt. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के मामले में

राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के मामले में

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

का.आ. 506.—पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि भारत के लिए पूर्त विन्यास के खजांची वित्त भूतपूर्व वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में निहित तथा सचिव खजांची (राष्ट्रीय बाल कोष) के नामे जमा रु. 15,00,000 (पन्द्रह लाख रुपये मात्र) के अंकित मूल्य की निम्नलिखित प्रतिभूतियां संबंधी प्रतिदान आय को सचिव खजांची (राष्ट्रीय बाल कोष) के नामे अंतरित कर दिया जाये।

प्रतिभूतियां का विवरण	अंकित मूल्य	जिस तिथि को देय है
पंचवर्षीय डाकखाना आवधिक जमा योजना	रु. 15,00,000	28-01-94

[सं. 13-4/93-टी-आर-II]

सुरजीत लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women & Child Development)

In the Matter of the Charitable Endowmens Act 1890

(6 of 1890)

In the Matter of the National Children's Fund, New Delhi

New Delhi, the 25th January, 1994

S.O. 536.—In pursuance of Section 10 of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Central Government do hereby order that the redemption proceeds in respect of the following securities of the face value of Rs. 15,00,00/- (Rupees Fifteen lakhs only) held in the name of Secretary-Treasurer (NCF) and invested in the Treasurer of Charitable Endowments for India, erstwhile Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block, New Delhi be transferred to the Secretary-Treasurer (NCF).

Description of Securities	Face	Maturing on
Five Years Post Office Time Deposit Scheme	Rs. 15,00,000/-	28-01-1994

[F. No. 13-4/93-TR-II]

SURJIT LAL, Under Secy.

पेट्रोलियम और केमीकल्स मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

का. आ. 507.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सुम्मन थालाम से गुडल पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उक्त कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बेसीन प्रोजेक्ट, 29 7-1/3/1 राजमंड्री--533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट सुरसनयानम से गुडल

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे (एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी (आं. प्र.)	उप्पलगुप्तम	सुरसनयनाम	196-1 भाग	0-09-50	
			197-1 भाग	0.02.00	
			197-2 भाग	0.49.00	
			199-भाग	0.12.50	
			188-1ए भाग	0.18.00	
			189-2 भाग	0.01.00	
			67-1ए भाग	0.18.00	
			67-1बी भाग	0.04.00	9 पी
			67-1सी भाग	0.13.00	
			68-1ए भाग	0 01.00	
			68-1बी भाग	0.16.00	
			68-2ए भाग	0.05.50	
			70-1 भाग	0.09.50	
			70-2 भाग	0.07.50	
			70-3 भाग	0.00.50	
			70-4 भाग	0.15.00	
			70-5 भाग	0.12.50	
			70-6 भाग	0.06.00	
			70-7ए भाग	0.40.00	
			70-7बी भाग	0.02.00	
			70-7सी भाग	0.01.00	
			70-7डी भाग	0.00.50	
			70-23ए/1 भाग	0.03.00	
			70-23ए/2 भाग	0.03.00	
			71-2बी	0.09.50	
			71-2सी	0.10.00	
			71-3ए	0.01.00	
			72-1 भाग	0.10.00	
			72-2 भाग	0.12.50	
			59-3सी भाग	0.08.00	
			79-भाग	0.03.00	जी पी
			92-1ए भाग	0.04.00	
			92-1बी भाग	0.09.50	
			92-8ए भाग	0.01.50	
			92-8बी भाग	0.03.00	
			92-9 भाग	0.01.00	
			91-1 भाग	0.07.00	
			91-2 भाग	0.03.00	
			90-2 भाग	0.12.50	
			90-3 भाग	0.11.00	
			90-4 भाग	0.01.00	
			83-5 भाग	0.07.50	
			89-3 भाग	0.07.50	
			84-1बी भाग	0.08.00	

1	2	3	4	5	6
			84–1सी भाग	0.16.00	
			84–3 भाग	0.04.00	
			85–1ए भाग	0.17.00	
			85–1बी भाग	0.06.00	
			28– भाग	0.02.50	

[3.95.00 या एसी 9-75 सेंटस]

[सं. एल– 14016/19/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

New Delhi, the 1st February, 1994

S.O. 507.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Surasanayanam to Gudala pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G Basin Project-29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GAS PIPE LINE PROJECT

Surasana Yanam to Gudala

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
East Godavari	Uppalaguptam	Surasana Yanam	196-1 part	0–09–50	
			197-1 ,,	0–02–00	
			197-2 ,,	0–49–00	
			199 ,,	0–12–50	
			188-1A ,,	0–18–00	
			189-2 ,,	0–01–00	
			67-1A ,,	0–18–00	
			67-1B ,,	0–04–00	G.P.
			67-1C ,,	0–13–00	
			68-1A ,,	0–01–00	
			68-1B ,,	0–16–00	
			68-2A ,,	0–05–50	
			70-1 ,,	0–09–50	
			70-2 ,,	0–07–50	
			70-3 ,,	0–00–50	
			70-4 ,,	0–15–00	
			70-5 ,,	0–12–50	
			70-6 ,,	0–06–00	
			70-7A ,,	0–04–00	
			70-7B ,,	0–02–00	
			70-7C ,,	0–01–00	
			70-7D ,,	0–00–50	
			70-23A/1 ,,	0–08–00	
			70-23 A/2 ,,	0–03–00	
			71-2B	0–09–50	
			71-2C	0–10–00	
			71-3A	0–01–00	
				2–39–50	AC 5-90 Cents

1	2	3	4	5	6
East Godavari	Uppala Guptam	Surasana Yanam	72-1 part	0-10-00	
			72-2 ,,	0-12-50	
			59-3C ,,	0-08-00	
			79- ,,	0-03-00	GP
			92-1A ,,	0-04-00	
			92-1B ,,	0-09-50	
			92-8A ,,	0-01-50	
			92-8B ,,	0-03-00	
			92-9 ,,	0-01-00	
			91-1 ,,	0-07-00	
			91-2 ,,	0-03-00	
			90-2 ,,	0-12-50	
			90-3 ,,	0-11-00	
			90-4 ,,	0-01-00	
			83-5 ,,	0-07-50	
			89-3 ,,	0-07-50	
			84-1B ,,	0-08-00	
			84-1C ,,	0-16-00	
			84-3 ,,	0-04-00	
			85-1A ,,	0-17-00	
			85-1B ,,	0-06-00	
			28- ,,	0-02-50	
				1-55-50	ORAC 3-85 Cents.
			1 PPSI	2-39-50	ORAC 5.90 Cents.
				3-95-00	ORAC 9.75 Cents.

[No. L-14016/19/93/GP]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

का. आ. 508 :—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सुरसन यानम गुडल पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजक्ट, 29-7/-1/3/1 राजमंड्री-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज कर सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट सुरसन यानाम से गुडल

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हैक्टे/ (एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदवरि (आं. प्र.)	उप्पलागुप्तम	वल्लपल्लि	741/1—भाग	0.00.50	जि पि
			741/2—भाग	0.05.50	जि पि
			739—1बी भाग	0.04.50	
			739—2 भाग	0.14.50	
			739—3 भाग	0.16.00	

1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरि (आं. प्र.)	उप्पलगुप्तम	चल्लपल्लि	739-5 भाग	0.02.00	
			736/2-भाग	0.06.00	
			736/2-भाग	0.06.50	
			722-1ए भाग	0.09.00	
			732-1बी भाग	0.07.50	
			722-2 भाग	0.01.00	
			722-3 भाग	0.07.50	
			721-1 भाग	0.06.50	
			721-2 भाग	0.09.50	
			720-1 भाग	0.04.50	
			720-2 भाग	0.22.50	
			718-भाग	0.03.00	
			752-भाग	0.04.00	
			749-1 भाग	0.13.00	
			749-2 भाग	0.11.00	
			750-भाग	0.14.00	
			751/1-भाग	0.03.00	
			751/1-2 भाग	0.09.50	
			754-भाग	0.01.50	जिपि
			759-4 भाग	0.01.50	
			760-2 भाग	0.00.50	
			760-3ए भाग	0.11.00	
			760-3सी भाग	0.02.00	
			760-3डी भाग	0.00.50	
			760-3ई भाग	0.08.00	
			761-2 भाग	0.00.50	
			761-7 भाग	0.09.50	
			761-8 भाग	0.08.50	
			761-9 भाग	0.07.50	
			761-10 भाग	0.04.50	
			761-17 भाग	0.01.50	
			660-4ए भाग	0.04.50	
			660-4ए भाग	0.03.00	
			जोड़	2.39.00	
			660-5बी भाग	0.01.00	
			660-5सी भाग	0.03.00	
			660-5डी भाग	0.01.50	
			660-5जी भाग	0.03.50	
			660-6सी भाग	0.00.25	
			659-1 भाग	0.06.50	
			659-3 भाग	0.00.25	
			659-4 भाग	0.01.00	
			659-5 भाग	0.01.50	
			659-6 भाग	0.04.50	
			659-7 भाग	0.04.50	
			659-8 भाग	0.08.50	
			661-1 भाग	0.03.00	
			661-2 भाग	0.03.00	
			661-3 भाग	0.03.00	
			661-4 भाग	0.03.00	
			661-5 भाग	0.04.50	
			661-6 भाग	0.04.00	
			661-7 भाग	0.04.50	
			661-8 भाग	0.05.00	

1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरि (आंध्र प्रदेश)	उप्पलगुप्तम (जारी)	चल्लपल्लि (जारी)	648–1ए भाग	0.03.50	
			648–1बी भाग	0.04.50	
			648–1सी भाग	0.07.50	
			648–3 भाग	0.09.50	
			648–4 भाग	0.09.50	
			644–1 भाग	0.00.50	
			649–2 भाग	0.07.50	
			650/2–भाग	0.18.00	
			642/2–6 भाग	0.25.50	
			631–भाग	0.06 50	जिपि
			632–2 भाग	0.42.00	
			641–8 भाग	0.07.50	
			641–9 भाग	0.17.00	
			641–10 भाग	0.07 50	
			638–भाग	0.02 00	जिपि
			कुल जोड़	4.73 50 या एसी 11–69½ (सैटस)	

[सं. एल—14016/19/93—जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 1st February, 1994

S.O. 508.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Surasenayanam to Gudala pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gas Pipe line Project

Surasenayanam-to-Gudala

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
East Godavari (Andhra Pradesh)	Uppalaguptham	Challapalli	741 —Part 1	0-00-50	G.P.
			741 —Part 2	0-05-50	G.P.
			739-1B Part	0-04-50	
			739-2 ,,	0-14-50	
			739-3 ,,	0-16-00	
			739-5 ,,	0-02-00	
			736 —Part 2	0-06-50	G.P.
			722-1A Part	0-09-00	
			722-1B ,,	0-07-50	

1	2	3	4	5	6
East Godavari (Andhra Pradesh)	Uppalaguptham—Contd.	Challapalli—Contd.	722-2 Part	0-01-00	
			722-3 „	0-07-50	
			721-1 Part	0-06-50	
			721-2 „	0-09-50	
			720-1 Part	0-04-50	
			720-2 „	0-22-50	
			718-Part	0-03-00	
			752-Part	0-04-00	
			749-1 Part	0-13-00	
			749-2 „	0-11-00	
			750-Part	0-14-00	
			751 ——1 Part 1	0-03-00	
			751/1-2 Part	0-09-50	
			754-Part	0-01-50	G.P.
			759-4 Part	0-01-50	
			760-2 Part	0-00-50	
			760-3A „	0-11-00	
			760-3C „	0-02-00	
			760-3D „	0-00-50	
			760-3E „	0-08-00	
			761-2 Part	0-00-50	
			761-7 „	0-09-50	
			761-8 „	0-08-50	
			761-9 „	0-07-50	
			761-10 „	0-04-00	
			761-17 „	0-01-50	
			660-4A Part	0-04-50	
			660-5A „	0-03-00	
			660-5B Part	0-01-00	
			660-5C „	0-03-00	
			660-5D „	0-01-50	
			660-5G „	0-03-50	
			660-6C „	0-00-25	
			659-1 Part	0-06-50	
			659-3 „	0-00-25	
			659-4 „	0-01-00	
			659-5 „	0-01-50	
			659-6 „	0-04-50	
			659-7 „	0-04-50	
			659-8 „	0-08-50	
			661-1 Part	0-03-00	
			661-2 „	0-03-00	
			661-3 „	0-03-00	
			661-4 „	0-03-00	
			661-5 „	0-04-50	
			661-6 „	0-04-00	
			661-7 „	0-04-50	
			661-8 Part	0-01-00	
			648-1A Part	0-03-50	
			648-1B „	0-04-50	
			648-1C „	0-07-50	
			648-3 „	0-09-50	
			648-4 „	0-09-50	
			644-1 Part	0-00-50	
			649-2 Part	0-07-50	
			650 ——Part 2	0-18-00	
			642 ——6 Part 2	0-25-50	
			631-Part	0-06-50	G.P.
			632-2 Part	0-42-00	

1	2	3	4	5	6
East Godavari (contd.)			641-8 Part	0-07-50	
			641-9 part	0-17-00	
			641-10 Part	0-07-50	
			638-Part	0-02-00	G.P.
			Total	2-34-50	
			Total	2-39-00	
			Grand Total	4-73-50 or AC	11-69 1/2 Cents

[No L-14016/19/93-GP.]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

का. आ. 509 :—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए गुरसन थानाम से गुडल पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बेसीन प्रोजेक्ट, 29-8-1/3/1 राजमंड्री —533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर एकड़ में)	विवरण
पूर्वी गोदावरी	उप्पालागुप्तम	गोपावरम	202-1 भाग	0.15.00	
			202-2 भाग	0.10.50	
			203-1 भाग	0.25.50	
			203-5 भाग	0.16.00	
			238-भाग	0.10.00	
			241-भाग	0.16.00	
			245-2 भाग	0.14.00	
			236-भाग	0.02.50	
			244-भाग	0.19.00	
			247-1 भाग	0.00.50	
			247-2 भाग	0.00.50	
			247-3 भाग	0.02.00	
			247-4 भाग	0.07.50	
			247-5 भाग	0.11.50	
			243-1 भाग	0.01.00	
			243-2 भाग	0.05.00	
			268-3 भाग	0.04.50	
			267-1 भाग	0.02.50	जी.पी.
			266-2 भाग	0.08.00	

1	2	3	4	5	6
पूर्वी गोदावरी (जारी)			266-3 भाग	0.07.00	
			266-4 भाग	0.01.50	
			266-5 भाग	0.03.00	
			266-6 भाग	0.01.00	
			262-भाग	0.24.00	
			272-भाग	0.03.00	जीपी
			263-भाग	0.01.00	
			279-2 भाग	0.11.50	
			278-1 भाग	0.07.50	
			278-2 भाग	0.13.00	
			276-1 भाग	0.07.50	
			277-3 भाग	0.16.00	
			286-भाग	0.03.00	जीपी
			287-2ए भाग	0.03.50	
			287-2बी भाग	0.09.00	
			287-3 भाग	0.02.00	
				2.85.00	(या एसी 7-04 सेन्टीयर)

[सं. एल-14016/19/93-जीपी]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 1st February, 1994

S.O. 509.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Surasanayanam to Gudala pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (i) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project. 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GAS PIPE LINE PROJECT

Sura Sana Yanam to Gudala

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
East Godavari	Uppalaguptam	Gopavaram	202-1 Part	0-15-00	
			202-2 ,,	0-10-50	
			203-1 ,,	0-25-50	
			203-5 ,,	0-16-00	
			238 ,,	0-10-00	G.P.
			241 ,,	0-16-00	
			245-2 ,,	0-14-00	
			236 ,,	0-02-50	
			244 ,,	0-19-00	
			247-1 ,,	0-00-50	
			247-2 ,,	0-00-50	
			247-3 ,,	0-02-00	
			247-4 ,,	0-07-50	
			247-5 ,,	0-11-50	
			243-1 ,,	0-01-00	
			243-2 ,,	0-05-00	
			268-3 ,,	0-04-50	
			267 ,,	0-02-50	G.P.
			266-2 ,,	0-08-00	
			266-3 ,,	0-07-00	

1	2	3	4	5	6
East Godavari	Uppalaguptam	Gopavaram	266-4 Part	0–01–50	
			266-5 ,,	0–03–00	
			266-6 ,,	0–01–00	
			262 ,,	0–24–00	
			272 ,,	0–03–00	G.P.
			263 ,,	0–01–00	
			279-2 ,,	0–11–50	
			278-1 ,,	0–07–50	
			278-2 ,,	0–13–00	
			276-1 ,,	0–07–50	
			277-3 ,,	0–16–00	
			286 ,,	0–03–00	G.P.
			287-2A ,,	0–03–50	
			287-2B ,,	0–09–00	
			287-3 ,,	0–02–00	
				2–85–00 Or Ac 7.04 Cents	

[No. L-14016/19/93-GP]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

का. आ. 510 :—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सुर्सानीयानम से गुडला पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछायी जानी है।

और यह भी अनुभव करती है कि उक्त कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने का मंशा को घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अभिरुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमि. के. जी. बेसिन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 गोष्मी लाइब्रेरी के सामने राजमंड्री—533 104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

सुर्सानीयानम से गुडला

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरणी
1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी (आ. प्र.)	अल्लवरम	साडिकोंडा	166-1 भाग	0.17.00	
			166-2 भाग	0.04.00	
			165-2 भाग	0.14.50	
			167-3ए भाग	0.01.50	
			164-2 भाग	0.20.50	
			164-3 भाग	0.20.00	
			173-भाग	0.05.50	जिपि
			179-2 भाग	0.07.50	
			175-1 भाग	0.04.00	
			175-2 भाग	0.12.00	
			178-5 भाग	0.09.50	
			176-7 भाग	0.06.50	

1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी (आं. प्र.)—समाप्त	अल्लवरम	ताडिकोना	176-8 भाग	0.05.50	
			176-5 भाग	0.00.50	
			152-1 भाग	0.01.00	
			147-3 भाग	0.18.00	
			147-4 भाग	0.07.50	
			148-1सी भाग	0.09.00	
			148-1बी भाग	0.05.50	
			148-1ए भाग	0.07.50	
			149-1बी भाग	0.00.50	
			149-1सी भाग	0.05.50	
			149-1ए भाग	0.01.50	
			145-भाग	0.04.00	जी.पी.
			127-2 भाग	0.21.00	
			127-1 भाग	0.08.50	
			125-3सी भाग	0.02.00	
			125-3बी भाग	0.03.00	
			125-3ए भाग	0.03.00	
			125-2 भाग	0.03.50	
			125-1 भाग	0.03.50	
			124-2 भाग	0.10.50	
			132-4 भाग	0.07.50	
			कुल	2.-33.00	
				ओ आर ए सी 5.76 सेन्ट्स	

[सं. एल--14016/19/93 जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 1st February, 1994

S.O. 510.—Whereas it appears to the Cetnral Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Surasenayanam to Gudala pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project. 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GAS PIPE LINE PROJECT

Surasanayanam-to-Gudala

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
East Godavari (Andhra Pradesh)	Allavaram	Tadikona	166-1 Part	0-17-00	
			166-2 ,,	0-04-00	
			165-2 Part	0-14-50	
			167-3A Part	0-01-50	
			164-2 Part	0-20-50	
			164-3 Part	0-02-00	
			173-Part	0-05-50	G.P.
			179-2 Part	0-07-50	
			175-1 Part	0-04-00	
			175-2 Part	0-12-00	
			178-5 Part	0-09-50	
			176-7 Part	0-06-50	
			176-8 Part	0-05-50	

176-5 Part	0–00–50		
152-1 Part	0–01–00		
147-3 Part	0–18–00		
147-4 Part	0–07–50		
148-1C Part	0–09–00		
148-1B Part	0–05–00		
148-1A Part	0–07–50		
149-1B Part	0–00–50		
149-1C Part	0–05–50		
149-1A Part	0–01–50		
145-Part	0–04–00	G.P.	
127-2 Part	0–21–00		
127-1 Part	0–08–50		
125-3C Part	0–02–00		
125-3B Part	0–03–00		
125-3A Part	0–03–00		
125-2 Part	0–03–50		
125-1 Part	0–03–50		
124-2 Part	0–10–00		
132-4 Part	0–07–50		
Total	2–33–00		
	or AC		5.76 Cents

[No. L-14016/19/93-GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

का. आ. 511.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए सूरसन से यानाम पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बेसिन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री—533 104, आन्ध्र-प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

सूरसन से यानाम

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरि	अल्लवरम	गूडल	324–1डी भाग	0.17.50	
			325–1 भाग	0.03.50	
			325–2 भाग	0.29.00	
			325–4बी भाग	0.07.50	
			325–5बी भाग	0.07.50	
			317–1 भाग	0.00.50	
			317–2 भाग	0.00.25	
			317–3ए भाग	0.11.00	
			317–3बी भाग	0.00.50	

305- 1 भाग	0 09.50
305- 3 भाग	0.10.50
305- 4 भाग	0.10.00
305- 5 भाग	0.10.00
309- 1 भाग	0.03.00
309- 2 भाग	0.04.50
309-3 भाग	0.05.50
309- 5 भाग	0.05.50
309- 6 भाग	0.05.00
308- 2 भाग	0.00.50
308- 4 भाग	0.05.50
308- 5 भाग	0.08.50
314-भाग	0.20.00

[1-75-2 या एसी/4-33/1/2 सेंट्स]

[सं. एल.-14016/19/93--जीपी]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 1st February, 1994

S.O. 511.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Surasena yanam to Gudala pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore. in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project. 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GAS PIPE LINE PROJECT

(Gudala) Sura Suna Yanam to Gudala

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
East Godavari	Allavaram	Gudala	324-1D Part	0-17-50	
			325-1 Part	0-03-50	
			325-2 Part	0-29-00	
			325-4B Part	0-07-50	
			325-5 Part	0-07-50	
			317-1 Part	0-00-50	
			317-2 Part	0-00-25	
			317-3A Part	0-11-00	
			317-3B Part	0-00-50	
			305-1 Part	0-09-50	
			305-3 Part	0-10-50	
			305-4 Part	0-10-00	
			305-5 Part	0-10-00	
			309-1 Part	0-03-00	
			309-2 Part	0-04-50	
			309-3 Part	0-05-00	
			309-5 Part	0-05-50	
			309-6 Part	0-05-00	
			308-2 Part	0-00-50	
			308-4 Part	0-05-00	
			308-5 Part	0-08-50	
			314 Part	0-20-00	

1-75-25 or AC 433 1/2 Cents

[No. L-14016/19/93-GP]
ARDHENDU SEN, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1994

का.आ. 512 —भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2277 (हिन्दी पाठ) तारीख 30 अक्तूबर, 1993 में अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ 2 में "राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्य" के स्थान पर "राजस्थान" पढ़ें ।

[सं. आर 31015/48/93–ओ.आर.–I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1994

का.आ. 513 —केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 2279 (हिन्दी पाठ) तारीख 30 अक्तूबर, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तम्भ 1 में "डिप्टी कलेक्टर (प्रतिनियुक्ति पर)" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर "भूमि अर्जन अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[सं. आर–31015/48/93–ओ.आर.–I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd February, 1994

S.O. 514.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2279, dated the 30th October, 1993, namely :—

In the table to the said notification, in column 1, for the words and brackets, "Shri Ram Verma, Deputy Collector (on deputation)" the words and brackets" Mr. Shri Ram Verma, Land Acquisition Officer (on deputation)", shall be substituted.

[No. R-31015|48|93-O.R-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

का.आ. 515.—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कतिपय संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार अधोवर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहद् योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 10–9–93 के नोटिस संख्या एफ. 10(19) 91 एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 11–क की उप-धारा (3) में यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे ।

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां और सुझाव जनता से प्राप्त नहीं हुई हैं, और यतः केन्द्र सरकार ने दिल्ली वृहद् योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है ।

अतः अब केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11–क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद् योजना में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन :—

पृष्ठ 154 पर (बांया कालम), भारत का राजपत्र भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 1-8-90, उप-शीर्ष पी-2 (जिला पार्क) में "चिड़ियाघर" शब्द के पीछे निम्नलिखित संशोधन जोड़े जाते हैं :—

"40 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिला पार्क में रेस्तरां, जोकि निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है :—

(क) रेस्तरां के प्लाट का क्षेत्रफल 0.8 हैक्टेयर (2 एकड़) अथवा जिला पार्क का 1% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ख) रेस्तरां का प्लाट शेष जिला पार्क के क्षेत्रफल से वास्तविक रूप से अलग नहीं है ।

(ग) भवन अधिकतम 5एफ.ए.आर. सहित एक मंजिला होगा और बिना किसी आवास सुविधा के इसकी ऊंचाई 4 मी. से अधिक नहीं होगी तथा यह अड़ौस-पड़ौस के अनुकूल होगा ।

(घ) जहां पर अड़ौस-पड़ौस में गाड़ियों के पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर रेस्तरां से उपयुक्त दूरी पर पार्किंग सुविधा मुहैया करानी चाहिए, पार्किंग क्षेत्रफल रेस्तरां परिसर/हरित पट्टी का भाग नहीं होना चाहिए ।

(ङ) स्थल पर जहां पानी, सीवर और अन्य सुविधाएं नहीं हैं, अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, वहां पर उक्त सभी सुविधाओं की व्यवस्था उद्यमी ही करेगा ।

[सं. के. 13011/7/93–डीडी (1 बी)]

एस.सी. सागर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 31st January, 1994

S.O. 515.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder were published with Notice No. F.-10 (19)91-MP dated 10/9/93 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objections/suggestions were received from the public with regard to the said proposed modifications and whereas the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notifications in the Gazette of India.

MODIFICATION :

At page 154 (left hand column), Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii) dated 1-8-90 under subheading P-2 (District Park), the following modifications are added after the words 'Zoological Garden";

Restaurant in a District Park having area above 40 hectares, subject tol that;

(a) area of the restaurant plot is not more than 0.8 hect. (2 acres) or 1% of the District Park, whichever is less;

(b) restaurant plot has no physical segregation from the rest of the, District Park area;

(c) the building is to be a single storey structure with maximum FAR of .5 and height not more than 4 mtrs. without any residential facility and to harmonise with the surroundings;

(d) in case there is no parking lot in the vicinity, parking should be provised at a reasonable distance from the restaurants; the parking area should not form a part of the restaurant complexe'greens.

(e) the enterpreneur is to make all arrangement so water, sewerage and other utilities wherever not available at site or provided for the the local ody.

[No. K-13011/7/93-DD 1B]

S. C. SAGAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1994

का.आ. 516.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मे. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मुरूलीडीह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-1-94 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.-20012/38/88-डी-4(ए)/आईआर(कोल-I)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th January, 1994

S.O. 516.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. II), Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Murulidih Colliery of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 14-1-1994.

[No. L-20012/38/88-D.IV (A)/IR (C-I)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 13 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Murulidih Colliery of M/s. B.C.C.L. and their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Advocate

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 6th January, 1994

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/38/88-D.IV (A)/I.R. (Coal-I). dated, the 9th May, 1989.

SCHEDULE

"Whether the management of M/s. B.C.C. Ltd. in relation to Murulidih Colliery, P.O. Mohuda, Dist. Dhanbad (Bihar) is justified in denying employment to 47 workmen detailed in the enclosed Annexure-I who are alleged to have reported for duty pursuant to Office order No. GM/ARII/ID/OO/79-2095—18 dated 1st August, 1979 by the General Manager, M/s. B.C.C. Ltd. Area No, II, P.O. Mohuda Dist. Dhanbad."

2. The action of the management of Murulidih Colliery, Dist. Dhanbad has been challenged in denying employment to 47 workmen as detailed under schedule to the order of reference.

3. The concerned workmen submitted their statement of claims stating therein that they had been working as casual wagon loader at Bhatdih Colliery since long from time of the erstwhile employer but the management of Bhatdih Colliery illegally and arbitrarily stopped from services without assigning any reason. The union namely the Bihar Colliery Mazdoor Sangh filed representation and the management after having appreciated the legal point involved in the matter issued an office order dated 1-8-79 directing the concerned workmen to report for duty at Murulidih Colliery as Miner/loader. It is stated that in pursuance of the said office order all the 55 workmen reported for their duty at Murulidih Colliery but only 8 workmen namely Shri Basudeo Bhuiya, Singheshwar Bhuiya, Bhiku Rai, Mathura Deshwali, Manu Bauri, Lattan Bhuiya, Fagu Bhuia and Palton Modi were allowed to resume their duty. The concerned workmen were not allowed to resume their duty nor any reason was assigned to them. Ultimately the industrial dispute was raised giving rise to the present reference.

4. The management has denied the relationship of employer and employee between the management and the concerned workmen. It was stated that the concerned workmen are absolutely strangers for the management and they never worked in the Colliery. Firstly the very reference was challenged to be bad in law on the ground that it was a stale case and the management had never issued any socalled office order. The so-called officer dated 1-8-79 as relied upon by the union is forged and fabricated document. It was also submitted that as per office order the concerned workmen were denied employment in the year 1979 but they kept mum for a long 10 years without any representation and this means the union is trying to induct impersonators in the garb of present purported dispute. In the circumstances it has been prayed that the concerned workmen have got no case and they are not entitled to any relief.

5. The point for consideration is as to whether the concerned workmen as per schedule of the reference are entitled for employment in pursuance to an alleged office order dated 1-8-1979.

6. The concerned workmen namely Shri Paramatama Singh and 46 others as per schedule of the reference claim to have been working as casual wagon since the time of the erstwhile employed but the management of Bhatdih Colliery stopped them from their work illegally and arbitrarily without assigning any reason. I find that the office order bearing No. GM|AR|II|FD|OO|79-2095—15 dated 1-8-1979 is the sheet anchor of the union whereunder and whereby the concerned workmen were directed to report for duty as miner/loader at Murulidin Colliery. However the management has denied to have issued any such order and as such the said office order was forged and fabricated document. In view of these facts the consideration of the office order dated 1-8-79 regarding its genuineness or otherwise seems to be a matter of paramount important. The management examined one Shri D. B. Singh MW-4, Dy. P. M, who had occasion to work as Personnel Manager under Mohuda Area for the period from April, 1986 to December, 1989. During his tenure the union namely Bihar Colliery Mazdoor Sangh had raised industrial dispute on the basis of the order dated 1-8-79. The witness stated that the said order was not a genuine one and according to him the management had never issued any such order. He also stated that the union had never produced the original of the said office order. I find that the conciliation proceeding has been called for from the office of the ALC(C), Dhanbad. Perusal of the proceeding will simply reveal that the original order dated 1-8-79 was never produced by the union. In this way the position stands admitted that at no stage the original order dated 1-8-79 was ever filed by the union and on this ground it was urged by the management that the document (Ext. M-6) was a forged and fabricated document. Anyway before appreciating this contention of the management we are required to examine other aspect of the matter and also circumstances appearing in the reference.

7. Admittedly, Form B Register has to be necessarily maintained under the provisions of Section 48 of the Mines Act, 1952 wherein the name and other details of each employee must be noted. This fact has been testified by MW-4 also. He admitted to have attended the conciliation proceeding but according to his own saying he had not filed original Form B Register of Bhatdih Colliery. Here it may be mentioned that a photo copy of Form B Register of Bhatdih Colliery has been filed under Ext. M-5 which does not bear the name of the concerned workmen. Shri B. Lakra, MW-3 has proved the photo copy of this Form B Register. In cross-examination he stated that in Bhatdih Colliery there is Form B Register wherein the names of the employees including the Manager of the Colliery can be found. He also stated that Form B Register bears the signature of Manager and the clerk who prepares it. He admitted that this Form B Register under Ext. M-5 does not bear the signature of Manager or the clerk. This statement denying signature of the Manager or the clerk in Form B Register has definitely put a question mark on the genuineness of the document. Now the question arises as to who had prepared this photo copy and from which document. Regarding original Form B Register the witness stated that it was taken over by the CBI about 20 years ago and the same was never returned to the management. The union has challenged the genuineness of Ext. M-5 and a suggestion to this effect has been put to the mouth of this witness suggesting that the phoot copy was not prepared from original Form B Register The witness MW-3 cannot say as to when Form B Register was seized by CBI. It is well settled that a seizure list has to be necessarily prepared in case of any seizure of document by any authority. The question is if the said Form B Regiser was seized then naturally the CBI must have prapared a seizure list and a copy of the same must have been given to the management. Again the question remains as to whether the management had ever entered into any correspondence with the CBI authority to return for original Form B Registers. We find that nothing has been brought on the record to appreciate this fact and that being the position the statement of the witness regarding the seizure of the Form B Register by the CBI authority cannot be appreciated. Be that as it may for the reasons stated above the photo copy of the Form B Register Ext M-5 cannot oe believed and relied upon.

8. The management has filed photo copy of Form B Register a Murulidih Colliery just to show that the names of the concerned workmen do not figure in that register. The question is if the concerned workmen were ever allowed to join their duties at Murulidih Colliery ? According to the union they were not allowed to join their duty at Murulidih Colliery. It is also stated that the management transferred 55 workmen including the concerned workmen from Bhatdih Colliery to Murulidih vide office order dated 1-8-79. They all reported for duty but only 8 were allowed to resume their duty and the rest were refused. When they did not join Murulidih Colliery there was no question of their names appearing in Form B Register of Murulidih Colliery.

9. However, the management admitted to the extent that 7 persons and not 8 were transferred to Murulidih Colliery but by different order. Surprisingly enough that different order has not been brought on the record. Certainly one order dated 13-8-79 has been filed under Ext. M-4 which reads as follows :—

> "The following newly loaders are hereby allowed to resume their duty with immediate effect. They are hereby directed to report for their duty to the Asstt. Manager. 15 Pit with immediate effect."

This order discloses 19 names in all including Basdeo Bhuia and others. According to the management they were transferred to Murulidih Colliery. But this order is not transfer order at all. This is an order directing the workmen to join their duty. Again the concerned workmen were not newly appointed loaders. In absence of any separate transfer order of 7 persons it will be presumed that they were transferred vide the order dated 1-8-79 which is being relied upon by the union. The question is if 7 workmen were transferred vide order dated 1-8-79 then the management cannot be permitted to deny the genuiness of this document. The management cannot be permitted to blow hot cold together. At one stage it allowed duty of 7 persons on the basis of the order dated 1-8-79 (Ext. M-6) and at the same time it is challenging the same order giving it a bad name as forged and fabricated when the question of employment of the concerned workmen arose. This assails and nullify the stand of the management that the union should produce original of order dated 1-8-79.

10. The management has also examined MW-1 who used to make entry in Dak and Despatch Register. The photo copy of the same has been marked Ext. M-1 to M-6. He used to fix up Sl. No. on the letter in his own hand. No Sl. Number was typed for the purpose of despatch. As stated he was not giving any composite number while giving despatch number. By adducing such evidence the management wanted to impress upon that the order dated 1-8-79 was forged for it was not bearing real despatch order number. But for the reasons stated above I have no reason to doubt the genuineness of this order under Ext. M-6. The witness in cross-examination stated that to his knowledge a clerk maintaining despatch register puts his signature but there was no such system in Mohuda Colliery and he never signed in this register By making such statement he has put a question to himself regarding the genuineness of Ext. M-1 series. In this way I am to hold that the concerned workmen were transferred to Murulidih Colliery vide order dated 1-8-79 under Ext. M-6 but they were refused to employment. Even at the conciliation stage the management has disbelieved the genuineness of order on the ground that the names of the concerned workmen were not traceable in Form B, C and E register maintained at Bhatdih Colliery. It may be mentioned that the correctness of he Form B Register which

is a photo copy under Ext. M-5 has already been discussed but the management never filed Form C and E register before this Court.

11. The management has also filed a few other documents but they are not very much relevant for the purpose of this case.

12. Ext. M-3 is the photo copy of the abandonment notice in Form I under C.M.R. 6. Ext. M-7 is the notice given by the P.M. concerning non-employment of the concerned workmen. He has stated that authentic records were not available in the Colliery as well as in the area office from which it can be ascertained as to whether they have been transferred. Ext. M-8, M-8/1, M-9, M-10, M-11 and M-12 with respect to another case namely Mahendra Thakur and other Ext. M-13 is the letter addressed to the ALC(C) Dhanbad by Shri Daula Mia, Zonal Secreary, Bihar Colliery Mazdoor Sangh Murulidih raising industrial dispute. All the important documents have already been discussed which leads support to the case of the union.

13. From the discussion made above it is well proved that an office order dated 1-8-79 was in existence whereby the concerned wornmen were transferred from Bhatdih Colliery to Murulidih Colliery to join and work there as Miner/loader but they were not given any employment rather they were stopped from their duty. That stoppage amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I. D. Act. It is also true that termination/stoppage was not preceded by statutory notice which was a flagrant violation of the provision contained under Section 25-F of the I. D. Act.

14. The learned counsel for the management submitted that the industrial dispute was raised after long delay say about after 10 years and so it was a stale claim. Reliance was placed upon certain authority as reported in M/s. Shalimar Works Ltd. vrs. their workmen AIR 1959 Supreme Court page 1217, Inder Singh and Sons Ltd. vrs. their workmen 1961 Lab. I.C. page 89 and similar other authorities. By relying on these authorities the learned counsel submitted that even though it is true that law of limitation does not apply in the industrial adjudication but it is well accepted principle that over stale claim should not generally be encouraged or allowed unless there is satisfactory explanation for the delay. It was submitted that this will have an unsettled effect on the employers financial arrangement. I find that these authorities have already been well discussed in the authority relied upon by the learned counsel for the workmen as reported in Lab. IC 1991 page 633. There is also reference of the authority as reported in AIR 1976 Supreme Court at page 1111 and 1976 Lab I.C, page 769. The learned counsel for the workmen relying upon such decision submitted that reinstatement is the only relief that follows out of illegal termination of the concerned workmen. The Hon'ble Court while discussing all the authorities was pleased to hold that there was no absolute proportion of law that in no case relief can be granted merely because there was delay in raising the industrial dispute. That was a case in which industrial dispute was raised almost after 18 years of termination. Here in the instant case we find that industrial dispute was raised after about 10 years. The concerned workmen as alleged were stopped in the year 1979 whereas the reference was made in the year 1989. We further find that industrial dispute was raised sometimes in the year 1986.

15. I have examined various aspect of the matter and on the basis of documentary and oral evidence I am to hold the view that the concerned workmen were transferred from Bhatdih Colliery to Murulidih Colliery vide office order dated 1-8-79 but they were not allowed to join their duty. I have also held that before stopping there was no compliance of giving any notice or compensation to the concerned workmen as provided under Section 25-F of the I. D. Act. For the reasons stated above I have to hold further that the concerned workmen are entitled for their reinstatement. Certainly they claim to have been making correspondence with the management for their reinstatement but we have no paper to support this contention. Thus the management is directed to reinstate all the concerned workmen within two months from the date of the publication of the Award as miner/loader provided they have not attained the age of superannuation and they are medically fit but in the circumstances, of the case there can be no order of back wages.

This is my Award.

B. RAM, Presiding Officer

ANNEXURE I

1. Parmatma Singh
2. Sujit Singh
3. Md. Henifuddin Ansari
4. Md. Juyue Ansari
5. Asmauddin
6. Shahid Khan
7. Aklal Thakur
8. Rabindra Singh
9. Khurshid Alam
10. Siraj Mia
11. Unush Mia (Chhoto)
12. Ramprasad Mahto
13. Bara Idris Mia
14. Brijnundu Pd. Singh
15. Banwari Prasad
16. Bindeshwar Pd. Singh
17. Birendar Thakur
18. Surendar Thakur
19. Barha Thakur
20. Surendar Pd. Mahoka Sharma
21. Brajesh Kr. Sharma
22. Babulal Thakur
23. Baresh Kumar
24. Yadunanda Thakur
25. Ram Pd. Harijan
26. Mahabir Thakur
27. Dhiraj Thakur
28. Dookumar Thakur
29. Devendra Kumar
30. Ram Prasad Thakur
31. Sadhu Rajwar
32. Raghunandan Rewani
33. Bhudan Rewani
34. Sakru Rewani
35. Ser Md.
36. Ch. Idrish Mia
37. Abdul Sattar
38. Suban Nag
39. Chandeshwar Sharma
40. Kailash Harijan
41. Hardwar Sharma
42. Baleshwar Sharma
43. Harenath Sharma
44. Rajendra Paswan
45. Rago Dusad
46. Bhola Paswan
47. Kailash Paswan.

Sd/-
Presiding Officer
Central Govt. Industrial
Tribunal (No. II) Dhanbad
(SEAL)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1994

का.आ. 517 —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा–1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-2-1994 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय–4 धारा–44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है (और अध्याय–5 और 6) धारा–76 की उपधारा (1) और धारा–77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

राजस्व ग्राम का नाम व नगर-पालिका सीमा	होबली	तालुक	जिला
बंगारपेट	बंगारपेट	बंगारपेट	कोलार
देसीहल्ली बंगारपेट एस.जी. कोटे बेंगानूर	हुनासानाहल्ली मंडल पंचायत	बंगारपेट	कोलार
अन्दर सन पेट रोबर्ट सन पेट	बंगारपेट	बंगारीपेत	कोलार

[संख्या एस –38013/1/94–एसएस-I]
जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 20th January, 1994

S.O. 517 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 1974 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka namely :

Name of the revenue village or Municipal limits	Hobli	Taluk	District
Bangarpet	Bangarpet	Bangarpet	Kolar
Desihalli Bangarpet S.G. Kote Benganur	Hunasanahalli Mandal Panchayat	Bangarpet	Kolar
Andersonpet Robert Sonpet	Bangarpet	Bangarpet	Kolar

[No. S-38013/1/94-SS.I
J.P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1994

का.आ. 518 —कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-कक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन गठित कार्यकारी समिति में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1288 दिनांक 4 मई, 1991 के तहत नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :—

अध्यक्ष

(क) धारा 5–कक की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त।

1. सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली

(ख) धारा 5–कक की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त।

2. अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली
3. वित्तीय सलाहकार, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

(ग) धारा 5–कक की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त।

4. सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, कलकत्ता।
5. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, लखनऊ।
6. सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग, श्रम एवं ऊर्जा विभाग, बम्बई।

(घ) धारा 5–कक की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा चयनित :

7. श्री ए. के. कसलीवाल, मै. एस. कुमार इन्टरप्राइजेज (सिनफैब) प्रा.लि., निरंजन बिल्डिंग, 99, मैरीन ड्राइव, बम्बई-400002
8. श्री पी.बी. दुग्गल, ई–222, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली।
9. श्री एन. कानन, सचिव दक्षिणी भारत नियोक्ता परिसंघ, कस्मुथी सेंटर, 498, अन्ना सलाई, मद्रास-600035

(ङ) धारा 5–कक की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा चयनित।

10. श्री प्रद्युमन सिंह, सचिव, पंजाब राज्य समिति, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एकता भवन, पुतलीघर, अमृतसर ।

11. श्री हरिभाऊ नाइक,
सचिव, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
मार्फत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, जी. डी. अम्बेडकर मार्ग, परेल, बम्बई

12. श्री ए. वैंकटराम,
भारतीय मजदूर संघ, कर्नाटक राज्य,
सूबेदार चात्रम रोड, बंगलौर–560009

(च) धारा 5–कक की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त

13. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मयूर भवन, नई दिल्ली ।

[सं. वी. 20025(1)/93-एस.एस.II]
जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 1994

S.O. 518.—In exercise of the powers conferred by section 5AA of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, the following persons to the Executive Committee constituted under the said Act in place of persons appointed vide S.O. No. 1238, dated the 4th May 1991, namely :—

CHAIRMAN :

(a) Appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 5AA.

1. Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.

(b) Appointed under clause (b) of sub-section (2) of section 5AA.

2. Additional Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.

3. Financial Adviser, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

(c) Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 5AA.

4. Secretary to the Govt. of West Bengal, Labour Department, Calcutta.

5. Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Labour Department, Lucknow.

6. Secretary to the Govt. of Maharashtra, Industry, Labour and Energy Department, Bombay.

(d) Elected by the Central Board under clause (d) of sub-section (2) of section 5AA.

7. Shri A. K. Kasliwal,
M/s. S. Kumar Enterprises (synfabs) Private Ltd., Niranjan Building, 99, Marine Drive, Bombay-400 002.

8. Shri P. B. Duggal,
E-222, New Rajinder Nagar, New Delhi.

9. Shri N. Kannan,
Secretary, Employees Federation of Southern India Karumuthi Centre 498, Anna Salai, Madras-600 035.

(e) Elected by Central Board under clause (e) of sub-section (2) of section 5AA.

10. Shri Parduman Singh,
Secretary, Punjab State Committee, All India Trade Union Congress, Ekta Bhawan, Putlighar, Amritsar.

11. Shri Haribhau Naik,
Secretary, Indian National Trade Union Congress, C/o Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, G. D. Ambedkar Marg, Parel, Bombay-9.

12. Shri A. Venkatram,
B.M.S. Karnataka State, Subedar Chatram Road, Banglore-560 009.

(f) Appointed under clause (f) of sub-section (2) of section 5AA.

13. Central Provident Fund Commissioner,
Employees Provident Fund Organisation, Mayur Bhawan, New Delhi.

[No. V 20025(1)/93-SS-II]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1994

का.आ. 519. :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैं. इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी लिमि. की चासनाला साऊथ कालियरी के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 1), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-94 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल–20012/134/90–आई आर (कोल-1)]
सी. गंगाधरन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th January, 1994

S.O. 519.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. I). Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chasnalla South Colliery of M/s. IISCO and their workmen, which was received by the Central Government on 24-1-1994.

[No. L-20012/134/90-IR (C-I)]
C. GANGADHARAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act. 1947

Reference No. 246 of 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chasnala South Colliery of M/s. Indian Iron and Steel Company Limited.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri P. K. Sinha. Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, the 14th January, 1994

AWARD

By Order No. L-20012/134/90-I.R. (Coal-I), dated the 5th October, 1990, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred in clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Chasnalla South Mine Colliery of M/s. IISCO in dismissing Shri Nandlal Ram, Loader under letter No. SM. 5B/2326 dated 15-6-89 is justified ? If not to what relief the workmen is entitled ?"

2. The learned counsel for the employer submitted that since long the Union has not been taking any interest in the case presumably because the concerned workman had expi[illegible] for passing necessary order in view of [illegible] of the case.

3. It appears that the case was placed for taking step for substitution of the workman who had expired. Since then the case has been coming on for taking this step and it appears from the order-sheet that on many times Shri D. Mukherjee, Secretary of the concerned Union, had taken adjournments for taking step regarding substitution of the deceased workman. From some of the orders it appears that one Shri K. Chakraborty had appeared on behalf of the workman and one Shri G. Chakraborty had also appeared on his behalf. It also, appears that for the last five dates none had been appearing on behalf of the workman.

4. Obviously, the matter has lingered for too long for taking one small step and it now appears that the Union has lost interest in this referred dispute may be because of the death of the workman. No doubt that for sometime this Tribunal had run without Presiding Officer but regular orders have been passed by the Incharge Presiding Officer. Even for a long period when the learned predecessor was working in this Tribunal, the Union had failed to take any step involving substitution of the deceased workman.

5. I do not think any useful purpose will be served by dragging the matter further.

6. Hence, I pass a 'no dispute award' in the present case.

P. K. SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1994

का.आ. 520.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/345/86-डी II (ए)]
बी.एम डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th January, 1994

S.O. 520.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on 24-1-1994.

[No. L-12012/345/86-D.II(A)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 45/87

J. K. Behl Vs. State Bank of Patiala
For the workman—Shri Tek Chand Sharma.
For the Management—Shri P. S. Arora.

AWARD

Central Government vide Gazette Notification No. L-12012/345/86-D.II (A) dated 26th June, 1987 issued U/S 10(1)(d) of I. D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of Patiala in relation to their Gill Road Branch, in dismissing Shri J. K. Behal w.e.f. 6-1-86 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. Brief facts of the case that the petitioner an employee of the respondent bank was placed under suspension and ultimately dismissed from service on 6-1-1986 on the charge that he fraudulently obtained blank debit slip, deposit slip in the name of Teja Singh saving bank holder (S.B. Account No. 1705 L/F 78/13) subsequently converted the debit slip into the debit voucher for Rs. 8000 withdrawing the amount of said saving bank account on the basis of special term deposit voucher, opening a special term deposit account No. 478-S in the name of Teja Singh by forging his signatures in English on the document viz. relative term deposit pay-in-slip, speciman signature card and term deposit account opening form and thereafter received the payment of said special term deposit account by putting the signatures of said Teja Singh on the back of the relative special term deposit receipt. The grievance of the petitioner that the dismissal order has been passed against him is illegal and bad in law on the ground that the charge sheet was wrong and fabricated. His reply to the charge sheet was not considered by the competent authority. Appointment of the enquiry officer was not proper. He was allowed to be defended by T. C. Sharma in the enquiry by the enquiry officer Mr. M. R. Aggarwal and upon his death the subsequent enquiry officer Mr. M. D. Sharma did not allow him to be defended by the said T. C. Sharma. He was only allowed to be defended only on the intervention of the ALC (C), Chandigarh. His further grievance is that he was not allowed to examine the documents. The enquiry officer did not record the proceedings in accordance with the procedure. Defence witnesses called were not allowed by the enquiry officer and evidence of one G. K. Supra was not allowed though his name was given as one of the defence witness Enquiry Officer was biased having under the direct administrative control of the charge sheeting authority. His confession dated 4-2-1982 was obtained under coercion and not entered in the dak register of the branch. The disciplinary authority did not apply its mind to the facts of the case and he did not considered the reply filed by him. Dismissal order is passed in violation of the settled law. The enquiry officer has not considered evidence of the management's witnesses. The disciplinary authority was not competent to inflict the punishment because the appointment of the disciplinary authority was not made in accordance with the provisions of law. He was not given opportunity to defend himself and personal hearing was not given. Thus he sought the reinstatement with full back wages and continuity of service.

3. The management in their written statement denied the allegations made by the petitioner in his statemen of claim. The stand of the management that the enquiry officer was appointed as per the provisions of the Bipartite Settlement. The reply of the petitioner dated 1-9-1982 to the charge sheet was duly considered. The appointment of the enquiry officer Mr. M. R. Aggarwal (since expired) was made by the General Manager (operation) the comptent authority to make the said appointment. The said enquiry officer duly allowed the petitioner to be defended by T. C. Sharma Vice President of State Bank of Patiala Employees National Union subject to the condition that the petitioner would prove that he is a member of the said Union. Upon the expiry of the enquiry officer the subsequent enquiry officer Mr. M. D. Sharma asked the petitioner to produce the proof that he is the member of the National Union. The petitioner did not

submit any proof during the enquiry proceedings on 25-8-1982 27-8-82 and 20-9-1982. The petitioner, in the meanwhile was allowed to be defended by another representative Mr. V. K. Mittal who was the General Secretary of the Union till said T. C. Sharma was allowed to defend the petitioner on the direction of ALC(C), Chandigarh. During the said period four witnesses were examined with the consent of the petitioner which is evident from the facts that they were duly cross-examined by the petitioner. The petitioner was allowed to persued|taken notes of the documents relied upon by the bank as confirmed by the petitioner in his letter dated 25-8-1982. Further plea of the management that G. K. Supra could not come to depose due to his illness despite being given ample opportunity to depose. The petitioner and his representative during the course of the proceedings held on 14-9-1985 themselves considered presence of Shri Supra not necessary. The petitioner had confessed his guilt in his letter dated 4-2-1982. The plea that the confession was got signed under coercion was never taken by the petitioner during the course of the enquiry. The non-entering the letter dated 4-2-1982 in the duk register does not make the letter as illegal. Further stand of the management that Teja Singh deposed at the enquiry that Dharam Pal Gupta got signed from him the debit slip, this gets negativated as he had confessed on seeing the impugned debit slip on the basis of whom the fraud occurred that same was not got signed from him by Mr. D. P. Gupta. The ample opportunity was given to the petitioner during the course of the enquiry and thereafter by the disciplinary authority including the personal hearing. The submission made by the petitioner during the personal hearing on 6-1-1986 was duly considered by the disciplinary authority. The dismissal order passed by the disciplinary authority is in accordance with the provsions of Bipartite Settlement. Thus the management sought the dismissal of this reference.

4. MW-1 S. S. Pandey Regional Manager State Bank of Patiala is the management's witness. He filed his affidavit Ex. M-1 in evidence. He also relied on the document Ex. M-2 the charge sheet, Ex. M-3 the reply to the charge sheet, Ex. M-4 findings of the enquiry officer, Ex. M-5 the show cause notice, Ex. M-6 reply to the show cause notice, Ex. M-7 the order dated 5-2-1987 passed in appeal. The petitioner filed his affidavit Ex. W-1 in evidence. The management also placed some documents in persuance of the application of the petitioner for the production of documents. The respective parties closed their evidence.

5. I have heard both the parties, gone through the evidence and record.

6. Main stress in the arguments made by the representative of the workman that the petitioner was not afforded reasonable opportunity to represent his case and enquiry officer was biased. The petitioner was not allowed to defend his case by Mr. T. C. Sharma. The confession of the petitioner was got recorded under coercion. The contentions raised by the representative of the petitioner is meritless. It is settled principle of law that enquiry can not be said to have properly held unless employee proceeded against has been informed clearly of the charges levelled against him. (ii) the witnesses are examined in the presence of the employee in respect of the charges. (iii) employee is given fair opportunity to cross-examine the witnesses, (iv) he is also given fair opportunity to examine witnesses including himself in his defence if he so wishes on any relevant matter and (v) enquiry officer records his findings with reasons for the same in his report.

Ex. M-2 the charge sheet. Ex. M-4 is the findings of the enquiry officer placed on the record by the management. undoubtedly the management of a concern has powers to direct its own internal administration and discipline but the powers are not unlimited and when dispute arises. The Tribunal has given the powers to see whether the termination of service of workman is justified and to give proper relief. In case of dismissal or misconduct the Tribunal does not ever act as a Court of appeal and substitutes its own judgement for that of management. In the instant case Ex. M-2 is the charge sheet. This contains all the relevant particulars which is basis of the charge enabling the petitioner to know what he is charged with in order to defend himself properly. The representative of the petitionr points out that the petitioner was not allowed to be defended by Mr. T. C. Sharma and a great prejudice has been caused to the petitioner. This plea can not be accepted. Initially the enquiry officer Mr. M. R. Aggarwal had allowed the petitioner to be defended by Mr. T. C. Sharma who was then the Vice President of State Bank of Patiala Employees National Union, subject to the condition that the petitioner will produce the proof of his being the member of the said Union. Upon the death of said enquiry officer and subsequently the appointment of M.D. Sharma was not allowed to defend the petitioner. No pre-proof of his being the member of the said Union. It is only when the petitioner did not submit any proof said Mr. T. C. Sharma was not allowed to defend the petitioner. No prejudice has been caused to the petitioner as the petitioner was allowed to be defended by another representative Mr. V. K. Mittal who was also the General Secretary of the said Union till Mr. T. C. Sharma was allowed to defend the petitioner on the intervention of the ALC(C), Chandigarh. The management had produced as many as 10 witnesses. All of them had duly cross-examined either by the petitioner or his representative Mr. V. K. Mittal General Secretary of the National Union and subsequently by Mr. T. C. Sharma. The petitioner has no where shown that prior to the induction of T. C. Sharma as a representative of the petitioner the cross-examination done by the petitioner or by Mr. V. K. Mittal was not adquate. Therefore, there is no question of having caused any prejudice to the petitioner on the point of late induction of Mr. T. C. Sharma as representative of the petitioner.

7. Another plea raised by the representative of the petitioner that the enquiry officer had ignored the evidence of Teja Singh who had deposed that the deposit slip were filled by D. P. Gupta and therefore, the petitioner has no hand in forging the signatures of said Teja Singh. This plea is again meritless on account of his own admission and as well the report of the handwriting experts submitted during the course of enquiry. Ex. M-3 is the reply to the charge sheet submitted by the petitioner. The relevant portion is important to be reproduced :

> "The manager had, however, once called me to fill in certain vouchers in his cabin as per usual practice at the branch and gave me a set for opening of a new account. I was asked by the Manager to write the name of depositor in English in appropriate columns and advised me that he will get the signature of depositors, who used to sign in Punjabi appropriately. It is unfortunate and intriguing that the said name of the depositor put by me in English is being made as a forged signatures".

Further as reflected in the findings of the enquiry officer Ex. M-4 the report of the handwriting expert Ex. P-23 (in the enquiry) that the handwriting of the petitioner and the writing of the petitioner on account opening form, specimen signature card pay-in-slip and debit vouchers does tally The plea that the said writing was got written under coercion at the instance of the branch manager can not be accepted being petitioner the senior employee must be fully aware of the implication of forging the signatures of some other person and it can not be expected that he would forge the signatures of other person at the instance of other person when inmplications or consequences are apparent.

8. Another feature in this case is the admission of the petitioner himself admitting his guilt. His admission dated 4-2-1982 has been placed on the record duly witnessed by S. S. Bahmi, Jagdeep Singh and S. C. Sarin who were also produced during the course of enquiry duly cross-examined by the petitioner in which he admitted his guilt stating that he signed the debit slip and used that debit slip for a special term deposit for Rs. 8000 in the name of Teja Singh. In the meantime his family circumstances become worse and he needed money and he got premature payment. He also says that he regret what has happened. He also stated that he had already deposited the amount in the saving bank account of Teja Singh the depositor. The plea of the petitioner is that the said confession was got written under force and coercion. This plea is again can not be accepted for the simple reason that if at all the petitioner had not involved himself in the said affair there were certainly no compelling circumstances and reasons for him to give the said confession. This confession is in clear terms and can not be said to be under coercion especially when it is being witnessed by the other employees of the bank.

9. Another plea raised by the petitioner that the enquiry officer did not act impartially being under the direct administrative control of charge sheeted authority. This plea is

again meritless in view of the settled law that the mere fac that the enquiry officer is an employee of the management can not lead to the assumption that he was bound to decide the case in favour of the management and biased to decide the case in favour of the management. Likewise the fact that the enquiry officer was subordinate to the disciplinary authority would be no ground for holding that be acted mala fide and had biased against the delinquent employee. Thus in the absence of an any special bias attributable to a particular officer it can never he held that the enquiry is bad just because it is conducted by an officer of the employer.

10. Another plea raised by the representative of the petitioner that the enquiry has not been conducted in accordance with law. This plea is again not accepted. The domestic enquiry need not to be conducted in accordance with the technical requirement of criminal trial. However they must be fairly conducted. consideration of fair play and natural justice and the same has been done in this case. Merely breach of bare technicalities can not equated with violation of the principle of natural justice. Ex. W-4 is the enquiry report. Every date and the sequence has been there in the said report which consist of 15 pages. The petitioner in his cross-examination has admitted that the regular enquiry was held against him. He participated in all the proceedings. He also admitttd that he had cross-examined all the management's witnesses. He was supplied the documents before the starting of the enquiry. He also admitted that the enquiry proceedings were duly recorded in the register and his signatures were obtained on the same. However after perusing the report of the enquiry officer the same is speaking order. The order of the disciplinary authority has also been passed after application of mind. The petitioner has not shown any where that in what way he has been prejudiced Ex. M-7 is the order of appellate authority rejecting his appeal wherein it is clearly stipulated that the petitioner was also given personal hearing on 6-11-1986 before rejecting of his appeal. The appointment of the enquiry officer was duly done by the General Manager (Operation) who is also the appellate authority. Therefore, it can be held that the enquiry has been conducted in all fairness and the workman has been given adequate oppirtunity to defend his case.

11. In view of the discussions made in the earlier paras, the action of the respondent bank in dismissing from service I. K. Behl is fully justified and workman is not entitled to any relief whatsoever.

Chandigarh,

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

का.आ. 521 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, उसे दिनांक 25-1-94 को प्राप्त इन्डियन आईल ब्लेन्डिंग लिमिटेड प्रबंधन के संबंध में उनके कर्मकारों और नियोक्ताओं के बीच हुये औद्योगिक विवाद के संबंध में अनुबंध में यथोक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय नं. 1, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है ।

[सं. एल-30012/27/89-आई.आर (विविध)]
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th January, 1994

S.O. 521.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, cum Labour Court No 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Oil Blending Ltd, and their workmen, which was received by the Central Government on 25-1-1994.

[No. L-30012/27/89-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL NO. 1, BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presidng Officer.
REFERENCE NO. CGIT-22 OF 1990

PARTIES :

Employers n relation to the management of Indian Oil Blending Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management : Shri Pota, Advocate
For the Workman : No appearance

INDUSTRY : Oil & Natural Gas STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 7th day of January, 1994

AWARD

By letter 30th March, 1990 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi has made the following reference for adjudication under section 10(1)(d) read with 2A of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Indian Oil Blending Ltd. in not regularising the services of Shri Mohd. Adam Karim Shaikh, Casual Labour, and terminating his services with effect from December 1983 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The case of the workman is that he was employed as a Casual Labour, has put in 16 years of service and last wages drawn by him were Rs. 600 per month. He further states that when he was sent for medical examination in 1978 for absorbing him in regular employment he was found medically fit. He continued to work as Badli worker till 1983, thereafter fell ill, could not attend to his duty. He was orally told in April 1984 when he went to report for work after recovering from his illness that he would be called for work as and when vacancy arose. In spite of that he has not been given work eventhough there was a vacancy. He states that he had completed 240 days work eligible for permanency. H was not given any opportunity to showcause before his services were terminated or before his name was struck out from the list of Badli/Casual workman.

3. He states that it is a case of illegal termination and therefore, he approached Regional Labour Commissioner and as the conciliation failed dispute is referred. According to him management failed to follow proper procedure before terminating his services and therefore, termination order should be set aside and he be reinstated with full back wages.

4. Reply of the management is filed and allegations that his services were terminated have been denied. It is contended that the management has to appoint casual labourers from 78 to 79 a pool of casual labourers was created. There is the employees who gathered at the gate of the plant wre picked up by the management for work depending upon the requirement of the Company. The managment states that the workman Shri Shaikh has never completed 240 days of service as the statement showing the number of days' work put in by him is annexed to written statement. The management stated that during the years 1983 and 1984 he reported for work only for 75 days and for one day in December 1983 an thereafter he stopped altogether till 11-8-1987. Same time in 1985, 19 vacancies arose for the post of labourers in the plant and the Company absorbed 19 in the regular employment from amongst the 45 in the pool, the claimant was not in the pool as he had stopped reporting during the year 1984. Remaining 26 who were not regularised approached through General Employees Association Bombay Regional Labour Commissioner and the Company ultimately absorbed 19 and gave up practice to employ casual labourers. Then the workman reported on 11-8-1987 for regularisation and he could not be regularised as those who were in the pool, 19 from 45 were absorbed and there was

no vacancy for him. Practice of employing casual labourers was already discontinued. It is denied that he is employed for 16 years and last salary was Rs. 600 per month. In fact labourers were engaged only in 1978 and they were paid Rs. 13.50 per day and from 1982 they were paid Rs. 17.50 per day for 8 hours work. It is denied that he was a Badli worker. Further denied that his services were terminated, contention is of his own record he stopped coming for work.

5. The Company has thus prayed for rejection of his claim. It is to be mentioned that objection has been raised on the ground that it is not an 'Industrial Dispute' within the meaning of section 2(k) of the Industrial Disputes Act. It is also contended that there has been considerable delay on the part of the workman in approaching the Labour Commissioner.

6. The workman was initially served the notices of this reference. He appeared through counsel and filed his statement of claim. He also applied for and sought time for producing documents. However, thereafter he ceased to appear and so also his counsel. He was given fresh notice of hearing of matter, that did not succeed as the registered packet was returned by the Postal Authorities 'unserved' and one having been returned with an endorsement 'Party out of India'. Others were returned with the endorsement 'not found'. In view of this there was no alternative but to proceed ex-parte.

7. On behalf of the management affidavit has been filed by Shri Nair, who is the Deputy Manager (Admn.) of the Company.

8. It is stated by him in the affidavit that the workman was engaged as one of the casual labourers since 1978-79 and at no point of time he completed 240 days in a year. It is further stated that in 1983-84 he worked for 75 days and for only one day in December 1983 and thereafter stopped coming till 11-8-1987. According to him he could not pray for a claim to be absorbed or regularised. In fact, according to him the exercise was made of absorbing some workman out of the pool in 1984 and with the remaining who were not absorbed, approached Regional Labour Commissioner for regularisation, and their services were regularised by settlement dated 18-7-1987. The claimant was not one of them. He applied on 11-8-1987 since right from December 1984 till the date of settlement on 18-7-1987, he did not approach, he could not be regularised and thereafter the Company has discontinued the practice of engaging casual labour employees. Thus the workman's claim for regularisation in my opinion could not have been acceded to by the Company nor could get that relief in these proceedings.

9. Statement Annexure-I clearly shows that at no point of time he has put in 240 days of work in a year. He discontinued coming in 1984 and for that year also attendance is of 75 days. I therefore, find that he is not entitled to the relief on the ground that he has been retrenched and in violation of section 25F of the Industrial Disputes Act.

10. Question of any enquiry does not arise because this is not a case of termination. The management has not inflicted any penalty.

11. There is undoubtedly delay in approaching the Regional Labour Commissioner. Right from 1984 till 1987 he did nothing. However, this is not the ground on which I am disallowing him relief.

12. In view of all this in the absence of any foundation for the claim made by the workman, the reference would have to be rejected and award will have to be passed accordingly. Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

का.आ. 522.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उसे दिनांक 25-1-94 को प्राप्त बम्बई पोर्ट ट्रस्ट प्रबंधन के संबंध में उनके कर्मकारों और नियोक्ताओं के बीच हुये औद्योगिक विवाद के संबंध में अनुबंध में यथोक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय नं. 1, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-31012/8/91-आई.आर (विविध)]
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th January, 1994

S.O. 522.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on 25-1-1994.

[No. L-31012/8/91-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-40 of 1992

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bombay Port Trust.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management : Shri Nargolkar, Advocate
For the Workman : Shri Patankar, Advocate.

INDUSTRY : Ports & Docks. STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 7th day of January, 1994

AWARD

The following reference has been made by Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, by letter dated 28th May, 1992, under section 10(1)(d) read with 2A of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication :

"Whether the action of the management of Bombay Port Trust, Bombay in refusing to change the Date of Birth from 1st July, 1932 to 25th May, 1935 based on School Leaving Certificate of Shri N. B. Patil, Fitter DPL, ID in Chief Mechanical Engineer, Deptt. and retiring him from services from June 1990 instead of June 1993 is just and proper ? If not, to what relief is the workman entitled to ?"

2. Statement of claim has been filed by the workman, and it is stated that he was appointed as a Casual Mazdoor on 8th December, 1953 by the Bombay Port Trust. At the time of the appointment he was referred to the Medical Officer for ascertaining his age and Medical Officer certified his date of birth as 1-7-1932 on a medical examination. That was recorded in the official records of the employee. In 1974 the employee applied for change of date of birth from 1st July, 1932 to 15th July, 1934 and produced in support a School Leaving Certificate and extract of birth register maintained by Tahsildar, Alibag. His request was rejected by letter dated 7th September, 1979. He again applied by letter dated 23rd October 1982 for the same purpose and he brought it to the Notice of the employer that the date of birth recorded by the Tahsildar was on the basis of entry made immediately after the birth and therefore, is likely to be correct as against the entry in the School Leaving Certificate made on the basis of information given to the School

Authorities at a much later date. This request was rejected on the ground that there was discrepancy in the dates given in School Leaving Certificate and birth register maintained by the Tahsildar.

3. He raised a dispute before the Conciliation Officer and requested the employer not to retire him in July 1990 on the basis of the birth date recorded in the official record. However, his request was rejected and he was retired in July 1990. It is in these circmstances that he prayed for the relief of correction of entry in the record of date of birth on the basis of birth date in Revenue Record cancel the order of retirement and pay him wages.

4. The management of Bombay Port Trust under the signature of the Secretary for the Board of Trustees of the Port of Bombay filed written statement. The contention raised on behalf of the management is that the date of birth was recorded at the time of his entry in service. He was referred for medical examination, as the workman did not produce any documentary evidence regarding his date of birth. It is contented that fora period of 21 years the employee did not raise any dispute. When he did so in the year 1974 by letter dated 26-11-1974 on the basis of School Leaving Certificate and the birth record of Tahsildar it was found that they did not tally. His application was therefore, rejected on considering the documents produced and inordinate delay in making request. This was in the year 1979. Again he applied in 1982 and it was rejected on the ground that it was barred and the workman failed to produce fresh sufficient, and reliable evidence in support of his contention by the letter dated 17-11-1984. As the workman was due to retire on the basis of the entry in the record of his birth date he retired on 1-7-1990.

5. The employer has further contended that in 1954 a circular was issued that every workman then in services should apply in writing for a change of date of birth recorded in his record within 3 months of the issue of the circular accompanied by documentary evidence. It was clearly stated that request made after a period of 3 months would not be entertained and would be treated as time-barred. In spite of this the employees and unions kept on making applications and therefore in the year 1959 an Arbitration Award dated 10-9-1959 was passed based on the agreement between the parties. It was provided that if any employee applies for rectification of the recorded date of birth by producing fresh evidence to the satisfaction of the Bombay Port Trust the same would be decided on merits provided he makes such application within 3 weeks on his becoming aware of the fresh evidence. It was also stipulated that it was subject to the satisfaction of the employer by the employee that the fresh evidence was not previously within his knowledge and that the same was not available notwithstanding exercise of due diligence. In 1973 further agreement was reached that if an application of any employee duly supported by a birth register extract or a School Leaving Certificate was received 6 months prior to the date of retirement, it would be entertained and examined after necessary verification with the concerned authorities.

6. The employer stated that in view of the policy requirements and time limits prescribed then the employer examined the application of present workman dated 26-11-1974 and the necessary verifications were carried out. The Deputy Chairman rejected the application in January 1982 on the ground that it was time barred and also because of the discrepancies. Similarly, the application dated 23-10-1982 also came to be rejected on the ground of discripancies. It is submitted that the workman has been properly retired on the basis of recorded date of birth.

7. There is one more contention regarding wrong joinder of Deputy Docks Manager and the Chairman of the employer as parties in the statement of claim. It is contended Board of Trustees is the employer.

8. It is pleaded that the workman has received retiremental benefits fully and nothing more is payable to him. Contention raised is that the medical examination was found necessary to ascertain age of the workman who were unable to produce any proof of their date of birth and in number of cases the date of birth co-incidentally tallied as per the medical opinion. Prayer for rejection of request is made.

9. On behalf of the workman, Shri Patankar, learned Advocate advanced oral arguments while written arguments have been submitted by management. Reliance has been placed on reported decision of Bombay High Court in Writ Petition No. 414 of 1985. Documentary evidence has also been adduced.

10. From the rival versions stated in the statement of claim and in the written statement it is undisputed that the workman joined Bombay Port Trust as the Casual Mazdoor on 8th December, 1953 and retired on 1st July, 1990 on reaching the age of 58 years. It is further an admitted fact that at the time of his entry in service, no documentary evidence of date of birth was adduced and he was examined by the Medical Officer and on the basis of the certificate issued his date of birth was recorded as 1st July, 1932. He made request for change of date of birth in 1974 and thereafter in 1982. His request was accompanied by the extract of birth and death register of village Kurkandi Cole Tembli, Taluka Alibag and School Leaving Certificate issued by the Principal of Dongri Municipal Marathi School. The management has verified the certificates issued and it is found that both the certificates are genuine. The Principal of the School to whom reference has been made by letter dated 31st July, 1974 certified that the applicant's date of birth was 15-7-1934 and that was in response to the letter of the Chief Mechanical Engineer, Bombay Port Trust dated 5-7-1978. Tahsildar also in reply to Management's letter dated 14-7-1978 replied by letter dated 2-5-1979 that date of birth was verified and it was found to be 25-5-1935 and the document produced by Shri Narayan Patil is correct. That 1st request was rejected by letter dated 7-9-1979 and the management states that it was rejected on the ground that there was inordinate delay and the flagrant conflicting discrepanies in the two documents. He was communicated the decision. The workman again applied 23-10-82 and for the same purpose and that was rejected on 17-11-1984 on merits. It is to be noted that the circular has been issued on 13-9-1954 calling upon the employees to apply for any change of date of birth if they were of the view that the date recorded was not correct and that they would do so within 3 months with proper documentary evidence. It is also to be noted that on the basis of agreement reached an Arbitration Award dated 10-9-1959 was passed and under the Award the employees had a right to apply for rectification of the recorded date of birth by producing fresh evidence. This was to be done within 3 weeks of his becoming aware of fresh evidence. The management states that thereafter in the year 1973 a further agreement was reached with the union that if an application of any employee duly supported by a birth registry extract or a School Leaving Certificate was received 6 months prior to the applicant's date of retirement, it would be entertained and examined after necessary verification with the concerned authorities. Therefore, the time factor was not so very material and even if the application was received 6 months prior to the date of retirement it was expected to be entertained and examined. Considered from his point rejecting the applicant's application for change of date of birth on the ground that it was delayed or not made within prescribed time could not be justified.

11. The next ground on which it is rejected is that there were discrepancies in the two documents produced. The workman in this case has addressed communication to the management on 5th November, 1979 stating the date of birth recorded in School Leaving Certificate was not correct and the one recorded in this birth certificate issued by the Tahsildar was correct and may be accepted. He mentioned therein the reason for preferring extract of birth register to the School Leaving Certificate by stating that the parents might have given such a date to the School Authorities to serve the purpose of getting admission in the School. He makes another request in 1982 for the same purpose and mentioned facts and requested the management to record the date of birth as per birth and death register extract. According to him that is made immediately after the birth of a child by the Police Patil of the village and therefore, likely to be more authentic. This was rejected and for the same reasons namely that there were discripancies. Discrepancies in fact in the two dates of birth recorded in the two different documents was not disputed. The point was which was to be preferred and the management instead of assigning reasons for accepting one of the other rejected request of workman on the ground that there were discrepancies. Management preferred to act

upon the date of birth recorded on the basis of medical examination at the time of entry in the service.

12. In this connection the learned counsel for the workman has heavily relied upon a decision of Bombay High Court in Writ Petition No. 414 of 1985. The same point arose for consideration in that petition, the date of birth recorded on the basis of medical examination was preferred to the date of birth recorded in the School Leaving Certificate and one of the grounds for rejecting it was delay in making that request. The High Court while dealing with this aspect disapproved in strongest possible words this part of the reasoning for rejecting the same. The High Court also dealt with the correctness of the managements action in relying upon the date of birth recorded on the basis of medical examination. It has been observed that Medical Officer can at the most speak about the age of a person on the basis of examination. can never speak of the date of birth solely on the basis of medical examination. The High Court also noted that hundreds of persons had the same date of birth recorded in the register in the records of the employee. The High Court pointed out the earlier decisions rendered by the same High Court and also by the Supreme Court on the point and criticised the management's action for adopting the same attitude in spite of the decision.

13. It is true that there is a discrepancy in the date of birth recorded in the birth and death extract and School Leaving Certificate, but in this judgement the High Court has made reference to another decision in Writ Petition No. 1519 of 1982 in the case of Gangaram Tatoo Bansode Vs. Trustees of Bombay Port Trust and another, Hon'ble Mr. Justice Kordukar, struck down the order of the Bombay Port Trust retiring the petitioner therein with effect from 30th June, 1982 and directing the Bombay Port Trust Authorities to give all the benefits as permissible in law, had he not retired on 30th June, 1987. The fact in this present case are similar to those in the case of Gangaram Tatoo Bansode. The management has acted on the date of birth recorded on the basis of medical examination and his claim was rejected on the ground that there was a discrepancy regarding the date of birth in the two documents of School Leaving Certificate and birth extract of village record. Curiously enough that was also on the basis of medical examination date of birth was recorded as 1st July, 1924. The magic of this date of 1st July is difficult to understand as in that case also in respect of and large number of employees same date of birth 1st July was recorded as the date of birth of the employee At any rate, it is therefore, seen that the authorities instead of acting upon the documents produced and considering the case of the applicant has rejected both the documents on the ground that there was descripancy which according to him was not right. In view of the decision referred to of the High Court in Writ Petition No. 414 of 1985 rendered on 18th July, 1989 which I respectfully follow I hold that the rejection was wrong. I hold date of birth recorded in the record of Bombay Port Trust ought to have been changed and the same should have been changed to 25-5-1935 as recorded in the birth and death extract register. He might not have been retired on 1st July, 1990. the age of retirement is 58 years and there is no dispute on this point. On the basis of date of birth as recorded in the village record he would have retired on 25-5-1993. The workman is entitled to all the benefits which he would have got had he continued in service till that day.

14. There is no merit in the contention that some wrong parties have been joined at No. 2 and 3 in the application and therefore, application is liable to be rejected. Bombay Port Trust is the employer and has been joined. Notice has been issued to the Bombay Port Trust, the Secretary for the Board of Trustees of the Port of Bombay, Shri Apte has filed the written statement.

15. I therefore, find that the action of the management in rejecting the request to change the date of birth from 1st July, 1932 to 25th May, 1935 was not correct. Here I may state that there is slight error in the frame of schedule where in instead of mentioning the birth and death register extract School Leaving Certificate is mentioned. That error is required to be ignored. The retirement made from June 1990 instead of 1993 is not just and proper. He is entitled to all the benefits of services as if he had continued in service upto the end of June 1993.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

का.आ. 523:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, उसे दिनांक 25-1-94 को प्राप्त बम्बई पोर्ट ट्रस्ट प्रबंधन के संबंध में उनके कर्मकारों और नियोक्तागों के बीच हुये औद्योगिक विवाद के संबंध में अनुबंध में यथोक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय नं.-1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-31011/22/90-आई.आर (विविध)]
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th January, 1994

S.O. 523.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Cum Labour Court No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on 25-1-94

[No. I-31011/22/90-IR (Misc)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

PRESENT: Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer

Reference No. CGIT-28 of 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bombay Port Trust

AND

Their Workmen

APPEARANCES.—

For the Management—Shri M. B. Anchan, Advocate.
For the Workmen—Shri Jayaprakash Sawant

INDUSTRY : Ports & Docks STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 12th day of January, 1994

AWARD

The following reference has been made by Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by letter dated 27-3-1991 referring the following issue for adjudication under section 10(1(d) read with 2A of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the management of Bombay Port Trust, Bombay, were justified in dismissing from service of Shri T. K. Bandkar, Rivetting Mazdoor in Chief Mechanical Engineer Office for a mere loss of Photo Identity Card? If not, to what relief is the workman entitled to ?"

2. Statement of claim has been filed on behalf of the workman by the Secretary, B.P.T. Employees' Union, Kamgar Sadan, Mazgaon, Bombay. It is stated that Shri Bandkar, has been dismissed with effect from 28-8-1989. The charge was misconduct of gross negligence by frequently lossing photo identity cards. It is stated that loss of photo identity cards does not constitute a mis-conduct as it has not been so

specified. The union contends that unless either in the certified standing order or in the service regulations duly framed an act or omission is prescribed as mis-conduct, it is not open to the employer to fish out some conduct as mis-conduct and punish the workman. It is further contended that the loss of identity cards on account of certain reasons cannot amount to negligence or work. It is also stated that for a mere loss of photo identity card penalty of dismissal from service was unjustified. He claims reinstatement of Shri Bandkar, with full back wages, consequential benefits and compensation.

3. The management filed written statement and contended that Shri Bandkar had a bad service record and was very negligent in taking care of the photo identity cards issued to him from time to time between the period 5-4-1966 to 4-7-1986 he had lost identity cards on 9 occasions, for which he was warned verbally as well as in writing. On the 10th occasion while warning him he was told that severe disciplinary action will be taken against him if he failed to preserve the identity card. Inspite of it the new identity card issued to him was lost on the very same day that is 5-7-1986. The enquiry was decided to be held and committee constituted and he was chargesheeted and called upon to explain. His explanation was unsatisfactory and therefore. Enquiry officer was appointed and after a fair and proper enquiry, the Enquiry Officer Mrs. Rane held him guilty and Disciplinary Authority agreeing with the findings and issued an order of dismissal after giving him show cause notice. The workman's explanation was not satisfactory and considering his past record, order of dismissal was passed. His appeal was also dismissed.

4. It is further contended that the action of management was justified because it was a case of habitual negligence or neglect of work and past record justified the panalty imposed. It amounted to misconduct under Rule 22(2)(i) & (s) of the B.P.T. Rules and Regulations for non-scheduled staff. It is pleaded that there is every justification for the action and prayed for rejecting the reference made.

5. In fact, the wording of the schedule indicates that the point referred is with regard to the action of dismissing Shri Bandkar for a mere loss of photo identity card is justified.

6. The management has justified the action on the ground that this was 11th occasion on which he had lost his photo identity cards. On the previous 9 occasions he was warned orally and in writing for the same lapse. On the 10th occasion he was told that severe action would be taken against him for loss of identity cards and yet on the very same day he lost new identity card necessitating a departmental enquiry. The importance of the photo identity card lies in the fact that it provides access to the sensitive areas and misuse of the same by unscrupulous element. In my opinion it is not a case of mere loss on one occasion but it is a case of habitual negligence on the part of Shri Bandkar. One cannot conceive of a case where such a photo identity card is lost on so many occasions. It is also difficult to say that in that event the penalty is unjustified.

7. It is then urged that it does not amount to 'misconduct' because it is not so prescribed. Reference has been made to section 22(2) which mentions habitual negligence or neglect of work as one of the grounds justifying suspension, demotion and/or reduction in grade, removal or dismissal without notice or payment of any compensation in lieu of notice. To say that unability to preserve photo identity card is not a case of negligence would not be correct. To say that losing it on 11 occasions is not a case of habitual negligence would much less be correct. Reliance on 1985 (i)LLJ p. 527 is, with respect, not correct and so is reliance on 1989 (I) LLJ page 573.

8. It is then urged that this is not a neglect inasmuch that he was not negligent in his work and it has been so admitted by a witness presented on behalf of the management. It is true that the witness examined before the enquiry officer Shri Mahadik, PW No. 2 stated in the course of cross-examination that it was true that there was no complaint regarding the work in the sections. Submission therefore was that he was not negligent in work. It has to be noted that there are two separate classes in Rule 22(2)(i) habitual negligence is one, neglect of work is another. The charge against Shri Bundkar falls in the first category namely habitual negligence and therefore, this arguments is not tenable.

9. During the course of arguments on behalf of the union a contention is sought to be raised that Shri Bandkar does not belong to the category of non-scheduled staff and therefore, rules and regulations for non-scheduled staff which were applied to him were not applicable. Submissions is sought to be supported by production of photostat copy of extract of section 23 of Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) with part of schedule. It shows Rivetting Mazdoor as one of the catogry of employees and therefore, he is an employee belonging to the scheduled employees and therefore, not a non-schedule employee regulated by B.P.T. Rules and Regulations for non-schedule staff. I find this particular aspect of the argument has been raised after the arguments were concluded. It has not been raised during the departmental enquiry nor in the appeal presented against order of dismissal. It is also not raised in the statement of claim. To allow it to be raised at this stage would not be proper. Under the circumstances, I do not find that the action of the management is unjustified and in that event Shri Bandkar is not entitled to any relief. Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

का.आ. 524 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उसे, दिनांक 25-1-94 को प्राप्त मैसर्स हिल, सन एण्ड दिनशा लिमिटेड प्रबंधन के संबंध में उनके कर्मकारों और नियोक्ताओं के बीच हुये औद्योगिक विवाद के संबंध में अनुबंध में यथोक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय नं.-1, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-31012/39/92-आई आर (विविध)]
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th January, 1994

S.O. 524.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Cum Labour Court No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Hill, Son & Dinshaw Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 25-1-1994.

[No. L-31012/39/92-IR(Misc)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

PRESENT: Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer

Reference No. : CGIT-1/58 of 1993

PARTIES :

The Employers in relation to the Management of Messrs. Hill, Son & Dinshaw Ltd. Bombay,

AND

Their Workmen

APPEARANCES.—

For the Employer—No appearance.

For the Workman—No appearance.

INDUSTRY : Port and Dock STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 12th day of January, 1994

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, has by letter dated 06-09-1993, made the following reference to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the Management of Mrs. Hill, Son & Dinshaw Ltd., Stevedore in dismissing from service of Shri Kunjilal Sahadev Varma, Gearman w.e.f. 21-1-1992 for remaining absent on medical ground from 8-7-1991 to 1-8-1991 is just, proper and legal? If not, to what relief is the workman entitled to."

2. After receipt of this reference, notices have been sent to the Company as well as to the Union, and they have been duly served with the same. Today, there is no appearance on behalf of the parties, no statement of claim has been filed.

3. A copy of the letter addressed to the Desk Officer. Shri Unni, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by the Chief Executive of M. s. Hill, Son and Dinshaw Ltd, accompanied by a copy of the Memorandum of Settlement dated 09-03-1993 has been sent to the office of this Tribunal. It appears from the letter and the Memorandum of Settlement that the dispute has been settled by the parties and it is not required to be adjudicated upon. It appears that for this very same reason, there is no statement of claim filed, nor is there any appearance on behalf of the Union. In the circumstances, the reference is disposed off and award is accordingly made.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

का.आ. 525 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, उड़ीसा (भुवनेश्वर) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/88/87-डी-II (ए) आईआर (बी-III)]

बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th February, 1994

S.O. 525.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar (Orissa) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner & Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1994.

[No. L-12011/88/87-D.II(A)/IR(B.III)]

B. M. DAVID. Desk Officer

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

PRESENT :

Sri R. K. Dash, LL.B., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 31 of 1991 (Central)

Dated, Bhubaneswar, the 24th January, 1994

BETWEEN

The management of State Bank of Bikaner & Jaipur, Cuttack Branch, Bajrakabati Road, Cuttack. ...First party—management.

AND

Their workmen represented through State Bank of Bikaner & Jaipur Employees' Union, Bangalisahi, P.S. Purighat, Cuttack. ...Second party—workmen.

APPEARANCES :

Sri M. M. Das, Advocate—For the first party—management.

Sri J. Patnaik, Advocate—For the second party—workmen.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon it by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), have referred the following dispute for adjudication by this Tribunal vide their Order No. L-12011/88/87-D.II(A)/IR(B.III) dated 10th September, 1991 :—

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur, Cuttack Branch, in terminating the services of under-mentioned 24 workmen with effect from the dates shown against their name was justified ? If not, to what relief the workmen are entitled to ?"

Sl. No.	Name & Designation	
1.	S. Shri Ashwini Kumar Mohanty, Clerk	22-12-85
2.	Prashanta Kumar Mishra, Clerk	24-08-83
3.	Ramesh Chandra Pradhan, Clerk	06-03-86
4.	Pradipta Kumar Mohanty, Clerk	17-11-82
5.	Miss Rajalaxmi Das. Clerk	24-07-83
6.	Gouri Prasad Das, Clerk	04-07-84
7.	Pradipta Kumar Das, Clerk	17-03-85
8.	Nimai Charan Acharya, Clerk	17-08-82
9.	P. Srinivas, Clerk	21-04-84
10.	Ramesh Chandra Naik, Clerk	23-09-84
11.	Kailash Chandra Barik, Peon	26-05-84
12.	Ananta Charan Behera, Watchman	02-12-84
13.	Sukadev Sahoo, Clerk	14-07-83
14.	Rajkishore Mishra, Clerk	13-06-85
15.	Saroj Kumar Mishra, Clerk	07-01-84
16.	Parthasarathi Das, Clerk	16-03-85
17.	Amiya Mohan Mohanty, Peon	08-03-84
18.	Surya Kumar Das, Clerk	20-05-82
19.	Ajay Kumar Pattnaik, Clerk	14-06-84
20.	Pramatha Kumar Sarangi, Clerk	09-09-82
21.	Rabindranath Lenka, Peon	07-07-83
22.	Basanta Kumar Jena, Clerk	13-06-85
23.	Pravat Kumar Choudhury, Clerk	01-09-85
24.	S. K. Kar Mohapatra, Clerk	02-10-83

2. The aggrieved workmen numbering 24 were the Peons, Watchman and Clerks of Cuttack branch of the State Bank of Bikaner and Jaipur, a subsidiary bank of the State Bank of India. It being a nationalised bank the service conditions applicable to its employees are identical to that of the State Bank employees.

Briefly stated, the case of the aggrieved workmen is that they came to be appointed in their respective post on different dates and were entrusted to do permanent nature of work. Being so engaged they had been discharging their duties with utmost sincerity and to the best satisfaction of their employer. But, suddenly the management without any rhyme or reason illegally terminated them from their services and put an end to their source of livelihood. This action of the management being not as a punishment by way of disciplinary action amounts to retrenchment and therefore, as required under law the management ought to have given them a notice or notice pay, as also compensation but it did not. So, challenging the aforesaid illegal action of the management, the union representing the workmen raised an industrial dispute

which was admitted into conciliation and the same having culminated in failure, a report was made to the Central Government which refused to make a reference. Against such refusal a writ was filed in the High Court which was ultimately allowed with a direction to refer the dispute to this Tribunal. This is how the present case has come-up to this Court for adjudication of the dispute.

The workmen, therefore, have urged that the management's action in terminating their services should be held as illegal and unjustified and they be reinstated with all service benefits and back wages.

3. The case of the management, on the other hand, is that the second party-members were the temporary employees and had been given employment for a specified period, on expiry of which their services automatically stood terminated as provided u/s 2(oo)(bb) of the Industrial Disputes Act, 1947 (for short 'Act'). Its further case is that regular appointment to the posts held by the workmen have been given to the candidates who qualified in the competitive examination held by the Banking Service Recruitment Board. Since these workmen were unsuccessful in the said examination they could not have asked the management to reinstate them as matter of right merely because they had earlier served in the Bank for a specified period. If such a prayer was accepted the meritorious and selected candidates would have been denied of their right to employment. In the circumstance, the management prays that since the claim of the workman merits no consideration, the reference should be answered against them.

4. In course of hearing, both parties have tendered oral evidence and in addition thereto they have brought certain documents into record.

5. As would be seen from the evidence of W.W.1, none of the workman had completed 240 days work in the year when they were terminated from service. The other witness is W.W.2, according to whom the management having done away with the services of the workmen appointed fresh hands as sponsored by the Recruitment Board.

Admittedly, the posts which the second party-workmen were holding were regular posts and while putting an end to their job neither any notice nor notice pay and compensation had been given to them. The lone witness for the management speaks that the appointment of the second party-workmen for a specified period was made under written orders and after expiry of the said period their services were discontinued Copy of such appointment order, if any, has not seen light of the day. The reason for not filing the said order according to MW-4 is that the same is not available in the branch office. The management has absolutely no grievance about the sincerity and efficiency of the workmen. As would be seen from the evidence of MW-1 the scond party-workmen were qualified persons and during their tenure of service they worked to the best satisfaction of the management. In view of such admitted fact, the question emerging for consideration is whether the management was justified in terminating their services.

5. A brief reference to the relevant paras of the Shastri Award applicable to the present case are enumerated below :—

SECTION IV.—Procedure for termination of employment 522 :

(1) xx xx xx

(2) xx xx xx

(3) xx xx xx

(4) The services of any employee other than a permanent employee or probationer may be terminated, and he may leave service, after 14 days' notice. If such an employee leaves service without giving such notice he shall be liable for a week's pay (including all allowances).

(5) An order relating to discharge or termination of service shall be in writing and shall be signed by the manager. A copy of such order shall be supplied to the employee concerned.

(6) xx xx xx

523 :

It is now well settled that in cases where the services of a workman are terminated on grounds of retrenchment some compensation should be payable to him by way of equitable relief. The principle behind it is that the workman is not responsible, in any way, for the loss of his employment. Even where retrenchment is forced upon the management by reason of circumstances beyond their control, it is but just that they should give compensation for involuntary unemployment of their workmen when they have had the benefit of their services in the past. This is now so well established that it has come to be regarded as more or less a self-evident principle. Reference may also be made in this connection to the most recent decision of the Labour Appellate Tribunal reported in 1953(I) Labour Law Journal, 224.

6. No doubt, the workmen were engaged as temporary employees but as provided under the Shastri Award the management while terminating their services ought to have served 14 days notice as well as a copy of the termination order on each of the workman. It is asserted by the management that the termination in question does not fall within the ambit and scope of 'retrenchment' as defined in Section 2(oo) of the Act since the appointment was for a specified period on expiry whereof it automatically stood terminated. To my mind, such a plea has been taken keeping in view the beneficial provision enumerated in sub-clause (bb) to Section 2(oo) of the Act which came into the Statute Book by Act 49 of 1984. I am not inclined to accept such contention because of the reason that if at all appointment of the workmen was contractual, in other words, for a limited period there was no reason why the copy of the appointment order was not searched out and filed which would have thrown some light on the question involved. This apart the nature of duties performed by the workmen being permanent and perennial it was not permissible for the management to resort to a peculiar device of its own to give contractual appointment to the aggrieved workmen.

It stands admitted that the workmen having requisite qualification had been given appointment in their respective post. On being so appointed they discharged their duty with sincerity and their over-all performance was satisfactory. So, they being competent and hard-working employees the management to exert more work ought to have regularised their services so that they would have felt encouraged to be more efficient and duty bound but instead it arbitrarily put an end to their services and threw them out of employment.

7. In view of my discussions made above, I hold the termination of services of the workmen to be illegal and unjustified. So, they be reinstated in service with full back wages and the payment be made within a period of three months from the date of publication of the Award. It is, however, made clear that the management shall absorb them against permanent posts as and when he same will fall vacant or are created, in a phased manner and according to their seniority within a period of one year from the date of publication of the Award.

The reference is thus answered accordingly. Dictated & corrected by me.

R. K. DASH, Presiding Officer

Dated : 24-1-1994

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

का.आ.526 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/311/90-आई आर (बी-II)]

एस.एस. के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th January, 1994

S.O 526.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Goernment hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Cum Labour Court-No. 1 Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 24-1-1994

[No. L-12012/311/90-IR (B-II)]
S. S. K. RAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I. BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar,
Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-17 OF 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of Baroda

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management.—Shri R. S. Pai, Advocate.
For the Workman.—Shri A. P. Kulkarni, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 10th day of January, 1994

AWARD

Following reference has been made by Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by letter dated 12-2-91

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in not promoting Shri S. C. Surti, Daftary to the post of Head Peon w.e.f. 1985 is justified ? If not what relief the concerned workman entitled to ?"

2. Shri Surti, an employee of the Bank of Baroda has been appointed in 1976 on 25th November. Shri Kutty is admittedly senior to him in service while Shri L. S. Supe is junior to Shri Surti. On 2-2-1984 Shri Kutty, who was a Peon working in Dombivli Branch was advised to perform the additional duties of Daftary at Saralgaon Branch, Thane District. Shri Kutty did not accept this offer and informed the Bank accordingly. The Bank, according to the workman, informed him of the consequences of declining the offer and he was debarred for having any such offer for a period of 5 years. This was so, according to the workman because of Rule No. 10 of Bipartite Settlement dated 3rd October, 1978.

3. As he was debarred in the year 1984 Shri Surti was the seniormost eligible workman in the area comprising of Kalyan Municipal Corporation consisting of Dombivli, Ambarnath and Kalyan branches. The Bank, however, did offer promotion to the post of Head Peon gave it to Shri Kutty on 28-9-84 at Dombivli Branch on temporary basis, though debarred. He was also paid Head Peon's allowance.

4. It is stated that Shri Supe working as Daftary and attached to Dombivli Branch raised an objection to the appointment of Shri Kutty and the Bank paid Mr. Supe Head Peon's allowance for the period 20th April 1983 to 4th January 1984 on prorata basis and Shri Kutty was also paid allowance on the temporary basis upto 13-3-1985 and he was assigned the additional duties of Head Peon on regular basis with effect from 1-4-1985.

5. The management according to the workman has given promotion to Shri Supe w.e.f. 11-3-1985. The contention of the workman is that after the formation of Kalyan Corporation, which comprised Dombivli, Kalyan and Ambarnath branches, citywise seniority was the criteria under clause 3.1 (c) of the memorandum of settlement dated 3rd October 1978 read with clause 5.1 of the settlement and the Bank should have given that promotion of Head Peon to Shri Surti w.e.f. March 1985.

6. The workman Shri Surti therefore, has a grievance and according to him he has been denied the promotional post and consequent allowance and therefore, union approached Regional Labour Commissioner and after failure report was submitted by the Assistant Labour Commissioner this reference has been made.

7. The management of the Bank has not disputed the fact that Shri Kutty was the seniormost and below him was Shri Surti in order of seniority at the relevant time. It is further, not disputed that Shri Supe was junior to Shri Surti and was at the relevant time working at Dombivli branch, However, it is stated that Shri Surti was working at Kalyan branch.

8. According to the management corporation was formed on 2nd October, 1983, Bank of Baroda, Dombivli branch became eligible for a post of Head Peon w.e.f. 20th April 1983 on the ground that the staff's strength increased to seven. This post was assigned to Shri Supe, who was the seniormost working at Dombivli Branch and that was prior to the formation of Kalyan Municipal Corporation. This was permissible under Bipartite Settlement and therefore, could not have been given to Shri Surti, who was working not at Dombivli but at Kalyan.

9. The short point that would arise for consideration is whether the action of the Bank of Baroda in denying the promotion to Shri Surti w.e.f. 1985 is justified on the ground mentioned by it in the written statement and in view of Bipartite Settlement.

10. The learned counsel who appeared on either side have been heard by me on this point.

11. As stated earlier the seniority of Shri Supe is not in dispute. Shri Kutty is admittedly senior to both. The grievance made by Shri Surti is on the ground that he was debarred by reason of the fact that he had declined offer. On the point that he declined offer there is no dispute. The offer is made by letter dated 26-3-1985 serial No. 3 with list date June 1992 filed by the Bank of Baroda. Shri Kutty did not accept the same and that was communicated by the Bank Manager to him by letter dated 7-2-1984. Before that by letter dated 2-2-1984, he was not only called upon to communicate to signify his acceptance but he was also told that if refused no such offer would be made for a period of five years from the date of that offer and it would be considered only on written request received from him. On 24-1-85 the Regional Manager advised Dombivli Branch Manager who assigned additional duties of Daftary to Shri Kutty who had become eligible to the assignment of additional duties attracting special allowance. The grievance made by Shri Surti is that this could not have been done as he was not eligible for such offer within a period of 5 years from the date of first offer made on 2-2-1984. It is on the basis that Bipartite Settlement so stated in Rule 10. Rule 10 on reading the same I find that the bar comes in, if the employee refused to accept offer on an assignment/duties attracting special allowance on regular basis or on temporary basis on three occasions. It has not been shown that Shri Kutty had done it on three occasions and only material on record shows that it was done once when offer of 2-2-1984 was made. It is true that the letter written by the Branch Manager to Shri Kutty stated that if he refused the offer no such offer will be made to him in future for a period of 5 years from the date of this offer. But that is not consistent with Rule 10, which has been quoted above. Therefore, Shri Kutty could not be said to be debarred. The management of the Bank rightly offered the promotional post to Shri Kutty when he was eligible and post was available. That is by letter dated 26-3-1985. He was seniormost, he was working in the limits of Kalyan Municipal Corporation and he had claimed the post at Kalyan Branch.

12. Coming to the grievance about the appointment of Shri Supe, it has to be noted that Shri Supe was admitted juniors to Shri Kutty, Surti has joined in 1976 and Supe has joined in 1977. Shri Supe was assigned the additional duties of Head Peon at Dombivli Branch w.e.f. 20-4-1985 on which date the branch became eligible for the post of a Head Peon. According to the management he was the seniormost at the Dombiwli Branch on that day. The Corporation came to be

formed later on 2nd October 1983. Therefore, the claim for the appointment as Head Peon at Dombivli Branch of a Peon who was working there could not have been ignored. So far so good. But the grievance of Shri Surti is that after the formation of Katyan Municipal Corporation on the basis of citywise seniority, Shri Surti was senior to Shri Supe and therefore, when the post fell vacant and was required to be filled in 1985 on the basis of citywise seniority. Shri Surti's claim could not have been ignored. In this connection it is worthwhile refering to reply dated 12-9-1989 by the Regional Manager to the Assistant Labour Commissioner In this it has been stated that it was brought to notice of the regional office in March 1985 that the post of Dombivli Branch was eligible for a Head Peon w.e.f. 20-4-1983 as the number of sub-staff strength become seven. However, it was brought to the notice of regional office in March 1985 that there was no Head Peon at Dombivali Branch on a permanent basis and it was decided to assign the additional duties of Head Peon to the branch, taking into consideration the seniority of staff members of the branch as on the date the branch became eligible for a Head Peon i.e. 2-4-1983 and accordingly Mr. Supe being the seniormost sub-staff member at Dombivali Branch on 20-4-1983, it was decided to assign the additional duties of Head Peon to him w.e.f. 11-3-1985. It was further stated in that reply that though Shri Surti has joined the Bank before Mr. Supe, in view of the vacancy arising before formation of the Kalyan Corporation, it was decided to assign the duties of Head Peon to Mr. Supe in accordance with the agreements with the recognised Union. This agreement referred to probably refers to Bipartite Settlement of 1978. So far as the Bipartite Settlement is concerned it is seen that sanction of a Head Peon allowance would be on the basis of citywise seniority provided, however, if the allowance is to be paid temporarily it is to be given on branchwise seniority. Therefore, the management's contention is that post was created on 20th April 1983, the branch became eligible for a post of Head Peon w.e.f. 20-4-1983 and Shri Supe was the seniormost at that branch and therefore he was eligible to that post applying the criteria on citywise seniority as well as branchwise seniority because there was only one branch in the city of Dombivali on 2-10-1983 the Corporation was formed and then the question of citywise seniority would have probably negatived the claim of Shri Supe but since he was eligible for appointment on 20-4-1983 he was appointed to that post. This reply dated 12-9-1989 to which I have made reference above states that "however, when it was brought to the notice of the regional office in March 1985 that there is no Head Peon at Dombivali Branch on a permanent basis, it was decided to assign the additional duties of Head Peon in the branch, taking into consideration the seniority of staff members of the branch as on the date of the branch became eligible for a Head Peon that is 20-4-1983 and accordingly Mr. Supe being the seniormost sub-staff member at Dombivali Branch on 20-4-83, it was decided to assign the additional duties of Head Peon to him w.e.f. 11-3-1985." I am unable to accept this line of reasoning adopted by the management of the Bank. If the suggestion of paying Head Peon allowance temporarily arose, then it would be right for the Bank to say that the same would be paid to Mr. Supe who was the seniormost at Dobivali Branch. However, that is not so. With effect from 11-3-1985, he comes to be given the post of Head Peon on permanent basis. On that day on the basis of citywise seniority, Mr. Surti was eligible because he was senior to Mr. Supe within the Corporation limit which comprised of Dombivali, Kalyan and Ambarnath Branches. The criteria for promotion on that day that is 11-3-1985 is the same namely clause 5.6 of the Bipartite Settlement on 1978. It says that the sanction of Head Peon allowance would be on the basis of citywise seniority provided, however, if the allowance should be paid temporarily it would be on the branchwise seniority. At a time of filling this post in 1985 on permanent basis, the claim of Shri Surti could not have been ignored. If in 1983 before the formation of Kalyan Municipal Corporation the action of filling up the post was taken up it would have been possible for the Bank to appoint Shri Supe to that post on the basis of clause 5.6 as Supe was senior in the city of Dombivali. But since that was not done and the action of filling up the post was taken after the formation of Kalyan Corporation in 1985 it was incumbent upon the management to appoint Shri Surti on the basis of citywise seniority.

13. Mr. Pai on behalf of the management submitted that on 20th April 1983 Mr. Supe was the only person who could have been appointed on the basis of seniority. Because the Bank took a decision in 1985 it would not have been correct on the part of the Bank to refuse to appoint Mr. Supe as a Head Peon. I am of the view that where the question of filling up the post on permanent basis came up before the management in 1985 to criteria laid down in clause 5.1(c) of the Bipartite Settlement had to be applied. The correct action of the Bank would have been to appoint Mr. Surti as a Head Peon in Dombivli Branch, to pay Mr. Supe Head Peon allowance till the appointment of Shri Surti was made and he took over as Head Peon in the Dombivali Branch.

14. It was argued on behalf of the management by Mr. Pai that there is no question of promotion to the post of Head Peon and that Head Peon only gets an allowance and therefore, it is only an allowance carrying post and not a promotional post. He submitted that the reference is misconceived when it speeks of the action of the management in not promoting Shri Surti. As I can see from the record produced it is considered to be a promotional post from the post of Peon. Though the cadre is the same he gets additional emoluments and must be having additional duties including supervisory duties Be that as it may, I am of the view that Shri Surti should not have been denied the allowance carrying post when he became entitled to it with effect from March 1985 to be precise w.e.f. 11-3-1985 he will be entitled to the allowance on that basis, which the management shall pay.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1994

का.आ. 527.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, कार्पोरेशन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/554/89-डी-2 (ए)]
एस.एस. के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th January, 1994

S.O. 527.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Corporation Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 24-1-1994.

[No. L-12012/554/89-D.II (A)]
S. S. K. KAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, AT BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-27 of 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of Corporation Bank.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For theManagement—Shri M. S. Bandodkar, Advocate.
For the Workmen—Shri Zeller D'Souza, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Goa

Bombay, the 10th day of January, 1994

AWARD

The following reference has been made to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by letter dated 16-4-1990.

"Whether the action of the management of Corporation Bank, H.O. Mangalore in terminating the services of Shri Francis Rodrigues, Peon with effect from 10-4-1989 is justified, If not, to what relief the said workman is entitled to ?"

2. My learned predecessor had by judgement dated 25-7-1990 rejected the reference on the ground that the workman was absent and the envelop addressed to him has been returned with remarks 'unclaimed'.

3. Subsequently he restored the same by an order dated 14-12-1990 in Misc. Application No 7 of 1990.

4. On behalf of the workman statement of claim has been filed. He stated therein, that he was appointed as a Peon on 2-4-1984 at Mapusa Goa Branch and was confirmed with effect from 9-11-1984. He was thereafter transferred to Panaji. Goa Branch.

5. He was chargesheeted on 14-9-1988 on the allegation that his act in submitting a false certificate of having passed S.S.L.C. examination amounted to a 'misconduct' After the enquiry, during which he pleaded guilty to the charge, he was dismissed from services. His appeal was rejected and thereafter, he approached Conciliation Officer in vain and Government made reference for adjudication.

6. In the course of his statement he has complained that he has supplied the certificate by Kranti Coaching Classes which he had joined. He did not know that the certificate was false. He was cheated by the organisation of the said coaching classes and he has lodged a complaint against the owners and the matter was investigated into. He further stated that the domestic enquiry was concluded on the same day it started without examination of any witness on behalf of the Bank or production of any documents. He therefore, stated that the enquiry is vitiated According to him the action can be taken only under clause 19.1 to 19.16 of the first Bipartite Settlement. He further states that the order of dismissal is too harsh and severe and unjusified in view of past clean record. He prayed for reinstatement.

7. On behalf of the management written statement has been filed justifying order of dismissal. It is stated that the delinquent workman submitted a letter dated 6-10-1986 stating that he had passed S.S.L.C. examination in March 1986 and in support had enclosed a xerox copy of certificate/ marklist bearing No. 206357 dated 19-5-1986 as purporting to have been issued by the said Examination Board, namely, Karnataka Secondary Education Exmination Board (K.S.E.E.B) He also requested the Bank to take the certificate on Bank's record. On verification it was found that it was a false certificate and therefore chargesheet was given to him and enquiry held and in the course of enquiry, workman pleaded guilty and therefore, dealt with accordingly. It is stated that there is nothing wrong with the enquiry justified the final order of dismissal, while pleading that the order of penalty is not harsh.

8. The point arising for consideration is whether the action of the management in terminating the services of the employee is justified and for that purpose it has to be seen whether he was given a fair opportunity to defend himself while enquiring into the charges and while passing ultimate order and principles of natural justice have been followed. The fact that the certificate produced was not genuine one is not disputed. His contention that he did not know that it was not a genuine certificate is belied by the fact that when he did not appear for all the subjects the certificate showed that he had Anyone acting upon that certificate should have known that the same was not genuine. This employee inspite of it, produced the same and wanted the management to act upon it. When the chargesheet was given to him and enquiry held, he pleaded guilty to the charge Not that he was alone before the Enquiry Officer but he was accompanied by a representative and yet pleaded guilty to the charge. In the circumstances the Enquiry Officer found it unnecessary to hold any further proceedings and examine any witnesses to prove that which was not disputed. On the basis of this the Enquiry Officer found him guilty and made a report. It is seen that all along he was asking the management to take a lenient view and nothing more. The management considered this to be a very serious misconduct and passed the order of dismissal on the basis of the findings of the Enquiry Committee with which the Disciplinary Authority agreed. His appeal failed. I do not see any lapse on the part of the management in following the procedure, observing the rules of natural justice and in giving him a fair opportunity to defend himself. I must say during the course of arguments also the learned counsel appearing for the workman did not address any arguments on this aspect of the matter.

9 The point thus arising for consideration is whether the act of misconduct was covered by the relevant provisions of Bipartite Settlement. It is needless to say that unless so covered the management will not be justified in taking action against the employee and it is not necessary to refer to the relevant rulings on the point. I however, find that the act committed by the workman squarely falls within the mischief of 'misconduct' as envisaged by the Bipartite Settlement and in this connection I must refer to the relevant provisions. Gross 'misconduct' is spelt out in clause 19.5 and relevant provisions would be (m)/(n) which deals with one who knowingly makes a false statement in any document pertaining to or in connection with his employment in the Bank. Other clause is clause (j) which reads thus doing any act prejudicial to the interest of the Bank or gross negligence or negligence involving or likely to involve the Bank in serious loss. I fail to see how both these clauses are not attracted. This employee has produced a certificate and it is proved to be not genuine or more precisely proved to be false He had produced the certificate and I have stated earlier that he should be deemed to have known that it was not genuine. By letter dated 6-10-1986 he stated that he was glad to inform that he has passed the S.S.L.C. Examination held by Karnataka Secondary Education Examination Board held in March 1986 and was enclosing therein a xerox copy of the certificate (mark list) duly certified for perusal. Therefore, he makes a request to note that in records. He was called upon to produce the original and he had done it. It was sent for verification to the Secretary, KSEEB. The Board Secretary informed the Chief Manager by letter dated 25-8-1988 "the certificates is a bogus certificate". It is seen from the letter of the Vidyavardhaka Pre-University College Mundkur's letter dated 9-9-1988 that Principal informed the Chief Manager, Corporation Bank that the party secured only 18 marks and certificate produced was not issued by him. It is not necessary therefore to deal further with the argument about the act of misconduct indulged in by the employee not being covered by misconduct. In my opinion there is no merit in this contention that 19.5 (j) is not attracted.

10. Coming to the quantum of penalty it must be remembered that the misconduct is of a very serious nature, the penalty has to be proportionate to its gravity. On behalf of the management it was urged that only two years service was too short to build up a record of service either way. I entirely agree with the submission. I feel that the way he began the management rightly thought that he should not be given any further opportunities to progress in that directions more so when the employment was in a Bank. The action is justified and no relief could be given to the employee. Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1994

का.आ. 528 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ राजस्थान लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-1-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/3/90-आई आर बी-III आईआरबी-I]

एस.एस.के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd February, 1994

S.O. 528.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Rajasthan Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 31-1-94.

[No. L-12011/3/90-IR(B III)/IR.B.I.]
S. S. K. ROY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी.आई.टी० 34/90

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 12011/13/90—आई. आर. बी.टी. III दिनांक 4-5-90

श्री राम बाबू गुप्ता पुत्र श्री एस.एन. गुप्ता निवासी प्लाट नं. ई-220, अम्बाबाड़ी, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

अध्यक्ष, दी बैंक ऑफ राजस्थान, सेन्ट्रल ऑफीस, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।

एवं

प्रबन्धक, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. जौहरी बाजार, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एस.एन. गुप्ता
अप्रार्थी की ओर से : श्री आलोक फतहपुरिया
दिनांक अवार्ड :

दिनांक 26-11-93

अवार्ड

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश के द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे, तत्पश्चात अधिनियम 1947 संशोधित किया है, की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of Regional Manager, the Bank of Rajasthan Ltd., Jaipur in terminating the services of Shri Ram Babu w.e.f. 26-5-89 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. प्रार्थी श्री राम बाबू गुप्ता ने वाद पत्र दिनांक 21-6-90 को प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया है कि उसे प्रतिवादी बैंक ऑफ राजस्थान लि. को जौहरी बाजार जयपुर शाखा में अनिश्चित अवधि के लिए क्लर्क के पद पर 6 मई 1989 को नियुक्त किया गया था और शाखा प्रबन्धक ने सूचित किया था कि उसे नियुक्ति पत्र तत्काल ही दे दिया जायेगा। उसके कार्य की अवधि दोपहर 1.00 बजे से 6 बजे तक निश्चित थी, उस समय वह एम. कॉम प्रीवियस की परीक्षा 1989 में बैठ रहा था जो परीक्षा 29-5-89 को पूर्ण हुई। वाद पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि उसे दिनांक 19-5-89 को सायं शाखा प्रबन्धक ने अपने केबिन में बुलाकर कहा कि उसे 20-5-89 को आने की आवश्यकता नहीं है और उसकी सेवाएं बिना किसी कारण के समाप्त कर दी। यद्यपि वादी दिनांक 20-5-89 को उपस्थित हुआ किन्तु उसे शाखा प्रबन्धक ने कार्य करने नहीं दिया। वाद पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि उसके स्थान पर श्री मुकेश शर्मा की नियुक्ति दे दी गई और इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (जी) व (एच) का उल्लंघन हुआ है। औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 77 व 78 का तथा शास्त्री अवार्ड के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि उसे सेवा मुक्त करते समय कोई वरिष्ठता सूची नहीं निकाली गई। यह भी कथन किया है कि प्रबन्धन उससे इसलिए नाराज था क्योंकि वह श्री एस.एन. गुप्ता का पुत्र है जो इस बैंक के कर्मचारी पिछले 30 वर्ष से हैं और उन्होंने उक्त बैंक को कई अदालतों में हराया था। इस कारण उसे अवैध रूप से सेवा मुक्त किया गया है जो विक्टिमाईजेशन की तारीख में आता है। वाद पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि यह छंटनी का मामला है और अधिनियम 1947 की धारा (जी) व (एच) तथा औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमावली एवं शास्त्री अवार्ड के निर्देशों की अवहेलना की गई है।

3. अप्रार्थी की ओर से जवाबदावा दिनांक 13-9-90 को प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी को पार्ट टाईम पास बुक राईटर के रूप में रखा गया था। चूंकि उसने यह प्रकट किया था कि वह एक नियमित विद्यार्थी है, जो कि इस नियुक्ति की पूर्व आवश्यक शर्त थी किन्तु जब उससे विद्यार्थी होने का शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह प्रस्तुत करने में विफल रहा इस कारण वह पुनः काम पर नहीं आया इस प्रकार उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई। यह भी अभिकथन किया।

4. प्रार्थी राम बाबू ने अपनी साक्ष्य में स्वयं को परीक्षित कराया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-10 प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रदर्श डब्ल्यू-1 नोटिस दिनांक 10-6-89, डब्ल्यू-2 अन्य व्यक्ति प्रमोद कुमार पास बुक राईटर का नियुक्ति पत्र व डब्ल्यू-3 उस व्यक्ति को एक्सटेंशन पत्र, डब्ल्यू-4 असफल वार्ता प्रतिवेदन दिनांक 21-2-90, डब्ल्यू-5, राजस्थान विश्वविद्यालय की एम. कॉम प्रीवियस 1989 में बैठने का प्रार्थी का प्रवेश पत्र, डब्ल्यू-6 बैंक द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 2-2-90 जो सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को प्रेषित किया गया, डब्ल्यू-7 स्थाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची दिनांक 30-9-89, डब्ल्यू-8 बैंक का सरकूलर दिनांक 23-8-89, डब्ल्यू-9 प्रार्थी का आइडेंटिटी कार्ड, प्रदर्श डब्ल्यू-10 भुगतान आदेश दिनांक 5-2-92 के संबंध में प्रस्तुत किये गये।

5. अप्रार्थी की ओर से साक्ष्य में बैंक ऑफ राजस्थान, एम.आई. रोड़ शाखा के मुख्य प्रबन्धक श्री एस.एन. शर्मा को परीक्षित कराया गया है। प्रलेखीय सबूत में प्रदर्श एम-1 श्री राम बाबू के बयान जो श्रम न्यायालय जयपुर के मुकदमा सं. 210/89 में हुए, एम-2 प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी ने नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किया। एम-3 अंक तालिका, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की जिसमें प्रार्थी ने तृतीय वर्ष 1986 में जो अंक प्राप्त किये, एम-4 सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा 1981 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, एम-5 भुगतान पत्र दिनांक 13-7-89 प्रदर्शित कराये हैं। इसके अतिरिक्त बैंक के सरकूलर दिनांक 5-12-77 को भी प्रदर्श एम-3 मार्क किया गया है तथा भुगतान आदेश तादादी रु० 224.44 दिनांक 12-7-89 को प्रदर्श एम-4 मार्क किया गया है एवं फार्म प्रदर्श एम-2 के साथ सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा व स्नातक परीक्षा की अंकतालिका को क्रमशः एम-2 एवं एम-2 बी मार्क किया गया है।

6. मैंने पक्षकारों के प्रतिनिधियों की बहस विस्तारपूर्वक सुनी तथा पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों को ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

7. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया :

1. ए.आई.आर. 1976 (एस.सी.) पेज-4, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम एम. सुन्दरमणि।

2. 1990 I एल.एल.जे. 408 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय) राम चन्द्र यादव बनाम आर.एस.आर.टी.सी. ।

3. 1988 लैब. आई.सी. 503, (माननीय गोहाटी उच्च न्या.) आयोजन सैकिया बनाम आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आसाम ।

4. ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 1163, श्रीमति मेरी थोमन बनाम मैनेजर एम.जी.एम. हाई स्कूल, कुरुप्पमपेडी, केरला ।

5. डब्ल्यू.एल.आर. 1991 (एस) राज 373, जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, नई दिल्ली बनाम जज, सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल व अन्य एवं रेलवे कैजयूअल लेबर यूनियन बनाम जनरल मैनेजर नार्दर्न रेलवे ।

6. 1992 (1) डब्ल्यू.एल.सी. 464 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय) ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स बनाम दी प्रेसाइडिंग ऑफिसर, सैन्ट्रल गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ।

7. डब्ल्यू.एल.आर. 1991 (एस) राजस्थान 7, जोधपुर विश्व-विद्यालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर ।

8. 1984 लैब.आई.सी. 445 (माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय) नवभारत हिन्दी डेली नागपुर बनाम नवभारत श्रमिक संघ ।

9. 1990 (1) डब्ल्यू.एल.एन. 372, जनरल मैनेजर नार्दर्न रेलवे बनाम केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जोधपुर ।

10. 1989 लैब. आई.सी. 1597 (माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय) स्टेट ऑफ पंजाब बनाम कश्मीर सिंह व अन्य ।

11. 1984 लैब. आई.सी. 645, श्री गफ्फार एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ।

12. 1981 लैब. आई.सी. 217 (माननीय केरल उच्च न्यायालय) अब्दुल रहमान बनाम संभागीय अधीक्षक सदर्न रेलवे ओलावा-कोड व अन्य ।

13. 1987 लैब. आई.सी. 1361 (माननीय गुजरात उच्च न्या.) गुजरात स्टेट मर्शन टूल्स कार्पोरेशन बनाम दीपक जे. वैशाई ।

14. 1990 I एस.एल.जे. 445 (माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय नागपुर बेंच) दिलीप हनुमन्तराव शर्मे व अन्य बनाम जिला परिषद यावतमल व अन्य ।

15. ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 1960, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. विजयवाडा बनाम एस.वी. पूरन-चन्द्रा व अन्य ।

16. ए.आई.आर. 1980 पेज 1219 (एस.सी.) I एवं I-I एल. एल.जे. 72 संतोष गुप्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ।

17. ए.आई.आर. 1982, 854, एस.राबर्ट डिसूजा बनाम एग्जी-क्यूटिव इंजीनियर सदर्न रेलवे ।

18. 1961 II एल.एल.जे. 110 (एस.सी.) कावनपोर टैनेरी लि. बनाम गुहा, (एस.) व अन्य ।

19. 1986 लैब. आई.सी. 1191 (एस.सी.) एस. गोविन्द-राजू बनाम के.एस.आर.टी.सी. व अन्य ।

20. ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 1982, मक्खन सिंह बनाम नरायनपुरा कोआपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसायटी लि. ।

21. ए.आई.आर. 1986 (एस.सी.) 1108, जगदीश प्रसाद बनाम सचिव, जिला गन्ना कमेटी मुजफ्फरनगर व अन्य ।

22. ए.आई.आर. 1985 (एस.सी.) 722, डब्ल्यू.बी.एस.सी. बोर्ड बनाम देश बन्धु घोष ।

23. 199 (2) एस.एल.आर. 297 (माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, रघुबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य ।

24. डब्ल्यू.एल.आर. 1991 (एस.सी.सी.) श्रीमति संतोष कुमारी बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ।

25. 1987 एस.सी.सी. (लैब.) 75, कमलेश सिंह बनाम पीठा-सीन अधिकारी व अन्य ।

26. सिविल अपील नं. 420/1984 निर्णय दिनांक 5-1-93 बैंक ऑफ राजस्थान बनाम बैंक एम्पलाईज यूनियन ।

27. 1981 (42) एफ.एल.आर. 272, (माननीय केरल उच्च न्यायालय) प्रभाकरण व अन्य बनाम जनरल मैनेजर के.एस.आर.टी.सी. व अन्य ।

9. अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये :

1. 1991 (81) एफ.जे.आर. पेज 107, (माननीय पटना उच्च न्यायालय) कृष्ण मुरारी प्रसाद बनाम अलाहाबाद बैंक व अन्य ।

2. 1991 (81) एफ.जे.आर. पेज 505 (एस.सी.) इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यू.पी. बनाम पुष्पा श्रीवास्तव ।

3. 1991 (62) एफ.जे.आर. 755 (माननीय केरला उच्च न्या.) इंडियन एयरलाईन्स बनाम सबस्टिन ।

4. 1988 (73) एफ.जे.आर. 93 (माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय) कादरविधा बैंक एम्पलाईज यूनियन बनाम केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, बैंगलौर व अन्य ।

5. 1990 (I) एल. एल. जे. 447 (माननीय गुजरात उच्च न्यायालय) पटेल एवलिन रणछोड़भाई बनाम गुजरात आयुर्वेद यूनीवर्सिटी जामनगर ।

6. 1990 (2) एल. एल. जे. 70 पंजाब लैंड डेवेलपमेंट एंड रीक्लेमेशन कार्पोरेशन लि. चंडीगढ़ व अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ (एस. सी.) ।

7. 1992 (II) एल. एल. जे. 177, (माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय) जसविन्दर सिंह पसी बनाम रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज ।

8. 1991 (78) एफ. जे. आर. 441, (एस. सी.) स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य बनाम कौशल किशोर शुक्ला ।

9. 1992 (1) सी. एल. आर. 356, (माननीय केरला उच्च न्यायालय) राजन बनाम केरला स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

10. 1991 लैब. आई. सी. 1638 (2) (एल. सी.) म्यूनीसीपल कार्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बाम्बे बनाम डा. सुशील भी. पाटकर व अन्य ।

11. 1989 लैब. आई. सी. 1851 (2) (माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय) सतीश चन्द्र पाण्डे बनाम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी व अन्य ।

10. तथ्यात्मक स्थिति :

अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं प्रलेखों तथा विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस निर्देश का निस्तारण करूंगा ।

11. वाद पत्र में वादी ने यह कथन किया है कि उसे प्रतिवादी बैंक की जौहरी बाजार शाखा में अनिश्चित काल के लिए क्लर्क के स्थाई पद पर नियुक्त किया गया था और 6 मई, 1989 से उसने कार्य करना प्रारंभ किया । यह उल्लेखनीय है कि वादी ने कोई नियुक्ति पत्र पेश नहीं किया है ।

12. प्रतिवादी बैंक का यह स्पष्ट अभिकथन है कि वादी द्विपक्षीय समझौते के पैरा 30.4 के अनुसार विद्यार्थी होने की पूर्व शर्त के साथ पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर नियुक्ति किया गया था और उसने मात्र 14 दिवस ही इस पद पर कार्य किया। साथ ही उससे केवल दिन में दो घंटे 3.00 बजे से 5.00 बजे तक ही कार्य लिया जाता था। जब उससे नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाणपत्र मांगा गया तो वह पेश करने में असमर्थ रहा अत: उसका नियोजन स्वत: ही समाप्त हो गया।

13. प्रार्थी राम बाबू गुप्ता ने यह कथन किया है कि उसे क्लर्क के पद पर अनिश्चित काल के लिए मैनेजर ने 6 मई 1989 से रखा था और 20-5-89 को जब वह बैंक गया तो मैनेजर ने उसे कार्य पर लेने से इंकार कर दिया। उसका कथन है कि उसने बैंक को नोटिस प्रदर्श डब्ल्यू-1 दिनांक 10-6-89 को दिया था। यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श डब्ल्यू-2 व डब्ल्यू-3 अन्य व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार से संबंधित हैं जिसे पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर नियुक्त किया गया था जिसे सप्ताह में 12 घंटे ही कार्य करना पड़ता था। प्रदर्श-4 सहायक श्रम आयुक्त का असफल वार्ता प्रतिवेदन है तथा प्रदर्श डब्ल्यू-5 एडमीशन कार्ड है तथा प्रदर्श-6 प्रत्युत्तर है जो बैंक आफ राजस्थान लि. सहायक श्रम आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा डब्ल्यू-7 नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची है। प्रदर्श-8 बैंक का सरकूलर दिनांक 23-8-89 है। प्रदर्श-9 फार्म आफ आइडेंटिटी है जिस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। प्रदर्श-10 पत्र दिनांक 5-2-92 का है जो पे आर्डर के संबंध में वादी ने चीफ मैनेजर बैंक आफ राजस्थान लि. को 224.44 पैसे प्राप्त होने के संबंध में भेजा है।

14. यह उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक के विरुद्ध एक वाद कर रखा है उसके बयान प्रदर्श एम-1 पर ए टू बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी टू डी स्थान पर उसका बयान सही दर्ज है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने बैंक में निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रदर्श एम-2 प्रस्तुत किया था। उसने स्वीकार किया है कि वह नियमित विद्यार्थी नहीं है और न ही उसने नियमित विद्यार्थी होने का प्रलेख ही पेश किया है। उसने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने बैंक में 6-5-89 से 19-5-89 तक कार्य किया जबकि उसने इस कथन के विरुद्ध प्रदर्श एम-1 में यह बताया है कि उसने दिनांक 6-5-89 से 19-5-89 तक बैंक आफ राजस्थान की जोहरी बाजार शाखा में कार्य नहीं किया। इस प्रकार उसके ये दोनों बयान परस्पर विरोधी हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि एक स्वर में तो उसने यह कहा है कि उसने बैंक में 6-5-89 से 19-5-89 तक बैंक आफ राजस्थान में कार्य किया जबकि बयान प्रदर्श एम-1 में उसने इसको अस्वीकार करते हुए कहा है कि 6-5-89 से 19-5-89 तक उसने उक्त बैंक की जोहरी बाजार शाखा में कार्य नहीं किया। इस प्रकार वादी का सत्य के प्रति कोई आदर नहीं है, उसने अपनी इच्छानुसार अपना बयान बदला है। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राम बाबू गुप्ता ने जो नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रदर्श एम-2 प्रस्तुत किया था उसमें यह उल्लिखित किया था कि वह एम-काम प्रीवियस का विद्यार्थी है और परीक्षा दे रहा है। उसका कथन है कि उसने यह प्रार्थना पत्र 6-5-89 के चार/पांच रोज बाद भरकर दिया था जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में तारीख 4-5-89 अंकित है जिसे वह गलत लिखना बताता है। उसका कथन है कि पहले की तारीख क्यों लिख दी, उसने ऐसा माइन्ड नहीं किया। उसने अपने प्रति परीक्षण में यह भी कथन किया है कि प्रदर्श एम-2 के साथ एडमीशन कार्ड भी साथ दिया था परन्तु उसका उल्लेख प्रदर्श एम-2 में करना जरुरी नहीं समझा जबकि एडमीशन कार्ड प्रदर्श डब्ल्यू-5 है।

15. यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी बैंक के साक्षी श्री एस. एन. शर्मा ने अपने कथन से यह प्रमाणित किया है कि वह मई 1989 में बैंक आफ राजस्थान की जोहरी बाजार शाखा में चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने प्रार्थी राम बाबू गुप्ता को पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर नियुक्त किया था। बैंक के सरकूलर दिनांक 5-2-77 प्रदर्श डब्ल्यू-3 के अनुसार ऐसी नियुक्ति अधिकतम 180 दिवस तक ही हो सकती थी। वादी की कार्यावधि रोज 3.00 बजे से 5.00 बजे तक व शनिवार के दिन 12.30 से 2.00 बजे तक थी। द्विपक्षीय समझौते के प्रावधान 20.4 के अनुसार पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर केवल छात्र अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारी को ही नियुक्त किया जा सकता था। यह भी कहा कि राम बाबू ने प्रार्थना पत्र एम-2 के साथ सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा व स्नातक परीक्षा की अंकतालिकाएं क्रमश: प्रदर्श एम-2ए व एम-2 बी प्रस्तुत की थी व यह आश्वासन दिया था कि 19-5-89 तक विद्यार्थी होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देगा जो उसने मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार वह इस पद की न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करता था। इस साक्षी ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसे स्थाई कर्मचारी के रूप में नियोजित किए जाने वाले नियमों व प्रक्रिया के आधार पर चयन समिति द्वारा चयनित किया जाकर नियुक्त नहीं किया गया था। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में यह कथन किया है कि वादी को कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था उसके आवेदन पर उसे मौखिक नियुक्ति दी गई थी। उपस्थिति रजिस्टर में उसकी हाजिरी नहीं लगाई गई व उसे पे आर्डर द्वारा पूरा वेतन ही दिया गया। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में अडिग रहा है और उसने यह प्रमाणित किया है कि वादी को पार्ट टाईम पास बुक राईटर रखा गया था जब उससे नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह पेश करने में असफल रहा। जैसा कि मैं ऊपर उल्लिखित कर चुका हूं कि वादी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह नियमित विद्यार्थी नहीं है और न ही उसने नियमित विद्यार्थी होने का कोई प्रमाणपत्र पेश किया है जबकि विद्यार्थी होने की पूर्व शर्त के आधार पर ही उसको पास बुक राईटर पद पर नियुक्ति दी गई थी। द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.4 के अनुसार केवल छात्र अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारी को ही उक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है। वादी इस पद को पात्रता नहीं रखता था क्योंकि वह नियमित छात्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है। वादी ने मात्र 14 दिवस ही विपक्षी संस्थान में कार्य किया है और उसे इस अवधि का भुगतान भी किया जा चुका है। वादी का यह कथन सर्वथा असत्य है कि उसे अनिश्चित काल के लिए क्लर्क के स्थाई व रिक्त पद पर 6-9-89 को बैंक मैनेजर ने रखा हो। तत्कालीन मैनेजर श्री एस. एन. शर्मा ने वादी के इस कथन का प्रतिवाद करते हुए कथन किया है कि उसे पार्ट टाईम पास बुक राईटर के कार्य हेतु रखा गया था। वादी ने अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसे कोई नियुक्ति आदेश न दिया और न ही चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया। ऐसी स्थिति में उसका यह कथन असत्य हो जाता है कि उसे क्लर्क के स्थाई पद पर अनिश्चित काल के लिए रखा गया हो। प्रतिवादी के साक्षी एस. एन. शर्मा ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसको वादी राम बाबू ने यह आश्वासन दिया था कि वह नियमित विद्यार्थी है और वह उसका प्रमाणपत्र पेश कर देगा किन्तु बाद में उक्त प्रमाण पत्र मांगने पर भी वह प्रस्तुत नहीं कर सका और 19-5-89 को जब प्रमाणपत्र मांगा गया तो उसके बाद वह काम पर नहीं आया। इस प्रकार नियमित विद्यार्थी होने के प्रमाणपत्र के अभाव में वादी को पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता था और इस मामले में भी उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। राम बाबू गुप्ता ने अपने प्रार्थना पत्र प्रदर्श एम-2 में यह उल्लिखित किया था कि वह एम. काम प्रीवियस का विद्यार्थी है और उसे नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र पेश करने का आश्वासन दिया था किन्तु मांगने पर वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा और उसने मात्र 14 दिवस ही बैंक में कार्य किया।

16. अब मैं मामले के तथ्यों और विधि को दृष्टिगत रखते हुए यह अधिनिर्णित करुंगा कि क्या इस मामले में बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन एवं प्रबन्धकों के मध्य प्रथम द्विपक्षीय समझौते अथवा शास्त्री अवार्ड एवं अधिनियम 1947 के प्रावधानों की अवहेलना होना प्रमाणित हुआ है।

17. जैसा कि मैं ऊपर उल्लिखित कर चुका हूं कि द्विपक्षीय समझौते के अध्याय 4 के अनुसार पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर केवल छात्र अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जा सकता है, अन्य किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक लोक कल्याणकारी योजना विद्यार्थियों तथा सेवा निवृत्त व्यक्तियों के लिए लागू की गई। कोई शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन काल में विद्यार्थी तो अवश्य रहता है किन्तु उसका अभिप्राय यह नहीं निकाला जा सकता कि इस योजना के अन्तर्गत एक्स-स्टूडेंट भी फायदा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादी के विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि विद्यार्थी की श्रेणी में एक्स-स्टूडेंट अथवा प्राईवेट स्टूडेंट भी आते हैं। प्रस्तुत मामले में वादी ने स्वयं को नियमित विद्यार्थी बताते हुए पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित फार्म में प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु जब उससे नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह पेश नहीं कर सका और स्वयं ही काम पर नहीं आया। इस न्यायाधिकरण के समक्ष भी प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर भी नियुक्त किए जाने की न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करता था तथा उसका विपक्षी बैंक में वैध रूप से नियोजित होना ही नहीं माना जा सकता। शास्त्री अवार्ड के पैरा 522 व 524 भी इस मामले में आकर्षित नहीं होते क्योंकि जब वादी को नियोजित ही नहीं किया गया था तो उक्त प्रावधान लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ये प्रावधान तो स्थाई अथवा अस्थाई कर्मचारियों के लिए ही लागू होते हैं। वादी विपक्षी बैंक का कर्मचारी विधिनुसार नियुक्त ही नहीं था।

18. शास्त्री अवार्ड के पैरा 508 में कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया है किन्तु पार्ट टाईम कर्मचारियों के बारे में कोई निर्देश उनको हटाते समय कम्पनसेशन आदि देने के बारे में नहीं दिए गए हैं। वादी इस प्रकार किसी तरह का मुआवजा पाने का भी अधिकारी नहीं रह जाता। निष्कर्ष यह है कि वादी ने शास्त्री अवार्ड के जिन प्रावधानों का उल्लेख किया है वे इस मामले में आकर्षित ही नहीं होते और ना ही बैंक के प्रबन्धन द्वारा उनकी अवहेलना किया जाना प्रमाणित हुआ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(00) में छंटनी को परिभाषित किया गया है कि "छंटनी से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेरित है। अधिनियम 1947 की धारा 2(00) को 1984 में संशोधित किया जाकर 2 (बी बी) जोड़ा गया है जिसके अनुसार" "termination of the services of workmen as a result of non-renewal of contract of employment between employer and workmen concerned on its expiry of such contract"

अपवाद, मात्र होने से छंटनी की परिधि में नहीं आता है। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त 1990(II) एल. एल. जे. पेज 70 (सुपरा) पर भरोसा करता हूं। वादी के विद्वान प्रतिनिधि ने जो भी न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं वे 1984 के संशोधन से पूर्व के हैं जो हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। वादी को न तो विधिनुसार नियोजित ही किया गया और न ही उसकी छंटनी की गई है। वादी ने स्वयं को नियमित विद्यार्थी बताते हुए पार्ट टाईम पास बुक राईटर के अस्थाई पद पर नियोजित होना चाहा था किन्तु वह नियमित विद्यार्थी नहीं था और ना ही उसने उस आशय का प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किया और जब उससे उक्त प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह स्वयं ही काम पर नहीं आया। इस प्रकार उक्त पद की न्यूनतम पात्रता ही प्रार्थी नहीं रखता था। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त म्यूनीसीपल कार्पोरेशन आफ ग्रेटर बाम्बे बनाम डा. सुशील पाटकर (सुपरा) पर भरोसा करता हूं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रबन्धन द्वारा प्रार्थी श्री राम बाबू को इस पद हेतु वैध रूप में नियुक्त होना नहीं माना जा सकता अतः उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त होना माना गया है जो मेरी राय में उचित एवं वैध है। प्रबन्धन द्वारा इस प्रकरण में प्रार्थी की छंटनी किया जाना प्रमाणित नहीं होता है ऐसी स्थिति में अधिनियम 1947 की धारा 55 (जी) व (एच) तथा औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 77 व 78 आकर्षित नहीं होते क्योंकि उक्त प्रावधान केवल छंटनी किए गए कर्मकारों के संबंध में ही लागू होते हैं। वादी जो वरिष्ठता सूची प्रस्तुत की है वह नियमित रूप से चयनित किए गए कर्मचारियों की है जबकि प्रार्थी का चयन समिति द्वारा चयन किया जाकर उसे नियुक्ति नहीं दी गई थी न तो उसने कोई परीक्षा दी और न ही उसका कोई साक्षात्कार हुआ। वादी को डिस्चार्ज/डिसमिस/टर्मिनेट/अथवा रिट्रैन्च नहीं किया गया बल्कि नियोजित होने की शर्तें पूरी नहीं करने के कारण वह स्वयं ही काम पर नहीं आया।

15. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"रीजनल मैनेजर, दी बैंक आफ राजस्थान लि. जयपुर द्वारा दिनांक 20-5-89 से श्री राम बाबू गुप्ता की सेवाएं समाप्त किया जाना उचित एवं वैध है। श्रमिक किसी राहत व राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।"

16 अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम के भेजी जाए।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1994

का.आ. 529 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ राजस्थान लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-1-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/35/87-आईआर(बी)/आई आर बी-1]
एस.एस.के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd February, 1994

S.O. 529.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Rajasthan Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 31-1-94.

[L-12011/35/87-IR(B)/IR. B.I]
S. S. K. RAO, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 1/1990

रैफरेंस :— केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 12011/35/87 आई. आर. आर. दिनांक 22-12-8

श्री आर. के. दीक्षित पुत्र श्री चौथमल शर्मा, 22, विजय मार्ग, वार्ड नं. 6, तीन दुकान वेर के बालाजी, जयपुर—प्रार्थी

बनाम

सहायक महा प्रबन्धक, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि., सी-27 सरोजिनी मार्ग, सी. स्कीम जयपुर—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से	कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी की ओर से	श्री आलोक फतहपुरिया
दिनांक अवार्ड	30-11-1993

अवार्ड

श्री आलोक फतहपुरिया विपक्षी बैंक की ओर से हाजिर हैं, प्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं है। श्री फतहपुरिया शहादत पेश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि प्रार्थी की ओर से भी कोई शहादत नहीं है आई है। आज भी प्रार्थी अथवा उसके प्रतिनिधि हाजिर नहीं है। प्रार्थी को अनेकों बार शहादत का अवसर दिया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी इस प्रकरण में रुचि नहीं ले रहा है अतः इस प्रकरण मे नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

शंकर लाल जैन,
पीठासीन अधिकारी,

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1994

का. आ. 530.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ राजस्थान लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-1-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/5/90/आई आर बी III आई आर बी-I]
एस. एस. के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd February, 1994

S.O. 530.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Rajasthan Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 31-1-94.

[L-12012/5/90-IR. B.III/IR.B.I]
S. S. K. RAO, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई टी. 31/1990

रैफरैन्स : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 12012/5/90 आई आर बी दिनांक 10-4-1990

श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री जे आर. खण्डेलवाल प्लाट नं. बी० 218, नेहरू नगर, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. चेयरमैन, बैंक आफ राजस्थान लि., सेन्ट्रल आफिस सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
2. प्रबन्धक दी बैंक आफ राजस्थान लि. विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर—अप्रार्थीगण

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से	श्री एस. एन. गुप्ता
अप्रार्थीगण की ओर से	श्री आलोक फतहपुरिया
दिनांक अवार्ड	दिनांक 26-11-93

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश के जरिये निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम, 1947 संबोधित किया है, की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है।

'Whether the action of the Manager, The Bank of Rajasthan Ltd., Jaipur is justified in terminating the services of Shri Chandra Prakash Khandelwal w.e.f. 19-2-1989 ? If not, to what relief the workman is entitled ?'

2. प्रार्थी श्रमिक श्री सी.पी. खण्डेलवाल ने अपना वाद दिनांक 8-8-1990 को प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी बैंक आफ राजस्थान की विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया जयपुर शाखा में दिनांक 9-1-89 को अंशकालीन लिपिक के स्थाई व रिक्त पद पर अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था। शुरु में उसे दो माह के लिए नियुक्ति पर दिनांक 9-1-89 से 8-3-89 तक की अवधि के लिए दिया गया था दिनांक 18-2-89 को बैंक के प्रबन्धक ने उसे अपने केबिन में बुलाकर उस दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र ले लिया और उसे काम करने नहीं दिया तथा उसका नाम सेवा रोल से हटा दिया और उसे सेवा मुक्त कर दिया तथा उपस्थिति रजिस्टर से उसका नाम काटकर उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति श्री राकेश मीणा को नियुक्त कर दिया।

3. वाद पत्र में भी उल्लिखित किया गया है कि उसे हटाते समय न तो कोई नोटिस दिया, ना ही नोटिस के एवज में एक मास का वेतन एवं ना ही कोई छटनी मुआवजा ही दिया गया। वाद में यह उल्लिखित किया गया है कि जब उसे सेवा मुक्त किया गया तब उससे कनिष्ठ व्यक्ति कार्य कर रहे थे। किन्तु उन्हें नहीं हटाया गया और ना ही कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई यह भी अभिकथन किया है कि प्रबन्धन ने उसको हटाने के बाद कई नये। व्यक्तियों को नियुक्त किया किन्तु उसे नहीं बुलाया गया। वाद में यह भी उल्लिखित किया गया कि वह श्री एस. एन. गुप्ता का भतीजा है जिससे बैंक इसलिए नाराज था कि उन्होंने उक्त बैंक को कई अदालतों में हराया था जो उसी बैंक के कर्मचारी पिछले 30 वर्ष से है जो उनका मुकदमा भी लड़ रहे हैं, इस कारण रीजनल मैनेजर श्री पी. सी. कालानी के निर्देश पर उसे अवैध रूप से सेवा मुक्त किया गया है। बैंक का उक्त कृत्य अनफेयर लेबर प्रेक्टिस तथा विक्टिमाईजेशन की तारीफ में आता है। वाद पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि यह रिट्रैन्चमेंट का मामला है और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (जी) व (एच) तथा औद्योगिक विवाद केन्द्रीय नियमावली, जिसे तत्पश्चात नियमावली संबोधित किया है, एवं शास्त्री अवार्ड के निर्देशों को अवहेलना की गई है।

4. अप्रार्थी की ओर से वादोत्तर दिनांक 13-3-90 को प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी को पार्ट टाईम पास बुक राईटर के रूप में रखा गया था। चूंकि उसने यह प्रकट किया था वह एक नियमित विद्यार्थी है जो कि इस नियुक्ति की पूर्व आवश्यक शर्त थी किन्तु जब उससे विद्यार्थी होने का शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह प्रस्तुत करने में विफल रहा इस कारण वह पुन काम पर नहीं आया अतः उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई।

5. अप्रार्थी बैंक ने प्रार्थी के दावे को पूर्णतः असत्य व मिथ्या बताते हुए उसे पूर्णतया अस्वीकार किया है।

6. वादी की ओर से वाद के समर्थन में साक्षी श्री एस.एन.गुप्ता एवं प्रार्थी श्रमिक श्री चन्द्र प्रकाश को परीक्षित किया जाता है तथा प्रलेखिक साक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू-1 लगायत 10 प्रस्तुत किये गये है प्रदर्श डब्ल्यू-1 नियुक्ति पत्र दिनांक 9-1-89, प्रदर्श डब्ल्यू-2 नियुक्ति पत्र दिनांक 20-2-89 डब्ल्यू-3 श्री खण्डेलवाल वैश्य महाविद्यालय, संसार चन्द्र रोड की रसीद दिनांक 1-10-88 जिसके द्वारा विद्यार्थी परीक्षा शुल्क 63 रुपये वसूल करना

दिखाया गया है । प्रदर्श डब्ल्यू-4 राजस्थान विश्वविद्यालय की अंक तालिका की फोटो प्रति जिसमें चन्द्र प्रकाश द्वारा द्वितीय वर्ष कामर्स परीक्षा 1989 में अनुकम्पा से उत्तीर्ण होना अंकित किया गया है, प्रदर्श डब्ल्यू-5 एक अन्य व्यक्ति श्री पी.के. शर्मा का पार्ट टाईम नियुक्ति पत्र दिनांक 27-2-86, प्रदर्श डब्ल्यू-6, पी.के. शर्मा का एकरारनामा पत्र दिनांक 5-3-86, प्रदर्श डब्ल्यू-7 सहायक श्रम आयुक्त जयपुर के समक्ष वार्ता प्रतिदिन दिनांक 24/25-1-90, प्रदर्श डब्ल्यू-8 बैंक का सरकूलर दिनांक 23-8-89 प्रदर्श डब्ल्यू-9 बैंक की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1989-90 की पेज नं. 13 जिसमें विभिन्न श्रमिकों की स्थिति वर्ष 1989 व 1990 को दर्शाई गई है तथा प्रदर्श डब्ल्यू-10, स्थाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रस्तुत की गई है।

6. अप्रार्थी की ओर से उनकी साक्ष्य में बैंक आफ राजस्थान लि. विश्वकर्मा शाखा के प्रबन्धक श्री एस.के. जैन को परीक्षित किया गया है तथा प्रलेखीय सबूत में प्रदर्श एम-1 प्रार्थी श्रमिक का नियुक्ति पत्र, एम-2 प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र तथा एम-3 उसकी अंक तालिका को प्रदर्शित कराया गया है। उपस्थिति रजिस्टर को भी प्रदर्श एम-1 मार्क किया गया है।

7. तत्पश्चात अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं प्रलेखों पर सतर्कता पूर्वक विचार किया गया तथा पक्षकारान ने गुणीय प्रतिनिधिगण की बहस धैर्यपूर्वक सविस्तार सुनी गई।

8. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :—

1. ए.आई.आर. 1976 (एस.सी.) पेज 1111 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम. सुन्दरमणि ।
2. 1990 I एल.एल.जे. 408 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय) राम चन्द्र यादव बनाम आर.एस.आर.टी.सी. ।
3. 1988 लैब, आई.सी. 503 (माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय) प्राकोन सैकिया बनाम आसाम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, आसाम ।
4. ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 1163, श्रीमति मेरी मोमन, मैनेजर एम.जी.एस. हाई स्कूल, कुरुंप्पमपेडी, केरला ।
5. डब्ल्यू.आर.आर. 1991 (एस) राज 373, जनरल मनेजर, नोर्दन रेलवे, नई दिल्ली बनाम जज, सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल व अन्य एवं रेलवे केज्यूअल लेबर यूनियन बनाम जनरल मैनेजर नादर्न रेलवे ।
6. 1992 (1) डब्ल्यू एल.सी. 464 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय) ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स बनाम दी प्रेसाइडिंग आफिसर, सेन्ट्रल गर्वनमेंट इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ।
7. डब्ल्यू.एल.आर. 1991 (एस) राजस्थान, 7, जोधपुर विश्वविद्यालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर ।
8. 1984 लेब.आई.सी., 445 (माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय) नवभारत हिन्दी डेली नागपुर बनाम नवभारत श्रमिक संघ ।
9. 1990 (1) डब्ल्यू एल.एन. 372 जनरल मनेजर नार्दन रेलवे बन केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर ।
10. 1984 लेब.आई.सी. 645, श्री गफ्फार एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ।
11. 1989 लेब.आई.सी. 1596 (माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, स्टट बैंक ऑफ पंजाब बनाम काश्मीर सिंह व अन्य ।
12. 1981 लेब.आई.सी. 217 (माननीय केरला उच्च न्यायालय) अब्दुल रहमान बनाम संभागीय अधीक्षक सदर्न रेलवे, ओलावाकोडे व अन्य ।
13. 1987 लब.आई.सी. 1361 (माननीय गुजरात उच्च न्यायालय) गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कार्पोरेशन बनाम दीपक जे.देसाई
14. 1990 I एल.एल.जे. 445 (माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर बैंच) दिलीप हनुमन्तराव शर्के व अन्य बनाम जिला परिषद चान्द्रपुर व अन्य ।
15. ए.आई.आर. 1980 पेज 1219 (एस.सी.) एवं II एल.एल.जे 72 संतोष गुप्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ।
16. ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 1960, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. विजयवाड़ा बनाम एन.वी. पूरनचन्द्रा राव व अन्य ।
17. ए.आई.आर. 1982, 854, एल. राबर्ट डिसूजा बनाम एगजीक्यूटिव इंजीनियर सदर्न रेलवे ।
18. 1961 II एल.एल.जे. 110 (एस.सी.) कानपौर टेनरी लि. गुहा (एम.) व अन्य ।
19. 1986 लैब. आई.सी. 1191 (एस.सी.) एस. गोविन्दराजू बनाम के.एस.आर.टी.सी. व अन्य ।
20. ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) एस.सी. 1893, मक्खनसिंह बनाम नरायनपुरा कोआपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसायटी लि.
21. ए.आई.आर. 1986 (एस.सी.) 1108, जगदीश प्रसाद बनाम सचिव, जिला गन्ना कमेटी मुजफ्फरनगर व अन्य ।
22. ए.आई.आर. 1985 (एस.सी.) 722 डब्ल्यू.बी.एस.सी. बोर्ड बनाम देश बन्धु घोष ।
23. 199 (2) एस.एल.आर. 297 (माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय रणवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य ।
24. डब्ल्यू.एल.आर. 1991 (एस) एस.सी. 1 श्रीमती संतोष कुमारी बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ।
25. 1987 एस.सी.सी. (लैब) 75 कमलेश सिंह बनाम पीठासीन अधिकारी व अन्य ।
26. सिविल अपील नं. 420/1984 निर्णय दिनांक 5-1-93 बैंक ऑफ राजस्थान बनाम राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन व अन्य
27. 1981 (42) एफ.एल.आर. 222 (माननीय केरला उच्च न्यायालय) प्रभाकरण व अन्य बनाम जनरल मैनेजर, के.एस.आर.टी.सी. व अन्य ।

9. अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये ।

1. 1991 (81) एफ.जे.आर. पेज 107 (माननीय पटना उच्च न्यायालय) कृष्ण मुरारी प्रसाद बनाम इलाहाबाद बैंक व अन्य ।
2. 1981 (81) एफ.जे.आर. पेज 565 (एस.सी.) इन्स्टीट्यूट ऑफ मनेजमेंट डेवलपमेंट यू.पी. बनाम पुष्पा श्रीवास्तव ।
3. 1991 (62) एफ.जे.आर. 755 (माननीय केरला उच्च न्यायालय) इंडियन एयरलाइंस बनाम सेबास्टियन ।
4. 1988 (73) एफ.जे.आर. (93) माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय) कावरिकूपा बैंक एम्पलाईज यूनियन बनाम केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण बेंगलोर व अन्य ।
5. 1988 (I) एल.एल.जे. 447 (माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, पटेल एवलिन रन्छूडभाई बनाम गुजरात आयुर्वेद यूनीवर्सिटी जामनगर ।
6. 1990 (2) एल.एल.जे. 70, पंजाब ले.ड. डेवेलपमेंट एंड रीक्लेमेशन कार्पोरेशन लि. चंडीगढ़ व अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ (एस.सी.) ।
7. 1992 (II) एल.एल.जे. 177 (माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय) जसविन्दर सिंह पसी बनाम रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज ।
8. 1991 (78) एफ. जे. आर. 441, (एस.सी.) स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य बनाम कौशल किशोर शुक्ला ।

9. 1992 (1) सी. एल. आर. 350, (माननीय केरला उच्च न्यायालय) राजम बनाम केरला स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

10. 1989 लैब. आई. सी. 1051 (माननीय अलाहाबाद उच्च न्यायालय) संतोष चन्द्र पाण्डे बनाम बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी वाराणसी व अन्य ।

11. 1991 लैब. आई. सी. 1638 (2) (एस. सी.) म्यूनीसीपल कार्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे बनाम डा. सुशील वी. पाटकर व अन्य।

10. अब में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं प्रलेखों तथा विधि की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस निर्देश का निस्तारण करूंगा । तथ्यात्मक स्थिति :

11. वादी ने वाद पत्र में यह अभिकथित किया है कि उसे अंशकालीन लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाकर नियुक्ति पत्र अनैक्सचर-1 विपक्षी बैंक द्वारा जारी किया गया था जबकि वादी श्री चन्द्र प्रकाश ने अपने शपथ पत्र में यह कथन किया है कि उसे क्लर्क के पद पर अप्रार्थी बैंक की विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र शाखा में अनिश्चित काल के लिए स्थाई रिक्त पद पर 9-1-89 को रखा गया था और उसे दो माह का नियुक्ति पत्र दिनांक 9-1-89 से 8-3-84 तक का दिया गया था जो प्रदर्श-9 है।

12. यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने यह स्पष्ट अभिकथन किया है कि वादी को अंशकालीन पास बुक राईटर के पद पर द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.4 के अनुसार विद्यार्थी होने की पूर्व शर्त के साथ 9-1-89 से 8-3-89 तक की अवधि के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया था किन्तु जब उससे विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र मांगा तो वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा और उसने 18-2-89 तक ही कार्य किया । यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने वादी के इस कथन का पूर्णतया खण्डन किया है कि उसको अनिश्चित काल के लिए क्लर्क के स्थाई रिक्त पद पर रखा गया हो।

13. वादी श्री चन्द्र प्रकाश ने अपने प्रति परीक्षण में नियुक्ति पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 पर "ए' टू "बी" अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है यह भी स्वीकार किया है कि उसमें दर्ज बातें सही मानकर हस्ताक्षर किये थे । इस प्रकार नियुक्ति पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 जो वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसपर प्रतिवादी ने भी भरोसा किया है, यह दोनों पक्षों की ओर से एक स्वीकृत दस्तावेज है । इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वादी को दो माह की अवधि के लिए 9-1-89 से 8-3-89 तक की अवधि तक पार्ट टाईम पास बुक राईटर के अस्थाई पद पर नियुक्ति दी गई थी। इस प्रकार वादी का यह कथन सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है कि उसे अनिश्चित काल के लिए क्लर्क के स्थाई रिक्त पद पर रखा गया हो।

14. यह उल्लेखनीय है कि वादी ने नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रारूप में जो प्रार्थना पत्र प्रदर्श एम-2 प्रस्तुत किया था उसमें स्वयं को द्वितीय वर्ष बी. कॉम. सी. कामर्स का विद्यार्थी होना अंकित किया है। यहां यह उल्लिखित करना अनावश्यक नहीं होगा, नियुक्ति पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 में यह आवश्यक शर्त क्रमांक 6 पर अंकित थी कि नियुक्ति यह मानते हुए दी जा रही है कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में की गई घोषणा (डिक्लेरेशन) सत्य व सही है जो कि सेवा की आवश्यक शर्त थी। वादी ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकृत दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू-1 में वर्णित तथ्यों के विरुद्ध यह कथन किया है कि उसकी नियुक्ति पत्र छः माह के लिए था जबकि नियुक्ति पत्र में दो माह की अवधि 9-1-89 से 8-3-89 अंकित है जिसे भी उसने जान बूझकर गलत बताया है। इस प्रकार वादी को सत्य के प्रति कोई आदर ही नहीं है।

15. उपस्थिति रजिस्टर प्रदर्श-1 पर वादी ने "ए" टू "बी" हस्ताक्षर अपने होना स्वीकार किया है उसमें उसके काम का समय दो घंटे प्रतिदिन 2.45 से 4.45 बजे है जिसे जो जानबूझकर उसने गलत लिखा हुआ होना कहा है और यह कथन किया है कि उसके काम का समय दोपहर 1.00 बजे से 5.00 बजे तक था। वादी ने निर्धारित प्रारूप में जो प्रार्थना पत्र प्रदर्श एम-2 प्रस्तुत किया उसपर भी "ए" टू "बी" हस्ताक्षर उसने अपने होना स्वीकार किया है और यह भी कथन किया है कि उसके साथ मार्क शीट प्रदर्श एम-3 दी थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि श्री एस. एन. गुप्ता, जो कि इस मुकदमें में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके ताऊजी हैं।

16. वादी ने यह कथन किया है कि उसने लिखित परीक्षा पास नहीं की और न ही चयन कमेटी द्वारा उसका साक्षात्कार हुआ । जबकि नियमित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार लिखित परीक्षा पास करना, साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना तथा चयन कमेटी द्वारा व्यक्ति का चयन किया जाना आवश्यक होता है । यद्यपि वादी ने प्रति रक्षा के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि इससे विद्यार्थी होने का प्रमाण-पत्र मांगा गया हो तब वह खुद ही नौकरी छोड़कर चला गया हो ।

17. वादी की ओर से एक अन्य व्यक्ति प्रमोद कुमार वर्मा का नियुक्ति पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-5 प्रस्तुत किया गया है जो पार्ट टाईम पास बुक राईटर की नियुक्ति के संबंध में है, इसमें यह उल्लिखित है कि इससे सप्ताह में 12 घंटे काम लिया जायेगा । उपस्थिति रजिस्टर प्रदर्श एम-1 के अनुसार वादी ने भी प्रतिदिन दो घंटे ही कार्य किया है, इस प्रकार उससे भी सप्ताह में 12 घंटे का ही काम लिया गया है। इस प्रकार उसने पार्ट टाईम पास बुक राईटर के अस्थाई पद पर ही कार्य किया है। प्रदर्श डब्ल्यू-2 से यह प्रकट होता है कि उससे नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र मांगा गया था। प्रदर्श डब्ल्यू-2 में वादी ने यह प्रकट किया है कि विद्यार्थी का तात्पर्य नियमित/प्राईवेट तथा एक्स-स्टूडेंट से भी होता है क्योंकि तीनों ही स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। वादी ने प्रदर्श डब्ल्यू-2 में यह प्रकट किया है कि वह एक्स स्टूडेंट है उसने नियमित विद्यार्थी होने का उल्लेख नहीं किया है जबकि उसने अपने आवेदन पत्र में स्वयं को द्वितीय वर्ष बी. कॉम. सी. वाणिज्य का विद्यार्थी होना अंकित किया था इसी आधार पर ही उसे नियुक्ति पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 दिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि नियमानुसार इस पद के लिए विद्यार्थी तथा सेवा निवृत्त व्यक्तियों को ही ऐसी नियुक्ति दी जा सकती है इसका उल्लेख द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.4 में अंकित है।

18. विपक्षी के साक्षी श्री एस. के. जैन ने यह प्रमाणित किया है कि वह जनवरी व फरवरी 1989 में बैंक ऑफ राजस्थान की विश्वकर्मा शाखा में मैनेजर के पद पर नियुक्त था और वर्तमान में भी उसी शाखा में कार्यरत है। उसने यह प्रमाणित किया है कि वादी चन्द्र प्रकाश को पार्ट टाईम पास बुक राईटर के लिए नियुक्ति किया गया था और उसे नियुक्ति पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 दिया गया था जिस पर "ए" टू "बी" हस्ताक्षी प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश के तथा "सी" टू "डी" हस्ताक्षर अपने होना प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने यह भी प्रमाणित किया है कि वादी के कार्य की अवधि 2.45 से 4.45 तक तथा शनिवार को दोपहर 12.15 से 1.45 तक थी। इस साक्षी ने यह भी प्रमाणित किया है कि बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन व प्रबंधकों की राष्ट्रीय ऐसोसियेशन के मध्य प्रथम द्विपक्षीय समझौते के अध्याय 20 के प्रावधान 4 में पार्ट टाईम पास बुक राईटर केवल छात्र अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जा सकता है। उसने कथन किया है कि नियमित छात्र होने का प्रमाण पत्र प्रार्थी ने देने के लिए आश्वासन दिया था किंतु 17-2-89 तक उसने नियमित छात्र का प्रमाणपत्र नहीं दिया जो पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर नियोजित होने की मूल योग्यता थी। इस प्रकार वह विद्यार्थी होने की न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं कर सका। उसके मात्र 9-1-89 से 17-2-89 तक ही कार्य किया, उसके पश्चात् अनुपस्थित हो गया और उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई। इस साक्षी का यह भी कथन है कि अंक तालिका प्रदर्श डब्ल्यू-4 मुकदमें में पेश की गई है उनमें भी एक्स-स्टूडेंट होने का ही उल्लेख है। यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण में अडिग रहा है और सत्यता की कसौटी पर खरा उतरा है। उसका कथन प्रार्थी के कथन से अधिक विश्वसनीय व मजबूत है जो भरोसा किये जाने योग्य है।

19. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी की इस घोषणा के आधार पर ही उसे प्रदर्श एम-1 नियुक्ति पत्र पार्ट टाईम पास बुक राईटर के अस्थाई पद पर दो माह की अवधि के लिए 9-1-89 से 8-3-89 तक की अवधि के लिए दिया गया था, वादी ने प्रदर्श एम-2 में यह डिक्लेरेशन दिया था कि वह द्वितीय वर्ष टी. डी. सी. वाणिज्य का विद्यार्थी है जबकि उससे इस आशय का प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह पेश करने में असफल रहा और उसने केवल 9-1-89 से 17-2-89 तक ही पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर प्रति दिन 2 घंटे काम किया। द्विपक्षीय समझौते की धारा 20.4 के अनुसार पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर किसी छात्र अथवा सेवा नियुक्त व्यक्ति को ही नियोजित किया जा सकता था। वादी नियमित छात्र नहीं था इस कारण भी वह इस पद की न्यूनतम योग्यता/पात्रता नहीं रखता था।

20. वादी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि उसे अनिश्चित काल के लिए क्लर्क के स्थाई रिक्त पद पर रखा गया हो। उसने यह स्वीकार किया है कि न तो उसने कोई लिखित परीक्षा दी न ही उसका साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार नियमित भर्ती के लिए वह पात्रता नहीं रखता था। यह उल्लेखनीय है कि चन्द्र प्रकाश को प्रदर्श एम-2 में किये गये इस डिक्लेरेशन के आधार पर उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था कि वह द्वितीय वर्ष टी.डी.सी. वाणिज्य का विद्यार्थी है और उसने नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाणपत्र पेश करने का आश्वासन दिया किंतु उक्त प्रमाण पत्र मांगने पर वह पेश नहीं कर सका और दिनांक 18-2-89 के बाद वह स्वयं ही काम पर नहीं आया। उसका नियुक्ति पत्र उसी अवस्था में वैध माना जा सकता था जब वह नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र पेश कर देता।

21. अब मैं मामले के तथ्यों और विधि की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह अधिनिर्णित करूंगा कि क्या इस मामले में बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन व प्रबन्धकों की राष्ट्रीय एसोसिएशन के मध्य प्रथम द्विपक्षीय समझौते, शास्त्री अवार्ड एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना हुई है।

22. जैसा कि मैं ऊपर उल्लिखित कर चुका हूं कि द्विपक्षीय समझौते के अनुपात 1 के अनुसार पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर केवल छात्र अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जा सकता है अन्य किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह एक लोक कल्याणकारी योजना विद्यार्थियों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिये ही लागू की गई। कोई भी शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन काल में विद्यार्थी अवश्य रहता है, इसका अभिप्राय यह नहीं निकाला जा सकता कि इस योजना के अन्तर्गत एक्स स्टूडेंट भी फायदा पाने के अधिकारी होने चाहें। प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि विद्यार्थी की श्रेणी में एक्स-स्टूडेंट अथवा प्राइवेट स्टूडेंट भी आते हों। हस्तगत मामले में वादी के स्वयं को नियमित विद्यार्थी पाते हुए पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित फार्म में प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु जब उससे नियमित विद्यार्थी होने के प्रमाण पत्र मांगा गया तो उसने पेश नहीं किया और स्वयं काम पर ही नहीं आया। ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रार्थी की ओर से न्याया-धिकरण के समक्ष भी पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर भी नियुक्त किये जाने की योग्यता पूरी नहीं करता था, अतः उसका विपक्षी बैंक में वैध रूप से नियोजित होना नहीं माना जा सकता। शास्त्री अवार्ड के पैरा 522 व 524 भी इस मामले में आकर्षित नहीं होते हैं, प्रार्थी को जब नियुक्ति ही नहीं दी गई तो उक्त प्रावधान लागू नहीं हो सकते क्यों कि उक्त प्रावधान केवल स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों के लिये ही लागू होते हैं जबकि वादी विपक्षी बैंक का विधिनुसार कर्मचारी ही नहीं था।

23. शास्त्री अवार्ड के पैरा 508 में कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया है किन्तु पार्ट टाईम कर्मचारियों के बारे में कोई निर्देश उन्हें हटाते समय कम्पनसेशन आदि देने के संबंध में नहीं दिये गये हैं। अतः वादी किसी तरह का सुझावजा पाने का भी अधिकार नहीं रखता है। निष्कर्ष यह है कि वादी ने शास्त्री अवार्ड के जिन प्रावधानों का उल्लेख किया है वे इस मामले में आकर्षित ही नहीं होते, और न ही बैंक के प्रबन्धतंत्र द्वारा उसकी अवहेलना किया जाना प्रमाणित हुआ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(00) में छंटनी को परिभाषित किया गया है कि "छंटनी से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा प्रवसान अभि-प्रेरित है"। अधिनियम 1947 की धारा 2(00) को वर्ष 1984 में संशोधित किया जाकर (थीथी) जोड़ा गया है जिसके अनुसार 'termination of the services of workman as a result of non renewal of contract of employment between employer and the workman concerned on its expiry or such contract' अपवाद मात्र होने से छंटनी की परिधि में नहीं आता है। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त 1990(II) एल. एल.जे पेज 70(सुप्रा) पर भरोसा करता हूं। वादी के विद्वान प्रतिनिधि ने जो भी न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं वे 1984 के संशोधन से पूर्व के हैं जो हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। वादी को न तो विधिनुसार नियोजित ही किया गया और न ही उसकी छंटनी की गई है। वादी ने स्वयं को नियमित विद्यार्थी बताते हुए पार्ट टाईम पास बुक राईटर के अस्थाई पद पर नियोजित होना चाहा था किन्तु वह नियमित विद्यार्थी नहीं था न ही उसके इस आशय का प्रमाण पत्र ही पेश किया तथा वह स्वयं ही इसके बाद काम पर नहीं आया। उक्त पद की न्यूनतम पात्रता को प्रार्थी नहीं रखता था। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में म्यूनीसिपल कार्पोरेशन आफ ग्रेटर बाम्बे बनाम डा. सुशील बी. पाटकर (सुप्रा) पर भरोसा करता हूं। उक्त कारणों से प्रबन्धन द्वारा प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश को इस पद हेतु वैध रूप से नियुक्त होना नहीं माना जा सकता अतः उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त होना माना गया है जो मेरी राय में उचित एवं वैध है। प्रबन्धन द्वारा इस प्रकरण में प्रार्थी का छंटनी किया जाना प्रमाणित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अधिनियम 1947 की धारा 25 (जी) व (एच) व औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 77 व 78 आकर्षित नहीं होते क्योंकि उक्त प्रावधान केवल छंटनी किये गये कर्मकारों के संबंध में ही लागू होते हैं। वादी ने जो वरिष्टता सूची प्रस्तुत की है वह नियमित रूप से चयनित किये गये कर्मचारियों की है जब कि प्रार्थी का चयन समिति द्वारा चयन किया जाकर उसे नियुक्ति नहीं दी गई थी, न तो उसने कोई परीक्षा दी और न ही उसका कोई साक्षात्कार हुआ। वादी को डिस्चार्ज /डिसमिस/ टर्मीनेट या रिटरेन्च नहीं किया गया बल्कि नियोजित होने की शर्त पूरी न करने के कारण वह स्वयं ही काम पर नहीं आया।

24. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"दी बैंक आफ राजस्थान लि. जयपुर के प्रबन्धक द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल की सेवायें दिनांक 19-2-89 से समाप्त किया जाना उचित एवं वैध है। श्रमिक किसी राहत व राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।"

25 अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम के भेजी जाये।

शंकर लाल जैन,
न्यायाधीश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

का. आ. 531.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ण) की उपधारा (6) के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 30 जुलाई, 1993 की अधिसूचना संख्या 1748 के तहत दिल्ली जुध योजना के अधीन जुध आपूर्ति उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 29 जुलाई, 1993 से छह माह की कालावधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त अवधि को और छह माह के लिए बढ़ाना अपेक्षित है,

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ण) की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 29 जनवरी, 1994 से छह माह की कालावधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/14/81-डी-I(ए)]
एस. एस. पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th January, 1994

S.O. 531.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 1748 dated the 30th July, 1993 the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 29th July, 1993;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 29th January, 1994.

[No. S-11017/14/81-D.I(A)]
S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1994

का. आ. 532.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि कोल उद्योग को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 4 में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017(13)/81-डी-आई. आर. (पालिसी)]
एस. एस. पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th January, 1994

S.O. 532.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Coal Industry which is covered by item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/13/81-I.R.(Policy)]
S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

का. आ. 533.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-94 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-40011/12/90-आई. आर. (डी. यू.) (पीटी)]
के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th January, 1994

S.O. 533.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mahanagar Telephone Nigam Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on 24-1-94.

[No. L-40011/12/90-IR(DU)(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I. BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar,
Presiding Officer

Reference No. CGIT-12 of 1994

PARTIES :

Employers in relation to the management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd., Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management.—Shri Kotiankar, Advocate.

For the Workmen.—No appearance.

INDUSTRY : Telephones STATE : Maharashtra.

Bombay, the 12th day of January, 1994

AWARD

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by letter dated 4-2-1991, made following reference to this Tribunal.

"Whether the management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd., Bombay is justified in,—

(a) Suspension of S|Sh. Sunabarse H. F., Divisional Secretary, P. B. Kaneshkar, Treasurer, A. G. Puri, Vice-President, S. N. Chabria, member of Bhartiya Telecommunication Technicians Union, Bombay and

(b) Ordering transfer of 39 workmen contained in the ordrs No. ST|49-3|TR-X|4, 8 & 18 dated 8-9-88, 4-10-88 ?

If not, to what relief the concerned workmen are entitled to ?"

2. Statement of claim has been filed on behalf of the union. It appears from the statement of claim that the employees of M.T.N.L. had started some agitation to get their grievances redressed. 39 officials came to be transferred and four of them came to be suspended. Justification for the orders of transfer and suspension is the point in issue in this reference. It is not necessary to refer to the statement in detail, suffice it to say that the contention is that the transfer and suspension orders are smacking of malafide and therefore, not justified. The prayer, therefore is transferred officials should be brought back to their original place and particular criteria for transfer as be framed and directions issued. So far as the suspension is concerned it is also challenged on the very ground and rules with regard to finalisation of proceedings against suspended employees are quoted and it is pointed out that they have been violated. Cancellation of suspension orders is therefore prayed for.

3. On behalf of the management written statement has been filed mentioning the circumstances under which the management had to issue orders on administrative ground. It is alleged that the union has suppressed certain facts from this Tribunal and they were about proceedings pending in this Tribunal. It is further stated that the transfer orders as well as suspension orders were then justified. It is stated that the suspension orders have been revoked and the orders of transfer issued have been reviewed and 24 technicians have been shifted to new places. That was done persuant to direction of Central Administrative Tribunal. It is then prayed that the reference be answered aganst BTTU.

4. Statement of claim has been filed on behalf of the union, it appears that they are not taking any further part in proceedings. After I took over as the Presiding Officer of the Tribunal and the matter came up before me on 2-6-1993, I directed to issue notice to the union and since there was no appearance on behalf of the union on 11-8-1993, 24-9-1993, 19-11-1993 the matter was thereafter heard and Shri Kohankar Advocate represented M.T.N.L. It appears to me that the union is no more interested in getting dispute adjudicated. At any rate the grievance that the transfer and suspension orders have been issued malafide is not seen from the materials on record. It is not disputed on administrative grounds transfers could be effected. However, if the orders smack of malafide intention on amount to punishment then surely this Tribunal could examine it and hold that they were unjustified. However, for that material has to be brought on record and in the absence of that it is not possible to hold in favour of the union on that issue. As stated earlier. I find that no material has been placed on record to substantiate this plea.

5. Some Judgments have been placed on record and on the basis of those Judgments also it is not possible to hold that the action of the management was malafide or motivated. The Central Administrative Tribunal, Madras Bench held in the matter between P. Fulgthan & others Vs. Secret Ministry of Communications and others by order dated 23-1-1989 that no case was made out for interfering with the orders of transfer which were challenged & the application accordingly was dismissed. Similar contentions were raised on behalf of the applicant as have been raised here as against the mnagement of Telecommunications by the Technicians. Technical Supervisors. All of them were evamined in the light of arguments advanced and decision was rendered against the workman. I therefore, find that there is no merit in the contention that the order of transfer were malafide and therefore unjustified.

6. Similar is the position with regard to the orders of suspension. They were issued pending departmental enquiries and it is needless to say that suspension pending enquiry is permisible and justified. Once again it is to be pointed out that there is no material to hold that either the suspension pending enquiry or the enquiry itself was not justified.

7. It must be said at the end that the suspension orders were revoked. The transfer orders were reviewed as per direction of the Tribunal and 24 of them were altered after review. That appears to have satisfied the workmen and the union and therefore, their non-appearance in the present proceedings. In the end, I hold that the action of the management is not shown to be unjustified and award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

का. आ. 534.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीट्रोकाम फैक्ट्री बम्बई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-1-94 को प्राप्त हुआ था ।

[एल-40011/11/88-डी. 2(बी) (पार्ट)]
के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th January, 1994

S.O. 534.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Factory Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on 24-1-94.

[No. L-40011/11/88-D.II(B)(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar,
Presiding Officer

Reference No. CGIT-49 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Telecom Factory, Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management.—Mr. Masurkar, Advocate.
For the Workmen.—No appearance.

INDUSTRY : Telecommunication STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 14th day of December, 1993

AWARD

The following industrial dispute has been referred to this Tribunal for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Telecom Factory Bombay in terminating the services of 39 casual mazdoors as per the list enclosed is justified ? If not, to what relief these casual mazdoors are entitled to ?"

2. This is a reference made by the Ministry of Labour, Government of India, in respect of the dispute between the Telecom Factory, Bombay and the Casual Mazdoors appointed by it. The point that arose for adjudication is, whether the termination of the 39 casual mazdoors is justified ? and if not, what relief they, or any one of them are entitled to ?

3. Statement of claim has been filed by the All India Post and Telegraph Industrial Workers' Union The contention raised therein is that except the 3 workers, namely Mr. Savarkar, Gungal, and Mr. Sawant, the remining 36 workers

have not completed 240 days of continuous service and therefore, these 36 workers will be dealt with under the provisions of the Model Standing Order (Central) framed under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946. The contention therefore, is that, the termination in either case was illegal, and in breach of Sections 25F and 25N of the Act, and those of the Model Standing Orders (C). inasmuch as the provisions have of those sections have not been followed.

4. Resisting this, the management filed its written statement. It is denied that all were engaged & those at Sr. Nos. 1 to 7, 12, 13, 16 to 18, 2], 28 to 31, 33 to 39 were never employed. It is contended therein by the management that they were engaged as casual labourers for a specific period for carrying out a specific job. They were engaged out of the candidates sent by the Regional Employment Exchange, on the management's request. The job was over, and therefore, they were no longer required by the management. The management further contended that none of them have completed 240 days.

5. On the date of hearing, there is no appearance on behalf of the Union. There is also no material adduced on record to show that they have put in 240 days of continuous service in 12 calander months immediately preceding the date of termination. If this is not done, then they cannot be deemed to be in continuous service for a period of one years, within the meaning of Section 25B of the Act. In that event, they cannot claim benefit of Section 25F of the Act and contend that termination is in breach of section 25 of the Act and contend that termination is in breach of section 25F of the Act. So far as the remaining 36 workers are concerned, admittedly they have not completed 240 days of continuous service and therefore, they are not entitled to be protection under this section.

6. With regard to the rest, it has been urged on behalf of the management, that under Section 27(2) of the Certified Standing Orders (Central) applicable in this case no notice is required for termination of services of the casual labourers, who have put in less than one years continuous service.

7. There is no material to show that they have put in continuous service for one year, and that they were entitled to one month's notice in writing. Besides clause (2) says that notice is not necessary for terminating the services of workmen with less than one year's approved service or a Casual Labourer. The case of the present workmen is not of termination prior to the implementation of the Certified Standing Orders. In view of this, none of them are entitled for any relief on the ground that the termination was illegal.

8. It is also not possible to accept the contention of the workmen that the management has indulged in unfair labour practice. It is clearly mentioned that they have been employed for a specific period for a specific job and that there is no evidence in rebuttal.

9. In the circumstances, Award is accordingly made and reference is disposed off.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

का. आ. 535.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. डी. ओ फोन्स-I जोधपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण कोटा के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

[सं. एस.—40012/103/89-डी. 2(बी) (पार्ट)]
के. बी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st February, 1994

S.O. 535.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.D.O Phones-I Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government.

[No. L-40012/103/89-D.II(B)(Pt)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer.

अनुबन्ध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा/राज.

निर्देश प्रकरण क्रमांक : ओ.ग्या. (केन्द्रीय)-6/1990

दिनांक स्थापित : 3-2-90

प्रसंग: भारत सरकार श्रम मंत्रालय, के आदेश क्रमांक एम40012/103/89—डी-2 (बी) दिनांक 30-1-90

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री यादवराम शर्मा,
मकान नं. 104, बाम्बे लाज के सामने,
जसवन्त सराय के पास, जोधपुर।

—प्रार्थी श्रमिक

एवं

सब डिविजनल आफिसर फोन्स (जोधपुर)

—प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री जगदीश नारायण शर्मा,

(आर.एच.जे.एस.)

प्रार्थी श्रमिक की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रतिपक्षी नियाजक की ओर से श्री हजारी लाल गुप्ता
प्रतिनिधि :
अधिनिर्णय दिनांक : 5 जुलाई, 1993

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा निम्न निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(घ) के अंतर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :

"Whether the section of the S.D.O. Phone-I Jodhpur in terminating the services of Sh. Narendra Kumar Sharma S/o Sh. Yadav Ram Sharma daily rated labour w.e.f. 1.11.84. in just & legal ? If not to that relief is the worker concerned entitled" ?

2. निर्देश न्यायाधिकरण के प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व पक्षकारों को सूचना भिजवाई गयी, तदुपरान्त दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी उपस्थित न्यायाधिकरण में दी गई ।

3. इस प्रकरण में आज प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि स्वरुप श्री हजारीलाल गुप्ता उपस्थित हुए । यह निर्देश इस न्यायाधिकरण में दिनांक 3/2/90 से लम्बित है तथा 31/12/90 को श्रमिक की ओर से श्री शिवसहाय शर्मा ने उपस्थित होकर क्लेम हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया था। इसके उपरान्त से आज तक श्रमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रमिक पक्ष को इस विवाद में कोई दिलचस्पी

नहीं रही है। अतः इन परिस्थितियों में इस प्रकरण में "विवाद रहित अधिनिर्णय" पारित किया जाता है।

इस अधिनिर्णय की भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये।

जगदीश नारायण शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

का.आ. 536 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 20 जून, 1992 को भारत के राजपत्र, भाग-II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के दिनांक 28 मई, 1992 के का०आ० सं० 1657 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उपरोक्त अधिसूचना के भाग–I में, "सलाहकार समिति" शीर्षक के नीचे, क्रम संख्या 20 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी अर्थात् :—

"20. कु. एन्नी प्रसाद
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002"

[सं. एस.-42025/49/84–सीएंडडब्ल्यूएल(ii)]
शशी जैन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 1st February, 1994

S.O. 536.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 1657, dated 28th May, 1992 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) on the 20th June, 1992, namely :—

In the said notification, in Part I, under the heading "Advisory Committee" after serial number 20 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be added, namely :—

"21. Ms. Annie Prasad,
Member-Secretary,
National Commission for Women,
4, Deen Dayal Upadhyay Marg,
New Delhi.

[No. S-42025/49/84-C&WL-II]
SMT. SHASHI JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994